https://informatics.nic.in

वॉल्यूम 34, सं. 2, अक्टूबर, 2025

ISSN 0971-3409

इन्फॉर्मेटिक्स

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की एक ई-शासन प्रकाशन

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Digital India
Power To Empower

MeitY
Government of India

NIC
एनआईसी
National Informatics Centre

पहला पूर्ण हिन्दी संस्करण

साइबर सुरक्षा

प्रौद्योगिकी अद्यतन लेख

नशा मुक्ति रजिस्ट्री पोर्टल 22

जिज्ञासा 24

ओड़िशा आपदा संसाधन नेटवर्क 26

पैमाना पोर्टल 28

अनुमति प्रबंधन प्रणाली 30

32 शासन में साइबर सुरक्षा व गोपनीयता

36 आधुनिक समय की साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ

एनआईसी
NIC

इन्फॉर्मेटिक्स

वॉल्यूम 34 संख्या- 2, अक्टूबर 2025

संरक्षक
अभिषेक सिंह, आईएएस

सलाहकार मंडल
अजय सिंह चहल
सुचित्रा प्यारेलाल
सी. जे. एन्टनी
मनी खनेजा
आलोक तिवारी

प्रधान संपादक
मोहन दास विस्वम्

क्षेत्रीय संपादक
सुषमा मिश्रा
निस्सी जॉर्ज
विनोद कुमार गर्ग

सामग्री सहयोग
अर्चना शर्मा
हेमेंद्र कुमार सैनी

डिज़ाइन सहयोग
मुकेश भारती
रोहित कुमार मौर्या

वेब एवं ई-बुक
सुनील कुमार
अमित कुमार लोधी
मो. पिंटू

भाषा अनुवाद सहयोग
अंकित कुमार
वैशाख नायर

प्रिंट एवं समन्वय
यू.एक्स.डी.टी. विभाग

प्रकाशक
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी
मंत्रालय, भारत सरकार

संपर्क पता
इन्फॉर्मेटिक्स
379, ए4बी4, तृतीय तल, एनआईसी
ए-ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
नई दिल्ली-110003, भारत
फोन: 011-24305363/ 65
ईमेल: editor.info@nic.in

संपादकीय

एक ऐसे युग में, जहाँ प्रौद्योगिकी हमारे संवाद करने, सीखने और काम करने के तरीके को आकार दे रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर इसका प्रभाव अकाट्य हो गया है। नवाचार और नागरिक जीवन के इस संगम पर, जहाँ भागीदारी को व्यापक बनाने के विशाल अवसर हैं, वहीं सावधानीपूर्वक चिंतन की माँग करने वाली चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। जब दूरदर्शिता और जिम्मेदारी से निर्देशित किया जाता है, तो प्रौद्योगिकी समावेश और राष्ट्रीय विकास में एक सहभागी बन जाती है।

आज की डिजिटल प्रणालियाँ लोकतंत्र के स्तंभों—पारदर्शिता, जवाबदेही, और सार्वजनिक भागीदारी—को मज़बूती प्रदान करती हैं। नागरिक वास्तविक समय में चर्चाओं में शामिल हो सकते हैं, अपने विचारों को व्यापक रूप से साझा कर सकते हैं, और शासन के मामलों पर पहले से कहीं अधिक करीब से नजर रख सकते हैं। जानकारी तक आसान पहुँच व्यक्तियों को सूचित विकल्प बनाने और सार्वजनिक मुद्दों में अधिक सार्थक तरीके से जुड़ने के लिए सशक्त बनाती है।

जैसे-जैसे डिजिटल सेवाएँ बढ़ रही हैं, शासन स्वयं परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण, और नागरिक बातचीत के लिए आधुनिक उपकरण सार्वजनिक प्रणालियों को अधिक उत्तरदायी और कुशल बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। ये समाधान देरी को कम करते हैं, मनमाने विवेक पर रोक लगाते हैं, और प्रशासन को लोगों के निकट लाते हैं।

फिर भी, इन प्रगतियों के साथ नई चुनौतियाँ भी आती हैं। गलत सूचना, साइबर जोखिम, और असमान डिजिटल पहुँच उस विश्वास के लिए ख़तरा पैदा करते हैं जो नागरिकों को संस्थानों से जोड़ता है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि व्यक्तिगत डेटा को जिम्मेदारी से और व्यक्तिगत गरिमा के प्रति सम्मान के साथ संभाला जाना चाहिए। यह स्पष्ट संचार, सुरक्षित डेटा प्रबंधन, और ऐसे तंत्रों को बढ़ावा देता है जो नागरिकों को उनकी जानकारी पर अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं। हालाँकि यह कोई संपूर्ण समाधान नहीं है, लेकिन यह डिजिटल क्षेत्र में सार्वजनिक विश्वास को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी सभी को लाभ पहुँचाए, एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी हुई है। व्यापक कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता, और समावेशी डिज़ाइन के माध्यम से डिजिटल विभाजन को पाटना सार्थक भागीदारी के लिए अनिवार्य है। हर नागरिक, उसके भूगोल या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, डिजिटल सेवाओं तक पहुँचने और ऑनलाइन अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम होना चाहिए।

उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे सूचना पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास को पोषित करना। मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना, तथ्य-जाँच (फ़ैक्ट-चेकिंग) पहल का समर्थन करना, और प्लेटफ़ॉर्म की जिम्मेदारी को मज़बूत करना सार्वजनिक संवाद को विकृति से बचाने में मदद कर सकता है।

इस यात्रा के मूल में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा निहित है। चूँकि संस्थान व्यक्तिगत जानकारी की बढ़ती मात्रा एकत्र करते हैं, इसलिए मज़बूत सुरक्षा उपाय और जिम्मेदार डेटा प्रथाएँ आवश्यक हैं—न केवल कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बल्कि उस विश्वास को कायम रखने के लिए भी जो नागरिक सार्वजनिक प्रणालियों में रखते हैं।

डी.पी.डी.पी. अधिनियम का लक्ष्य एक ऐसे डिजिटल भविष्य का निर्माण करना है जो न केवल कुशल हो, बल्कि अडिग सत्यनिष्ठा पर भी आधारित हो। इन्फॉर्मेटिक्स के इस अंक में शासन में साइबर सुरक्षा और गोपनीयता पर एक अंतर्दृष्टिपूर्ण लेख शामिल है, जो पाठकों को रक्षात्मक सुरक्षा उपायों और सक्रिय डेटा संरक्षण रणनीतियों के अभिसरण से परिचित कराता है। आइए, हम सभी इस जिम्मेदारी को अपनाएँ और वैश्विक स्तर पर डिजिटल शासन के लिए एक मानदंड स्थापित करें।

हमें अत्यंत हर्ष है कि इन्फॉर्मेटिक्स का यह पहला, पूर्ण-हिंदी संस्करण—पूरी तरह इन-हाउस तैयार—आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का श्रेय हम महानिदेशक (एनआईसी) की सक्रिय रुचि और निरंतर प्रोत्साहन को देते हैं।

हम आशा करते हैं कि आपको यह अंक उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगेगा।

- प्रधान संपादक

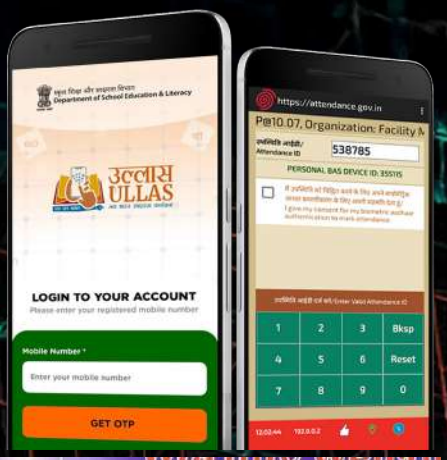

विषय सूची

संपादकीय 02

विषय वस्तु 03

राज्यों से

असम 04

छत्तीसगढ़ 10

जिलों से

अहिल्यानगर, महाराष्ट्र 16

जामताड़ा, झारखंड 18

टोंक, राजस्थान 20

ई-गवर्नेंस उत्पाद एवं सेवाएँ

नशा मुक्ति रजिस्ट्री पोर्टल 22

जिज्ञासा 24

ओडिशा आपदा संसाधन नेटवर्क 26

पैमाना पोर्टल 28

अनुमति प्रबंधन प्रणाली 30

प्रोद्योगिकी अद्यतन

शासन में साइबर सुरक्षा व गोपनीयता 32

आधुनिक समय की साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ 36

ऐपस्केप 38

अंतर्राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस उत्पाद 40

समाचारों में 42

पुरस्कार 48

अस्वीकरण

इस प्रकाशन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं, और ये संपादकों या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। साथ ही, लेखों में दिए गए तथ्यों एवं सूचनाओं की सटीकता की ज़िम्मेदारी लेखकों पर ही होगी।

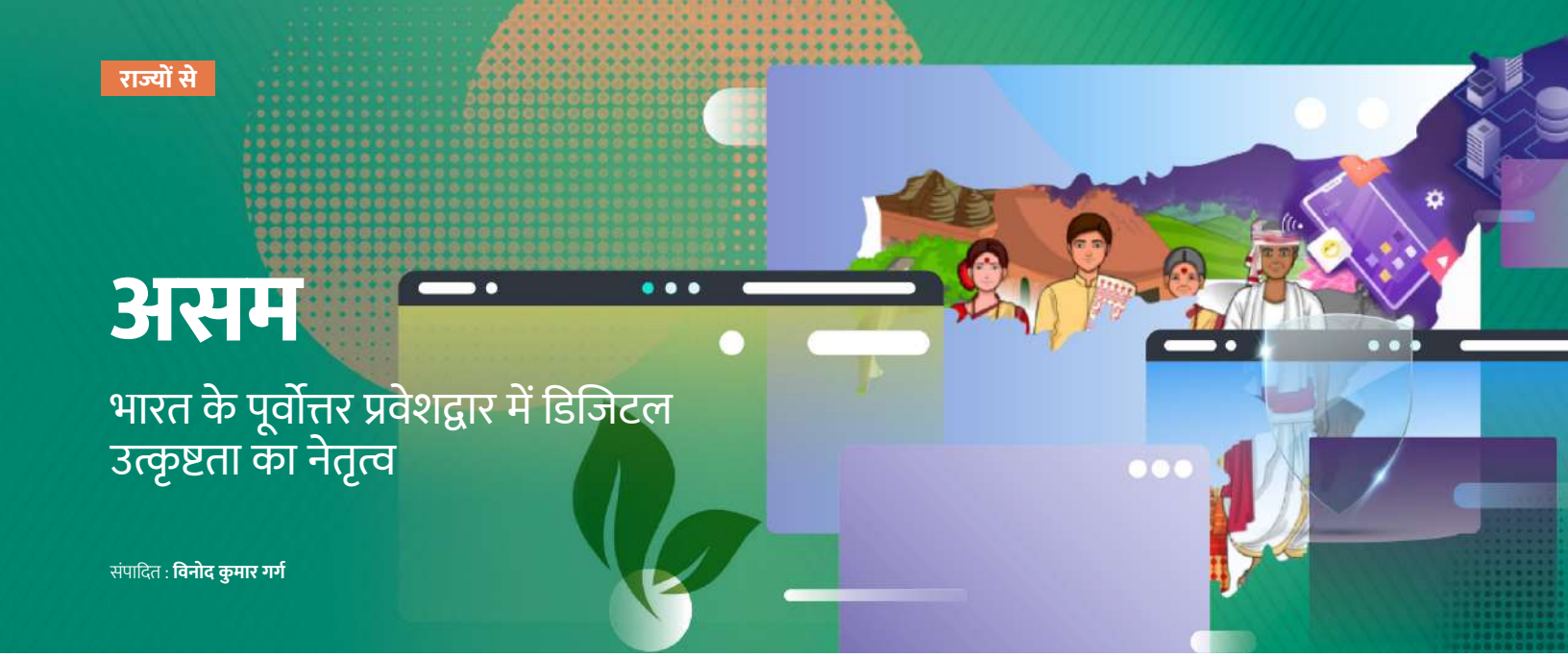

असम

भारत के पूर्वोत्तर प्रवेशद्वार में डिजिटल उत्कृष्टता का नेतृत्व

संपादित : **विनोद कुमार गर्ग**

असम, जीवंत पूर्वोत्तर राज्य, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अपनी चाय, एक सींग वाले गैंडे और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के लिए जाना जाता है, देश में डिजिटल परिवर्तन में अग्रणी बनकर उभरा है। राज्य ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति कर रहा है, और प्रशासन के सभी स्तरों पर बेहतर शासन प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग कर रहा है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) सरकार का सबसे विश्वसनीय और प्रमुख प्रौद्योगिकी भागीदार रहा है, जो प्रशासनिक दक्षता को मज़बूत करने और सरकार-से-नागरिक (जी2सी) सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए संपूर्ण डिजिटल समाधानों को सशक्त बनाता है। एनआईसी असम राज्य केंद्र ने 1986 से कार्य करना शुरू किया, और नब्बे के दशक के मध्य तक, राज्य के प्रत्येक जिले में एनआईसी की एक जिला इकाई थी। इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक के उत्तरार्ध में ऑनलाइन तकनीकों के आगमन ने असम और एनआईसी को इस स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया।

राज्य सरकार ने अपने विज़न में डिजिटल नवाचारों को सक्रिय रूप से अपनाया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रौद्योगिकी-संचालित शासन असम के हर कोने तक, शहरी केंद्रों से लेकर दूरदराज के गाँवों तक पहुँचे। इस विज़न को साकार करने के लिए एनआईसी ने कदम बढ़ाया। डिजिटल इंडिया के विज़न के साथ अपनी प्रगति को संरेखित करते हुए, असम और एनआईसी ने ई-गवर्नेंस समाधानों, संपर्क रहित नागरिक सेवाओं, डेटा-संचालित

रुबाइयात उल अली
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एसआईओ
rubaiyat@nic.in

मैत्रेयी सरमा
वैज्ञानिक - बी व एसएमसी
maitreyee.sarma@nic.in

असम भारत में डिजिटल नवाचार में सबसे आगे है, और एक अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक-हितैषी सरकार बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है। 1986 से मिलकर काम करते हुए, एनआईसी असम राज्य केंद्र और राज्य सरकार ने विविध आईसीटी पहलों के साथ एक व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है, जिसने लाखों नागरिकों के जीवन को बदल दिया है।

डैशबोर्ड से लेकर अगली पीढ़ी के बुनियादी ढाँचे और स्वचालन तक, विभिन्न सरकारी विभागों में व्यापक डिजिटल पहलों को लागू करने के लिए हाथ से हाथ मिलाया। एनआईसी असम ने स्केलेबल आईटी समाधान विकसित करने, मज़बूत डिजिटल बुनियादी ढाँचा स्थापित करने और राज्य की डिजिटल यात्रा का समर्थन करने वाली तकनीकी रीढ़ के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए नवीन अनुप्रयोगों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

असम के डिजिटल परिवर्तन में एनआईसी की भागीदारी का पैमाना वास्तव में महत्वपूर्ण है। असम की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पहलों का एक बड़ा हिस्सा एनआईसी द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया जाता है। इनमें 29 राज्य-विशिष्ट परियोजनाएँ, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप 12 राष्ट्रीय परियोजनाएँ, और सेवाओं एवं सुरक्षा ढाँचों सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की स्थापना शामिल है।

राज्य में आईसीटी पहलें

पंचायत मतदाता सूची और चुनावों का डिजिटलीकरण

लोकतंत्र की नींव पारदर्शी और कुशल चुनावी प्रक्रियाओं में निहित है। हालाँकि, यह नींव पुरानी और बोझिल मैनुअल प्रणालियों की अस्थिर नींव पर खड़ी थी। ऑनलाइन मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली (ओ. ई. आर. एम. एस.), चुनाव प्रबंधन और निगरानी प्रणाली, और मतदान कार्मिक प्रबंधन प्रणाली (पी. पी. एम. एस.) ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है। इसने संपूर्ण मतदाता सूची तैयार करने और मतदान प्रबंधन प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। इस प्रणाली ने 2,192 गाँव पंचायतों और 25,046 मतदान केंद्रों को कवर किया है, जिनमें 18,091,705 मतदाता नामांकित हैं। चुनावों के दौरान, इस प्लेटफ़ॉर्म ने आंचलिक पंचायत और जिला परिषद पदों के लिए 7,174 नामांकन संसाधित किए, 6,610 स्वीकार किए, 179 अस्वीकृत किए और 385 नाम वापस लिए। इस सरकार-से-सरकार (जी 2 जी) पहल ने असम में जमीनी स्तर के लोकतंत्र में पारदर्शिता और दक्षता लाई है।

सीएम डैशबोर्ड

सीएम डैशबोर्ड राज्य के शीर्ष नेतृत्व के लिए सरकारी प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन हेतु एक अभिनव दृष्टिकोण है। यह अनूठा एपीआई-आधारित प्लेटफ़ॉर्म ज़िलों की वास्तविक समय, डेटा-आधारित निगरानी और प्रदर्शन मूल्यांकन को सक्षम बनाता है, गतिशील, स्वचालित डेटा संग्रह के माध्यम से वास्तविक आंकड़ों के साथ सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ज़िलों को पारदर्शी रूप से प्रदर्शित करता है।

यह डैशबोर्ड 43 केंद्रीय योजनाओं, 37 राज्य योजनाओं और 1 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना की निगरानी करता है, जिसमें 17 संग्रहीत योजनाओं के साथ 38 परियोजनाएँ शामिल हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्यान्वयन प्रगति पर नज़र रखने और वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर सूचित निर्णय लेने का एक अनिवार्य उपकरण है।

सेवा सेतु

सेवा सेतु असम के प्रमुख नागरिक सेवा मंच के रूप में प्रतिष्ठित है, जो 20 से अधिक पोर्टलों और उमंग, आधार, ई-प्रमाण और

डिजिलॉकर सहित 10 राष्ट्रीय प्लेटफार्मों को एकीकृत करके अभूतपूर्व 815 सेवाएँ प्रदान करता है। इस सरकार-से-नागरिक (जी 2 सी) मंच ने 1.94 करोड़ आवेदनों का प्रसंस्करण किया है, जिनमें से 1.75 करोड़ आवेदनों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है।

इस मंच में एक एकीकृत अपील और शिकायत प्रबंधन प्रणाली शामिल है और यह कुशल बैक-एंड वर्कफ़्लो प्रबंधन के लिए एक इन-हाउस सेवा फ़्लोमास्टर का लाभ उठाता है। सुगम्यता के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए, सेवा सेतु डब्ल्यूसीएजी और जीआईजीडब्ल्यू 3.0 मानकों का अनुपालन करता है, जिसमें यूएक्स4जी द्वारा डिज़ाइन किया गया सुगम्यता मेनू शामिल है। इस मंच की तकनीकी संरचना मापनीयता के लिए माइक्रोसर्विसेस और सुरक्षित निरंतर एकीकरण और परिनियोजन के लिए डेवसेकऑप्स का लाभ उठाती है, जो इसे नागरिक-केंद्रित डिजिटल शासन के लिए एक आदर्श बनाती है।।

ई.ओ.डी.बी.

व्यापार सुगमता मंच ने असम को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डी.पी.आई.आई.टी) की ई.ओ.डी.बी. रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान दिलाया है। यह एकीकृत जी2सी मंच 21 विभागों और 42 उप-विभागों में 300 से अधिक ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करता है - 273 अंत-से-अंत और 27 बाहरी सेवाएँ।

इस मंच ने 26.65 लाख सेवाएँ प्रदान की हैं जिनकी निपटान दर 98.28% है। इस प्रणाली ने 3.4 लाख सामान्य आवेदन पत्र पंजीकृत किए हैं और 27.12 लाख आवेदनों का प्रसंस्करण किया है, जिससे व्यावसायिक अनुमोदन और मंज़ूरी प्राप्त करने में लगने वाले समय और जटिलता में उल्लेखनीय कमी आई है।

ई-प्रस्तुति

असम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने ई-प्रस्तुति के माध्यम से सरकारी वेबसाइटों के लिए एक मानकीकृत वेबसाइट ढाँचा लागू किया है। इस पहल ने सरकार की वेब उपस्थिति को मानकीकृत किया है, जिससे सभी आधिकारिक वेबसाइटों पर डिज़ाइन, पहुँच संबंधी सुविधाओं और सूचना संरचना में एकरूपता सुनिश्चित हुई है, जिससे सरकारी जानकारी अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो गई है। ई-प्रस्तुति 299 वेबसाइटों को कवर करती है, जिनमें विभागों, जिलों, राज्य पोर्टल और राज्यपाल पोर्टल की वेबसाइटें शामिल हैं।

ई-मंत्री सभा

ई-मंत्री सभा ने प्रस्ताव प्रस्तुत करने से लेकर निर्णयों की ट्रैकिंग और कार्यान्वयन तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर असम में कैबिनेट शासन को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे कैबिनेट बैठकें 100% कागज़ रहित हो गई हैं।

यह प्रणाली डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी एस सी), ई-परिचय और आधार प्रमाणीकरण को सहजता से एकीकृत करती है, और भारत वी सी एकीकरण भी जारी है। कार्यान्वयन के बाद से, इस प्लेटफ़ॉर्म ने 181 बैठकों का संचालन किया है, 3,497 निर्णयों को रिकॉर्ड किया है, जिनमें संग्रहीत कैबिनेट निर्णय भी शामिल हैं, जिससे राज्य कैबिनेट की दक्षता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

मुख्यमंत्री का आत्मनिर्भर असोम अभियान

उद्यमिता के माध्यम से बेरोज़गारी की समस्या का समाधान करते हुए, मुख्यमंत्री का आत्मनिर्भर असोम अभियान युवाओं को स्व-रोज़गार के अवसरों से सशक्त बनाने और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस जी 2 सी पहल के तहत 2,29,145 व्यक्तियों का पंजीकरण हुआ है, 1,04,091 आवेदन प्राप्त हुए हैं, और 25,000 से अधिक व्यक्तियों को अपना उद्यम शुरू करने में सहायता मिली है।

एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली (आई.एल.आर.एम.एस.)

भूमि अभिलेख, संपत्ति अधिकारों और कृषि प्रशासन का आधार हैं। आई.एल.आर.एम.एस. ने भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रक्रियाओं को एकीकृत अनुप्रयोगों के एक व्यापक समूह के साथ डिजिटल कर दिया है, जिसमें बसुंधरा, धरित्री, भू-अभिलेख, ई-खजाना, चिट्ठा, स्वामित्व, लैंडहब, एन.जी.डी.आर.एस., सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण और आर.सी.सी.एम.एस. शामिल हैं। नागरिकों को ऑनलाइन जी 2 सी सेवाएँ सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

निर्माण सखी

निर्माण सखी निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाती है। यह दावों (क्लेम) की पारदर्शी प्रक्रिया, सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) द्वारा भुगतान, मानक के अनुसार सेस आकलन, और श्रमिक कल्याण सेवाओं को सरल तरीके से प्रदान करती है। यह असम के निर्माण श्रमिकों के लिए श्रम विभाग के तहत काम करती है।

आधार वॉल्ट से जुड़ने वाला यह पहला आवेदन है। अभी तक इसके तहत कुल 1,35,387 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 96,471 पंजीकरण (ऑनबोर्डिंग) आवेदन और 38,916 नए आवेदन शामिल हैं।

▼ चित्र 1.1 : ई.ओ.डी.बी. वेबसाइट होमपेज

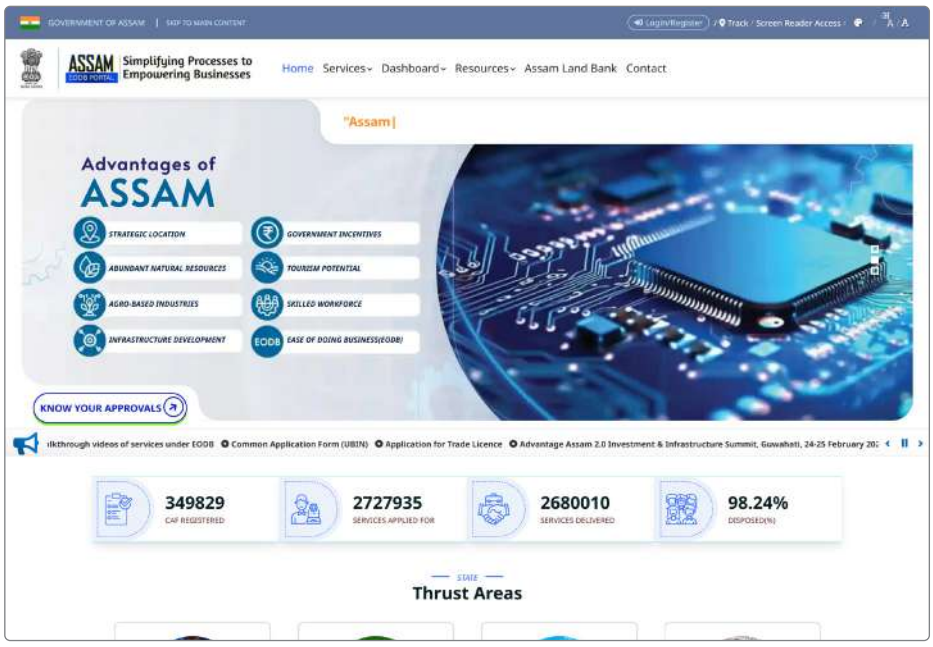

ऐसा माना जाता था कि असम में इस तरह का काम नहीं हो सकता। हमने धीरे-धीरे शुरुआत की है। परिवहन विभाग की (संपर्क रहित) सेवाओं से सात लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। लेकिन परिवहन में यह संख्या बढ़ती ही जाएगी और 2026 तक इस पूरी प्रक्रिया से लगभग एक करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। असम में रैंडमाइजेशन (उनके द्वारा विकसित सीएम-ट्रांस एप्लिकेशन का संदर्भ देते हुए) देश में पहला है। अगर कोई इसे अभी करना चाहता है, तो वह असम मॉडल होगा। इस काम के परिणामस्वरूप, हम भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। एनआईसी असम ने हमारे लिए यह कार्यक्रम किया है। उन्होंने इसे पहली बार किया है और एनआईसी असम हमारे अनुरोधों का जवाब देने में वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं एनआईसी टीम के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने हम सभी के लिए ये सभी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी एनआईसी की तारीफ़ करें क्योंकि उनकी वजह से ही हम कई उपलब्धियाँ हासिल कर पाए हैं। हमें इन सॉफ़्टवेयर के लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, न ही कोई बिल, अनुबंध या टेंडर है, हम बस इसे लागू कर रहे हैं क्योंकि एनआईसी हमारी मदद के लिए है और हम यह कर रहे हैं।

श्री हिमंता बिस्वा सरमा
असम के माननीय मुख्यमंत्री
(असम में संपर्क रहित परिवहन सेवाओं के उद्घाटन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री के भाषण का अंश)

एनआईसी असम राज्य की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है, जिसके दौरान असम के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कई राज्य-विशिष्ट और राष्ट्रीय परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

एनआईसी के स्केलेबल आईटी समाधानों ने व्यापक डैशबोर्ड और अन्य ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क रहित सेवाओं और डेटा-संचालित शासन को सक्षम बनाया है। 41 सक्रिय जी2सी, जी2ई और जी2बी अत्याधुनिक परियोजनाओं और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं—जिनमें निकनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनकेएन शामिल हैं—के साथ एनआईसी ने खुद को असम में एक प्रमुख आईसीटी स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। एनआईसी द्वारा विकसित गतिशील सीएम डैशबोर्ड का डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। निदेशालयों में ई-ऑफिस को अपनाने से सरकारी फ़ाइल प्रसंस्करण में बदलाव आया है, जबकि सेवा सेतु और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (ई.ओ.डी.बी.) जैसे सेवा पोर्टलों ने नागरिकों को बहुत लाभान्वित किया है। असम को ई-परिवहन को लागू करने में एक अग्रणी राज्य के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, जो इस महत्वपूर्ण राजस्व-अर्जन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है।

हर ज़िले में एनआईसी केंद्रों के साथ, डिजिटल सेवाएँ अब दूर-दराज़ के गाँवों तक पहुँच रही हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी नागरिक पीछे न छूटे। एनआईसी की साझेदारी ने असम को डिजिटल परिवर्तन में अग्रणी बनाने में मदद की है। राज्य सरकार और एनआईसी ने एक बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए डिजिटल तकनीकों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मिलकर काम किया है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक डिजिटल रूप से सशक्त असम बनाने के लिए निरंतर सहयोग की आशा करते हैं।

डॉ. रवि कोटा, आईएएस
मुख्य सचिव, असम

असम ई-ग्रास

सरकारी रसीद लेखा प्रणाली (ई-ग्रास) नागरिकों और विभागों को असम सरकार की सेवाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान करने में सक्षम बनाती है, जिससे ई-चालान निर्माण, बहु-शीर्ष भुगतान और कोषागार एवं गैर-कोषागार दोनों शीर्षों के लिए रसीद लेखांकन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। इस जी 2 जी/जी 2 सी प्लेटफ़ॉर्म ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,05,69,390 ई-चालान उत्पन्न किए हैं, जिनसे कुल ₹84,446.97 करोड़ का संग्रह हुआ है।

डिजिटल आईटीआई प्लेटफ़ॉर्म

यह मानते हुए कि कुशल कार्यबल का विकास आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, डिजिटल आईटीआई प्लेटफ़ॉर्म औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए एक एकीकृत डिजिटल सुइट का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्लेटफ़ॉर्म में तीन एकीकृत घटक हैं: एक एमआईएस पोर्टल जो वास्तविक समय में शिक्षाविदों, छात्रों और प्रशासन पर नज़र रखता है; एक संबद्धता पोर्टल जो आईटीआई अनुमोदन और अनुपालन प्रक्रिया को डिजिटल बनाता है; और एक ई-परामर्श पोर्टल जो निष्पक्ष, कागज़ रहित, योग्यता-आधारित आईटीआई प्रवेश को सक्षम बनाता है।

कृतज्ञता

कृतज्ञता ने पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाकर और बाधाओं को कम करके पेंशनभोगियों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इस जी2ई प्लेटफ़ॉर्म ने 59,722 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जोड़ा है, विभागाध्यक्षों द्वारा 55,610 मामलों का निपटान किया है और 51,552 पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) स्वीकृत किए हैं। 4,058 मामले पी पी ओ अनुमोदन के लिए लंबित हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म ने प्रभावशाली 92.70% पी पी ओ अनुमोदन दर बनाए रखी है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकारी कर्मचारियों को वर्षों की सेवा के बाद उनके पेंशन लाभ तुरंत और सम्मान के साथ प्राप्त हों।

▼ चित्र 1.2 : सेवा सेतु का सिस्टम आर्किटेक्चर

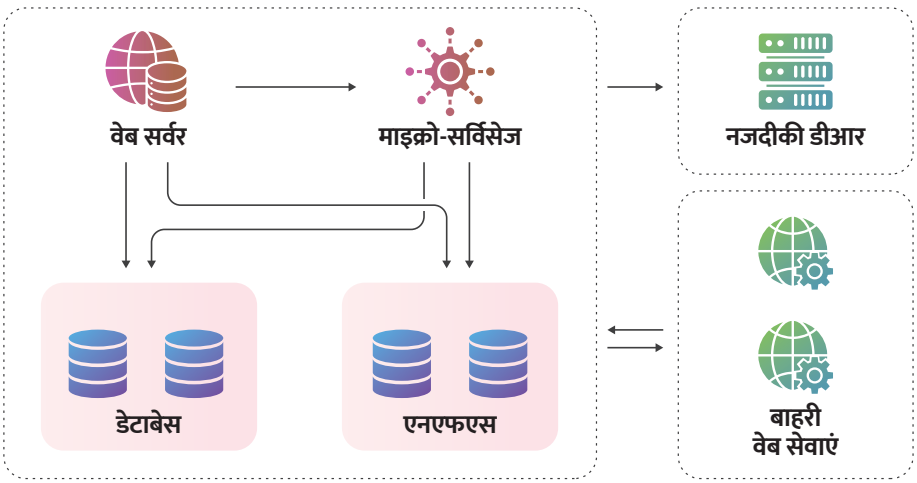

ई-समीक्षा

ई-समीक्षा एक महत्वपूर्ण निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करता है जिसका उपयोग माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विभाग प्रमुखों द्वारा विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। इस प्लेटफ़ॉर्म ने माननीय मुख्यमंत्री की 215 बैठकों में 3,062 कार्य बिंदुओं, उपायुक्त सम्मेलन में 116 कार्य बिंदुओं, एचसीएम नोट्स में 395 कार्य बिंदुओं, एचसीएम भ्रमण निर्देश में 180 कार्य बिंदुओं और सीएम कॉन्क्लेव में 42 कार्य बिंदुओं को सुगम बनाया है। निगरानी के लिए यह व्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि उच्चतम स्तर पर लिए गए निर्णयों की स्पष्ट जवाबदेही तंत्र के साथ कार्यान्वयन के माध्यम से निगरानी की जाए।

ई-प्रयुक्ति सेवा

ई-प्रयुक्ति सेवा त्वरित, अनुकूलन योग्य और कुशल ऐप विकास के लिए वन-स्टॉप मोबाइल ऐप-निर्माण सेवा प्रदान करके जमीनी स्तर पर डिजिटलीकरण के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। पंजीकरण, आवश्यकताओं को एकत्रित करने और वास्तविक समय सेवा स्थिति ट्रैकिंग के लिए एक एकीकृत पोर्टल की सुविधा के साथ, यह उपयोग में आसान प्रणाली विभिन्न विभागों को बिना किसी व्यापक तकनीकी विशेषज्ञता के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपनी सेवाओं को डिजिटल बनाने में सक्षम बनाती है।

जलतरंगिणी

जलतरंगिणी आई ओ टी तकनीक के माध्यम से बाढ़ प्रबंधन और जल संसाधन निगरानी की महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करती है। यह प्रणाली वास्तविक समय में जल स्तर की निगरानी करती है, नेटवर्क-विहीन क्षेत्रों से RF/LoRa के माध्यम से डेटा प्रसारित करती है और महत्वपूर्ण सीमाओं पर अलर्ट जारी करती है। आईओटी-सक्षम RF/LoRa तकनीक पर निर्मित यह प्लेटफ़ॉर्म कॉपीराइट पंजीकृत है और एनआईसी असम द्वारा पेटेंट दायर किया गया है और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इसे लागू करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रणाली ने प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं, जिनमें उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए एनआईसी इनोवेशन चैलेंज 2018 में स्वर्ण और जलवायु/आपदा लचीलापन के लिए ईटी डिजिटेक पुरस्कार 2023 में रजत पुरस्कार शामिल हैं, जो पूर्व चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से जीवन और संपत्ति को बचाने की इसकी क्षमता को उजागर करता है।

असम नागरिक पुरस्कार

असम सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों के वितरण की सुविधा प्रदान करने वाली यह समर्पित ऑनलाइन प्रणाली, एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पुरस्कार नामांकन को सुव्यवस्थित

▲ चित्र 1.3 : सेवा सेतु वेबसाइट होमपेज

करती है। इस पोर्टल को 2023 में 90 और 2024 में 266 आवेदन प्राप्त हुए, जो अनुकरणीय नागरिकों को मान्यता देने में बढ़ती जन भागीदारी को दर्शाता है।

ड्रग्स फ्री असम

ड्रग्स फ्री असम एक मोबाइल ऐप है जो नागरिकों को नशीली दवाओं से संबंधित संदिग्ध गतिविधियों, व्यक्तियों या परिवहन की सूचना पुलिस को देने के लिए सशक्त बनाता है। उपयोगकर्ता गुमनाम रूप से फोटोग्राफिक साक्ष्य और जीपीएस लोकेशन टैगिंग के साथ शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म को अब तक 1,624 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो कानून प्रवर्तन प्रयासों में प्रौद्योगिकी-संचालित जन भागीदारी के माध्यम से नशीली दवाओं के खतरे से निपटने में सामुदायिक भागीदारी को दर्शाता है।

सद्भावना

सद्भावना, फाइलों के त्वरित निपटान के लिए असम सरकार की एक प्रमुख पहल है। सद्भावना पोर्टल के माध्यम से सभी भौतिक फाइलों में लंबित मामलों का समाधान किया जाता है और फाइलों को बंद घोषित किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर 316 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 242 का निपटारा किया गया और 74 प्रक्रियाधीन हैं, जिससे 76.58% का प्रभावशाली निपटान दर बना रहा।

परीक्षा परिणाम

एनआईसी असम ने लगातार 12 वर्षों तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम (एच.एस.एल.सी. और एएचएम) और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (एच.एस.एस.एल.सी.) के परिणाम सफलतापूर्वक प्रकाशित किए हैं। परिणाम के दिन 23 लाख से अधिक वेबसाइट विज़िटर को संभाला है और जारी होने के बाद प्रति मिनट 12,000 हिट्स का प्रबंधन किया है, जो मजबूत बुनियादी ढांचे और मापनीयता का प्रदर्शन करता है।

चिकित्सा परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली

मेड-एएमएस ने चिकित्सा सुविधाओं में चिकित्सा परिसंपत्ति प्रबंधन को निर्बाध परिसंपत्ति प्रविष्टि, वास्तविक समय पारदर्शिता और विक्रेता एकीकरण के माध्यम से सुधारा और अनुकूलित किया है। परिसंपत्तियों की खरीद से लेकर निपटान तक ट्रैकिंग की जाती है जिससे उचित रखरखाव, उपलब्धता और उपयोग सुनिश्चित होता है। इसका उपयोग 16 चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में किया जाता है, जिसमें 3,408 प्रमुख परिसंपत्तियाँ (93% कार्यशील) और 44,227 लघु परिसंपत्तियाँ (92% कार्यशील) पंजीकृत हैं, जिससे चिकित्सा उपकरणों की जवाबदेही और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होता है।

शिक्षकों के लिए राज्य पुरस्कार

यह मंच हर साल शिक्षक दिवस पर राज्य के असाधारण शिक्षकों को सम्मानित करता है। इसमें शिक्षकों के लिए एक सुव्यवस्थित 3-चरणीय व्यापक स्व-नामांकन प्रक्रिया, स्वचालित मूल्यांकन और पूर्वनिर्धारित मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन की सुविधा है, जिससे प्रशासन द्वारा निर्णय लेना आसान हो जाता है। इस जी2सी मंच को 2024 में 273 और 2025 में 427 आवेदन प्राप्त हुए, जिससे 2024 में 13 और 2025 में 15 पुरस्कार विजेताओं का चयन हुआ, जिससे राज्य भर में शिक्षण उत्कृष्टता को मान्यता मिली।

मत्स्य बैभव

असम की "घरे घरे पुखुरी, घरे घरे माछ" (जीजीपीजीजीएम)

यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य चुनाव आयोग असम राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में पारदर्शिता और ईमानदारी बढ़ाने के उद्देश्य से चुनाव प्रक्रिया में आईसीटी अनुप्रयोगों को शामिल करने के लिए लंबे समय से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ काम कर रहा है। 2022 के मध्य में, राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना था। यह कार्य आयोग के मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, असम के सहयोग से किया गया। इस पहल के परिणामस्वरूप, प्रक्रिया के दौरान विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के बाद ऑनलाइन मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली (ओ. ई. आर. एम. एस.) का सफलतापूर्वक विकास किया गया। असम में पहली बार, आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने के लिए ओ. ई. आर. एम. एस. का उपयोग किया और 1.80 करोड़ से अधिक मतदाताओं वाली पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लिए आम चुनाव आयोजित किए।

ओ.ई.आर.एम.एस. के सफल विकास के बाद, आयोग ने एनआईसी असम के सहयोग से चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए आईसीटी अनुप्रयोगों की एक श्रृंखला विकसित करने की पहल की। इनमें ई-निर्वाचन (मतदान और मतगणना कर्मियों के कम्प्यूटरीकृत यादृच्छिकीकरण के लिए), मतपेटी प्रबंधन प्रणाली (मतपेटियों के कम्प्यूटरीकृत यादृच्छिकीकरण के लिए), और चुनाव प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (शपथपत्रों के साथ उम्मीदवारों के नामांकन के डिजिटलीकरण के लिए) शामिल हैं। इन सभी अनुप्रयोगों का पहली बार राभा हसोंग स्वायत्त परिषद चुनाव में और बाद में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के आम चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। पीआरआई चुनावों के दौरान, 1 लाख से अधिक कर्मियों का यादृच्छिक चयन किया गया और उन्हें संबंधित मतदान केंद्रों पर आवंटित किया गया, 50,000 से अधिक मतपेटियों को यादृच्छिक रूप से आवंटित किया गया, और 7,000 से अधिक नामांकन प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया।

उपरोक्त सभी आईसीटी अनुप्रयोगों को श्री रुबाइयात उल अली (वैज्ञानिक-एफ), एनआईसी, असम के नेतृत्व में उच्च योग्य सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की एक टीम और एक अनुभवी प्रबंधन समिति द्वारा विकसित किया गया था। इन अनुप्रयोगों का प्रबंधन एनआईसी असम के जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों (डीआईओ) और अतिरिक्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों (एडीआईओ) द्वारा कुशलतापूर्वक किया जाता है, जो राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात हैं।

आयोग एनआईसी असम के प्रयासों की सराहना करता है और असम राज्य में चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए नए आईसीटी अनुप्रयोगों के विकास और कार्यान्वयन की यात्रा जारी रखने की उम्मीद करता है।

श्री आलोक कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)
राज्य चुनाव आयुक्त, असम

▲ चित्र 1.4 : माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा परियोजना सद्भावना का शुभारंभ

योजना के अंतर्गत, मत्स्य परिसंपत्ति पोर्टल और मत्स्य बैभव मोबाइल एप्लिकेशन, जी. जी. पी. जी. जी. एम. के तहत बनाए गए सभी तालाबों और टैंकों की जीपीएस-आधारित जियो-टैगिंग के माध्यम से संपूर्ण डिजिटल संपत्ति मानचित्रण को सक्षम बनाता है। यह मज़बूत मोबाइल समाधान लाभार्थियों की जनसांख्यिकी, तालाबों के सटीक आयाम, भौगोलिक निर्देशांक और वास्तविक समय के फोटोग्राफिक दस्तावेज़ीकरण को व्यवस्थित रूप से कैप्चर करता है। इस एप्लिकेशन ने जी. जी. पी. जी. जी. एम. के अंतर्गत 9,083 तालाबों/टैंकों को सफलतापूर्वक कवर किया है, जिनमें से 9,029 को जियो-टैग किया गया है, 99% कार्य पूर्ण हो चुका है और सरकारी संपत्तियों की पारदर्शी निगरानी का प्रदर्शन किया है।

राज्य सार्वजनिक खरीद पोर्टल

माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा 22 अगस्त, 2022 को लॉन्च किया गया, एस.पी.पी.पी., असम सार्वजनिक खरीद अधिनियम, 2017 के तहत असम के एकीकृत निविदा पहुँच मंच के रूप में कार्य करता है। यह मंच असम निविदाओं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना "पी.एम.जी.एस.वाई., जीईएम और मैन्युअल निविदाओं को एकीकृत करता है, जिससे विभागों को एनआईटी, दस्तावेज़ और शुद्धिपत्र ऑनलाइन प्रकाशित करने में सक्षम बनाता है, साथ ही नागरिकों को निविदा विवरण और डैशबोर्ड तक स्वतंत्र रूप से पहुँच प्रदान करता है, जिससे सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।

मानव संपदा

मानव संपदा, जिसका नाम मानव पूंजी के लिए उपयुक्त है, सरकारी क्षेत्र के लिए एक व्यापक आई सी टी समाधान प्रदान करता है, जो प्रमुख कार्मिक प्रबंधन आवश्यकताओं को पूरा करता है। वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में लागू, इस जी 2 ई प्लेटफ़ॉर्म ने 3,126 सेवा पुस्तिकाएँ पंजीकृत की हैं, 5,696 अवकाश आवेदन प्राप्त किए हैं, और 2,109 वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) तैयार की हैं, जिससे सरकारी विभागों में मानव संसाधन प्रबंधन सुव्यवस्थित हुआ है।

नियुक्ति

नियुक्ति सरकारी विभागों के लिए एक सेवा के रूप में सॉफ़्टवेयर (SaaS) आधारित भर्ती समाधान है जिससे भर्ती अभियान चलाया जा सके। भर्ती एजेंसियाँ अधिकृत भर्तीकर्ताओं के रूप में शीघ्रता से शामिल हो सकती हैं और न्यूनतम कॉन्फ़िगरेशन के साथ भर्ती प्रक्रियाएँ शुरू कर सकती हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म तेज़, कुशल और पारदर्शी भर्ती प्रबंधन सुनिश्चित करता है। इसने 2,50,000 आवेदनों का प्रसंस्करण किया है, 900 से अधिक पदों पर 84 भर्ती पूरी की हैं, जिससे राज्य भर में सरकारी भर्तियाँ सुव्यवस्थित हुई हैं।

ई-डाक

ई-डाक मुख्यमंत्री सचिवालय में प्राप्त आधिकारिक पत्रों के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत, भूमिका-आधारित प्लेटफ़ॉर्म है।

▼ चित्र 1.5 : असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा सरमा, सीएम-ट्रांस का शुभारंभ करते हुए

यह भूमिका-आधारित पहुँच और कार्यप्रवाह के साथ संचार की डायरीकरण, प्रबंधन और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रणाली डायरीकृत और पुराने दोनों प्रकार के पत्रों को संभालती है, जिससे केंद्रीकृत ट्रैकिंग क्षमताओं के साथ सभी विभागों में सुव्यवस्थित पत्र प्रबंधन सुनिश्चित होता है।

मातृ पितृ वंदना

2022 में शुरू की गई मातृ पितृ वंदना पहल, असम सरकार के कर्मचारियों को माता-पिता और सास-ससुर के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए सालाना दो दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करती है। छुट्टी लेने के बाद, कर्मचारियों को विभाग प्रमुखों द्वारा अनुमोदित हस्ताक्षरित अवकाश आवेदन और अवकाश अवधि के दौरान माता-पिता के साथ ली गई तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी, जिससे कर्मचारियों के बीच कार्य-जीवन संतुलन और पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इस परिवार कल्याण पहल की जवाबदेही और वास्तविक उपयोग सुनिश्चित होगा।

आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल

प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण, पेंशन और लोक शिकायत विभाग द्वारा शुरू किया गया, सूचना का अधिकार ऑनलाइन पोर्टल आरटीआई अनुरोधों और प्रथम अपीलों को जमा करने और उन पर नज़र रखने के लिए एक पारदर्शी, कागज़ रहित मंच प्रदान करता है। आज तक rtionline.assam.gov.in को 2,812 आरटीआई अनुरोध और 527 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 1,548 नागरिक पंजीकृत हैं और 1,313 सार्वजनिक प्राधिकरण इसमें शामिल हैं। सुरक्षित भुगतान के लिए ई-ग्रास के साथ एकीकृत, यह सूचना तक समय पर पहुँच सुनिश्चित करता है और नागरिकों और अधिकारियों दोनों के लिए प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करता है।

रुर्बनसॉफ़्ट

रुर्बनसॉफ़्ट राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस में असम के योगदान का प्रतिनिधित्व करता है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.) के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली के रूप में कार्य करता है। पूरी तरह से असम में विकसित और सभी 26 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित, यह जी2सी प्लेटफ़ॉर्म आई.सी.ए.पी./डीपीआर योजना, पी.एफ.एम.एस. - सक्षम भुगतान और जियो-रुर्बन ऐप के माध्यम से जियो-टैग की गई संपत्ति ट्रैकिंग को सुव्यवस्थित करता है। हालाँकि नए कार्यों की ऑनबोर्डिंग अब बंद हो गई है, यह प्रणाली तब तक सक्रिय रहती है जब तक सभी विक्रेता भुगतानों का निपटान नहीं हो जाता, जो राष्ट्रीय स्तर पर स्केलेबल समाधान विकसित करने की असम की क्षमता को दर्शाता है।

असम के लिए अनुकूलित राष्ट्रीय परियोजनाएँ

राज्य-विशिष्ट पहलों के अलावा, एनआईसी असम ने स्थानीय आवश्यकताओं और भाषाई आवश्यकताओं के अनुरूप 12 प्रमुख राष्ट्रीय परियोजनाओं को सफलतापूर्वक अनुकूलित और कार्यान्वित किया है। ई-ऑफिस पहल ने निदेशालय स्तर तक सभी विभागों में 100% ई-फाइल अपनाई है, 811,640 ई-फाइलें, 4516,764 रसीदें बनाई हैं और 137,787 फाइलों को परिवर्तित करते हुए 1373,667 पत्र जारी किए हैं, जिससे कुशल और पारदर्शी शासन

▲ चित्र 1.6 : माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सेवा सेतु पोर्टल का शुभारंभ किया

संभव हुआ है और कहीं भी, कभी भी फाइलों तक पहुँच संभव हुई है। ई-ट्रांसपोर्ट प्लेटफ़ॉर्म, जिसे सीएम-ट्रांस के नाम से जाना जाता है, असम को 73 संपर्क रहित सेवाओं के साथ परिवहन स्वचालन में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाता है। यह व्यापक प्रणाली स्पीड लिमिटिंग डिवाइस, ई-चालान और ई-डार को एकीकृत करती है। इसमें परिवहन सेवाओं के पूर्ण स्वचालन के साथ-साथ, पायलट पहल के रूप में एम.ओ.आर.टी.एच. की कैशलेस उपचार योजना भी शामिल है।

अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आई.सी.जे.एस.) असम में एक सफल पहल है, जो पुलिस, ई-न्यायालय, ई-कारागार, ई-फोरेंसिक और ई-अभियोजन को एकीकृत करती है, जिसमें चिकित्सा विधिक परीक्षा और पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग प्रणाली (मेडलीएपीआर) भी शामिल है, जिससे 'एक डेटा, एक प्रविष्टि' सिद्धांत के तहत निर्बाध डेटा साझाकरण सुनिश्चित होता है, जिससे त्वरित और पारदर्शी न्याय प्रदान करना सुनिश्चित होता है। जीवन प्रमाण असमिया भाषा समर्थन के साथ बायोमेट्रिक-सक्षम डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करता है, जिसमें 32,708 सफल प्रस्तुतियाँ दर्ज की जाती हैं, जबकि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) एप्लिकेशन 1,115 पंजीकृत परियोजनाओं, 83 पंजीकृत एजेंटों और 405 शिकायतों (262 निपटाई गई) के साथ रियल एस्टेट विनियमन की सुविधा प्रदान करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 35,055 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 2,46,78,138 लाभार्थियों को कवर करते हुए 70,86,456 राशन कार्ड धारकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस.) असम को शिकायत निपटान के लिए पूर्वोत्तर में दूसरे और राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर रखती है, जबकि नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल 129 स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ता है, जो 14.723 मिलियन से अधिक ओपीडी पंजीकरणों को संसाधित करता है और 687 स्वास्थ्य सुविधाओं में कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। स्पैरो 5,720 ए.पी.ए.आर. पंजीकृत, समीक्षा और स्वीकृत के साथ प्रदर्शन प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है, जबकि ई-प्रोक्योरमेंट ने असम में 2014 में अपनी शुरुआत के बाद से ₹2,96,701 करोड़ मूल्य की 71,057 निविदाओं को सुगम बनाया है। ई-जागृति प्लेटफ़ॉर्म उपभोक्ता संरक्षण को सशक्त बनाता है 7,144 शिकायतें दर्ज की गईं और 4,877 का निपटारा किया गया (68.27% निपटान दर)। ये एनआईसी असम की अंतर-संचालन क्षमता और मानकों को बनाए रखते हुए राज्य-विशिष्ट संदर्भों के लिए राष्ट्रीय समाधानों को अनुकूलित करने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र

क्षेत्र की कंप्यूटिंग क्षमता को मज़बूत करने के लिए, पूर्वोत्तर के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र, 4 मेगावाट कुल क्षमता के साथ, एनआईसी और निक्सी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह रणनीतिक बुनियादी ढाँचा विकास क्षेत्रीय डिजिटल क्षमताओं में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। 200 से अधिक सर्वर रैक (400 तक विस्तार योग्य) की क्षमता के साथ, उच्च-स्तरीय कनेक्टिविटी, ऑन-डिमांड क्लाउड बुनियादी ढाँचा, और सुरक्षित डेटा होस्टिंग, प्रसंस्करण और डेटा प्रबंधन के साथ, यह पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक मज़बूत डिजिटल आधार तैयार करेगा जो ई-गवर्नेंस पहलों की बढ़ती माँगों का समर्थन करेगा।

▼ चित्र 1.7 : राष्ट्रीय डेटा केंद्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र

मुख्य सेवाएँ

निकनेट, एनकेएन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएँ और वेबकास्टिंग जैसी मुख्य सेवाएँ पूरे राज्य में व्यापक रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं। निकनेट 2003 से असम सरकार की डिजिटल आधारशिला रहा है, जिसका 21,388 नोड्स का व्यापक नेटवर्क चौबीसों घंटे निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करता है। असम सचिवालय के मज़बूत लैन बुनियादी ढाँचे में 5,000 से ज़्यादा नोड्स हैं जिनमें अप्रतिबंधित इंटरनेट बैंडविड्थ और आईपीवी6 अनुपालन है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएँ 1995 से एनआईसी असम के पोर्टफोलियो का हिस्सा रही हैं, जो कोविड-19 महामारी के दौरान अमूल्य साबित हुईं। 2025 (सितंबर तक) में 950 वीडियो कॉन्फ्रेंस और 2024 में 1,619 कॉन्फ्रेंस आयोजित की गईं। राज्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत ईमेल सेवाओं द्वारा और भी मजबूत किया गया है, जो assam.gov.in और assampolice.gov.in डोमेन पर 50,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं को समर्थन प्रदान करती हैं, और एक समर्पित सेवा डेस्क टिकटिंग प्रणाली के माध्यम से चौतरफा तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं। असम में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) उपस्थिति केंद्र 2011 से चालू है, जो 12 कोर नेटवर्क से जुड़ता है और 80G बैंडविड्थ क्षमता और उच्च उपलब्धता प्रणालियों के साथ 10/2.5 जी.बी.पी.एस. बैंडविड्थ प्रदान करता है, जो 64 प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को जोड़ता है।

रीजनल एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड ऑडिट

रासा, रीजनल सेंटर फॉर एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड ऑडिट, जो जयनागर, गुवाहाटी में स्थित है, अनुप्रयोग सुरक्षा ऑडिट्स, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, और पेनेट्रेशन टेस्टिंग सहित व्यापक सेवाएँ प्रदान करता है।

निष्कर्ष

एनआईसी असम राज्य सरकार का सबसे विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदार बनकर उभरा है, जो प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक सेवा वितरण को मज़बूत करने के लिए पूरी तरह से डिजिटल समाधान प्रदान करता है, जो राज्य मुख्यालय से लेकर दूरस्थ ज़िलों तक फैला हुआ है। असम सरकार की अधिकांश आईसीटी पहलों को संभालने, राष्ट्रीय स्तर पर समाधान विकसित करने और जल तरंगिनी जैसे अग्रणी नवाचारों की राज्य केंद्र की उपलब्धि, सरकार और एनआईसी के बीच प्रतिबद्ध साझेदारी की क्षमता को प्रदर्शित करती है। एनआईसी की तकनीकी विशेषज्ञता और राज्य सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा संचालित असम की डिजिटल परिवर्तन यात्रा, अन्य राज्यों के लिए, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण भौगोलिक और अवसंरचनात्मक परिदृश्यों में, एक प्रेरक मॉडल के रूप में कार्य करती है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी असम राज्य केंद्र
प्रथम तल, कम्पोजिट बिल्डिंग, अंतिम द्वार, दिसपुर
गुवाहाटी, असम - 781006
ईमेल: sio-asm@nic.in, फ़ोन: 0361-2237164

छत्तीसगढ़

डिजिटल विकास के साथ जड़ें मजबूत करना

संपादित : **सुषमा मिश्रा**

छत्तीसगढ़, जिसे अक्सर "भारत का धान का कटोरा" कहा जाता है, डिजिटल शासन और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण में लगातार अग्रणी बनकर उभरा है। पिछले कुछ वर्षों में, राज्य ने अपनी मुख्यतः ग्रामीण और आदिवासी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तकनीक का लाभ उठाया है, साथ ही सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की है।

भूमि अभिलेखों और धान खरीद के संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण से लेकर डिजिटल छात्रवृत्ति, आधार-सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणालियों तक की पहलों के साथ, छत्तीसगढ़ ने समावेशी विकास के लिए एक मज़बूत आधार तैयार किया है। राज्य ने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप वाहन, सारथी, एन.जी.डी.आर.एस., ई-कोर्ट, मनरेगासॉफ्ट और पीएमएवाई-जी जैसे राष्ट्रीय प्लेटफार्मों को भी एकीकृत किया है। एनआईसी, छत्तीसगढ़ ने राज्य विधानसभा में प्रश्न/उत्तर को और अधिक सहज बनाने के लिए भी तकनीक का लाभ उठाया है।

निकनेट, स्वान और एनकेएन के माध्यम से मजबूत नेटवर्क अवसंरचना द्वारा समर्थित और राज्य एवं जिला दोनों स्तरों पर व्यापक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग द्वारा सुदृढ़, छत्तीसगढ़ एक डिजिटल रूप से सशक्त राज्य में परिवर्तित हो गया है। इसकी उपलब्धियों को

तेज नारायन सिंह
उप. महानिदेशक व एसआईओ
tnsingh@nic.in

सत्येश कुमार शर्मा
तकनीकी निदेशक व एसएमसी
satyesh@nic.in

ज्योति शर्मा
वैज्ञानिक - सी
jyoti.soni@nic.in

छत्तीसगढ़ भूमि अभिलेख (भुईंया, भू-नक्शा), कृषि (एकीकृत किसान पोर्टल, टोकन तुहार हाथ), कल्याण (छात्रवृत्ति पोर्टल, ए.ई.पी.डी.एस.), आवास, श्रम, उत्पाद शुल्क और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में डिजिटल शासन के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। निकनेट, एनकेएन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहयोग से, राज्य राष्ट्रीय एमएमपी को एकीकृत करता है और राष्ट्रीय पुरस्कार जीतता है। इसका भविष्य ऑटो-म्यूटेशन, एआई-संचालित एनालिटिक्स, पेपरलेस फाइनेंस और नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय स्तर पर ई-गवर्नेंस, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सुधारों में नवाचार के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

जैसे-जैसे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, उसका ध्यान डिजिटल समावेशन को गहरा करने, एआई-संचालित विश्लेषण का विस्तार करने और नागरिक-केंद्रित पोर्टलों को बेहतर बनाने पर बना हुआ है - यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रौद्योगिकी शासन और जमीनी स्तर के बीच की खाई को पाटती रहे।

राज्य में आईसीटी पहलें

एनआईसी छत्तीसगढ़ शासन को बेहतर बनाने और नागरिक सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए अत्याधुनिक डिजिटल समाधानों को डिज़ाइन और कार्यान्वित करने में अग्रणी रहा है। इसका ध्यान विभिन्न विभागों में एकीकृत, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल प्रणालियों के निर्माण पर रहा है। कुछ प्रमुख राज्य-स्तरीय आईसीटी पहलों में शामिल हैं:

भुइयां

https://bhuiyan.cg.nic.in

भुइयां छत्तीसगढ़ की प्रमुख भूमि अभिलेख कम्प्यूटरीकरण परियोजना है, जो कागज़-आधारित अभिलेखों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में परिवर्तित करती है। नागरिक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बी-I (खतौनी) और पी-II (खसरा) निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अधिकारी ओटीपी और आधार सत्यापन के साथ प्रविष्टियों, स्वचालित म्यूटेशन और अनुमोदनों का ऑनलाइन प्रबंधन करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ: ऑनलाइन नामांतरण रजिस्टर, जियो-टैगिंग के साथ मौसमी फसल (गिरदावरी) प्रविष्टि, आधार/मोबाइल लिंकेज, शहरी नजूल और डायवर्जन रिकॉर्ड, एसएमएस अलर्ट, और पटवारियों और नागरिकों के लिए एक मोबाइल ऐप।

प्रभाव

- 20,527 गाँवों का डिजिटलीकरण; 19,566 मानचित्रों का एकीकरण
- 5,500 से अधिक पटवारी सक्रिय रूप से इस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं
- बैंक एकीकरण से त्वरित कृषि ऋण प्राप्त होता है
- नागरिकों को भूमि अभिलेखों तक तत्काल, पारदर्शी पहुँच प्राप्त होती है।

स्वतः-म्यूटेशन के लिए एन.जी.डी.आर.एस. और योजना सत्यापन के लिए एकीकृत किसान पोर्टल से जुड़कर, भुइयां राज्य में डिजिटल भूमि प्रशासन की आधारशिला बन गया है।

भू-नक्शा

https://bhunaksha.cg.nic.in

भू-नक्शा छत्तीसगढ़ के भू-नक्शों को ऑनलाइन लाता है, जिसमें स्थानिक और पाठ्य भूमि अभिलेखों को एकीकृत किया गया है। यह भूखंडों के विभाजन, विलय और पुनर्संख्यांकन की सुविधा प्रदान करता है, और नामांतरण रजिस्टर में अद्यतनों को भी प्रदर्शित करता है।

मुख्य विशेषताएँ: 19,566 ग्राम मानचित्रों, क्षेत्रफल/दूरी मापन उपकरणों, स्वामी-वार भूखंड रिपोर्ट और कई मुद्रण विकल्पों (ए4 भूखंड मानचित्रों से ए0 ग्राम मानचित्रों) तक ऑनलाइन पहुँच। सुसंगतता के लिए सीधे भुइयां के साथ एकीकृत।

प्रभाव

- राज्य के लगभग सभी गाँवों का पूर्ण कवरेज
- 5,500 से अधिक पटवारी दैनिक कार्यों के लिए मानचित्रों को अद्यतन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं
- नागरिक भूमि भूखंड मानचित्रों को देख, डाउनलोड और प्रमाणित कर सकते हैं, जिससे विवादों में कमी आती है

भूनक्शा नक्शों को ज़मीन के लिखित रिकॉर्ड के साथ मिलाकर, पारदर्शी, कुशल और नागरिक-हितैषी ज़मीन प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

सी.जी.ए.डब्ल्यू.ए.ए.एस.

https://tcp.cg.gov.in

यह छत्तीसगढ़ की ऑनलाइन प्रणाली है जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कॉलोनी विकास परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करती है। यह बहु-विभागीय अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है, पारदर्शिता और समयबद्ध सेवा वितरण सुनिश्चित करती है।

मुख्य विशेषताएँ

- कॉलोनाइज़र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और डिजिटल भुगतान कर सकते हैं
- आवेदन निर्धारित समय-सीमा (120 दिन) के साथ नोडल विभागों में स्थानांतरित होते हैं
- आवेदकों को चरण-दर-चरण अपडेट, अस्वीकृति सूचनाएँ और अंतिम अनुमोदन डिजिटल रूप से प्राप्त होते हैं
- कॉलोनी अनुमोदन और राजस्व के लिए स्वचालित एमआईएस

प्रभाव (2025)

- 804 आवेदन प्राप्त हुए, 238 वितरित किए गए, और 29 खसरा एकीकरण पूर्ण हुए
- अनुमोदनों से ₹34.9 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ
- शहरी विस्तार के लिए मैन्युअल अड़चनों को कम किया गया और तेज़ निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई

कॉलोनी अनुमोदनों को डिजिटल बनाकर, सी.जी.डब्ल्यू.ए.ए.एस. ने तेज़ आवास विकास, बेहतर शहरी प्रशासन और डेवलपर्स और नागरिकों दोनों के लिए अधिक पारदर्शिता को सक्षम बनाया है।

ऑनलाइन ऑडिट और ई-सीएसए

https://res.cg.gov.in

छत्तीसगढ़ के ऑनलाइन ऑडिट और ई-सीएसए (राज्य ऑडिट प्रणाली) प्लेटफ़ॉर्म पंचायती राज संस्थाओं, मंडियों, विश्वविद्यालयों, बोर्डों और निगमों के ऑडिट को डिजिटल बनाते हैं, मानकीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ:

- पंचायती राज संस्थाओं का ऑनलाइन ऑडिट, ई-ग्राम स्वराज के साथ एकीकृत
- मंडियों, विश्वविद्यालयों और राज्य संस्थाओं के लिए कार्यप्रवाह-आधारित ऑडिट
- मानकीकृत प्रारूप, डिजिटल संरक्षण और एमआईएस डैशबोर्ड
- रीयल-टाइम फंड ट्रैकिंग के लिए ई-कोष और ई-वर्क्स से लिंक

प्रभाव

- 11,688 ग्राम पंचायत प्रोफाइल बनाए, जिनमें से 11,586 ग्राम विकास परियोजनाएँ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपलोड की गईं
- पंचायती राज संस्थाओं और संस्थानों में 11,800 से अधिक ऑडिट पूरे किए गए
- कई ई-पंचायत पुरस्कारों से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त

इन प्रणालियों ने रीयल-टाइम वित्तीय निगरानी को सक्षम बनाया है और फंड उपयोग में जमीनी स्तर पर जवाबदेही को मजबूत किया है।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल

https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/

छत्तीसगढ़ का पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को छात्रवृत्ति का कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह वितरण सुनिश्चित करना है। यह एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म छात्रवृत्ति प्रबंधन के संपूर्ण जीवनचक्र को सुव्यवस्थित करता है - छात्र पंजीकरण और छात्रावास नामांकन से लेकर धन स्वीकृति, हस्तांतरण और व्यय निगरानी तक। यह प्रणाली मैन्युअल बाधाओं को दूर करती है और छात्रावास अधीक्षकों, जिला अधिकारियों और राज्य प्रशासकों सहित हितधारकों को समन्वित और पारदर्शी तरीके से संचालित करने में सक्षम बनाती है।

मुख्य विशेषताएँ

- **ऑनलाइन छात्रावास प्रबंधन:** नए प्रवेश, नवीनीकरण, उपस्थिति और वार्षिक छात्रावास बंद होने की संपूर्ण प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण
- **एकीकृत कार्यप्रवाह:** अधीक्षकों से लेकर सहायक आयुक्तों द्वारा जिला-स्तरीय अनुमोदन तक निधि प्रस्तावों को सुव्यवस्थित करना
- **डीबीटी:** कुशल और सुरक्षित भुगतान के लिए छात्रवृत्ति और वजीफे सीधे अधीक्षकों और प्रधानाध्यापकों के संयुक्त खातों में जमा करना
- **वास्तविक समय व्यय निगरानी:** छात्रावास/आश्रम निधियों पर वास्तविक समय में नज़र रखना, आवंटित निधियों की स्वीकृत बनाम स्वीकृत सीटों से तुलना करना
- **एमआईएस रिपोर्टिंग:** विभागीय अधिकारियों को सूचित योजना, लेखा परीक्षा और निर्णय लेने के लिए विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करना

प्रभाव और उपलब्धियाँ

- 1341 आश्रम, 1782 प्री-मैट्रिक छात्रावास और 457 पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास इस प्रणाली पर पंजीकृत हैं
- चालू सत्र में 78,917 नए छात्र और 1,25,652 नवीनीकरण छात्र नामांकित हुए
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से छात्रावासों/आश्रमों को ₹301 करोड़ सफलतापूर्वक हस्तांतरित किए गए, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई
- रीयल-टाइम डैशबोर्ड प्रशासकों को जिलों में छात्रावासों में उपस्थिति, स्वीकृत सीटों और व्यय के रुझान की निगरानी करने में सक्षम बनाते हैं

इस पोर्टल ने न केवल प्रसंस्करण में देरी और प्रशासनिक खर्चों को कम किया है, बल्कि छात्रों और अभिभावकों के बीच विश्वास भी बढ़ाया है। सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और लाभार्थियों के बीच की खाई को पाटकर, यह समावेशी शिक्षा के लिए डिजिटल सशक्तिकरण का एक मॉडल बन गया है।

एचएमएस और आर.एस.एम.आई.एस

छत्तीसगढ़ की छात्रावास प्रबंधन प्रणाली (एचएमएस) और आवासीय विद्यालय एमआईएस (आर.एस.एम.आई.एस), राज्य द्वारा संचालित छात्रावासों और विशिष्ट आदिवासी विद्यालयों के प्रशासन को डिजिटल बनाती हैं, जिससे छात्र कल्याण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

छात्रावास प्रबंधन प्रणाली (एचएमएस)

- 1341 आश्रमों, 1782 प्री-मैट्रिक और 457 पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण
- छात्रावास अधीक्षकों द्वारा प्रस्तुत उपस्थिति, व्यय और निधि प्रस्तावों पर नज़र रखती है।
- स्वीकृत बनाम स्वीकृत सीटों की निगरानी के लिए डैशबोर्ड के साथ, जिला-स्तरीय सत्यापन के बाद सीधे निधि हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है।

आवासीय विद्यालय एमआईएस

- 75 एकलव्य विद्यालयों (21,084 छात्र) और 15 प्रयास विद्यालयों (4,946 छात्र) को कवर करता है
- प्रवेश, आवधिक परीक्षा परिणाम और शैक्षणिक प्रदर्शन रिकॉर्ड करता है
- ऑनलाइन निधि स्वीकृति और उपयोग निगरानी के साथ, बुनियादी ढाँचे और जनशक्ति संसाधनों पर नज़र रखता है।

ये प्रणालियाँ मिलकर छात्रों के प्रवेश, शैक्षणिक परिणामों और संसाधन प्रबंधन की निगरानी के लिए एक 360° डिजिटल ढांचा तैयार करती हैं। छात्रावास कल्याण को विद्यालय प्रदर्शन ट्रैकिंग के साथ जोड़कर, वे जनजातीय और हाशिए पर रहने वाले छात्रों के लिए डेटा-आधारित निर्णय लेने और लक्षित समर्थन सुनिश्चित करते हैं।

इन पोर्टलों को https://hmstribal.cg.nic.in/ और https://eklavya.cg.nic.in/ पर एक्सेस किया जा सकता है।

▼ चित्र 2.1 : माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साईं ने छत्तीसगढ़ भर में 51 महतारी सदनों का वर्चुअल उद्घाटन किया

एनआईसी ने हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली पोर्टल बनाया है। यह डिजिटल शासन में एक बड़ी सफलता है। इस पहल से पता चलता है कि हम हर छात्र को बराबर और हॉस्टल/आश्रम से जुड़ी अच्छी शिक्षा देने के लिए पक्के हैं।

यह पोर्टल नई तकनीक से हॉस्टल के सारे काम आसान बनाता है, जिससे सही छात्रों को पूरी पारदर्शिता, तेज़ी और सही समय पर मदद मिलती है। हमारा मानना है कि यह पोर्टल आगे चलकर सरकारी मदद देने के तरीके को और बेहतर बनाएगा, जिससे हमारे देश के युवाओं को शक्ति मिलेगी और देश का भविष्य मज़बूत होगा।

सोनमणि बोरा, आईएएस
प्रमुख सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग, छत्तीसगढ़

एकीकृत किसान पोर्टल

https://agriportal.cg.nic.in

एकीकृत किसान पोर्टल एक एकल-खिड़की प्लेटफ़ॉर्म है जो प्रत्येक किसान को भुइयां भूमि अभिलेखों से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी प्रदान करता है, जिससे प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है और दोहराव समाप्त होता है।

मुख्य विशेषताएँ

- एक किसान - एक आईडी जिसमें व्यक्तिगत, भूमि और फसल संबंधी विवरण शामिल हैं
- धान खरीद, बागवानी, इथेनॉल और गन्ना खरीद, पीएम-आशा जैसी योजनाओं का समर्थन करता है
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के लिए तैयार, बैंक खातों का सत्यापन पीएफएमएस के माध्यम से किया जाता है
- सुरक्षित अंतर-संचालन के लिए एपीआई-आधारित डेटा साझाकरण
- एकल पंजीकरण, अनेक योजनाओं में उपयोग योग्य

प्रभाव (2025)

- 27.19 लाख किसान पंजीकृत
- 207 फसलों और 37.2 लाख हेक्टेयर का मानचित्रण
- अनेक विभागों में निर्बाध लाभ वितरण
- दोहराव को रोका, दक्षता में सुधार किया, और वास्तविक समय निगरानी को सक्षम बनाया

यह पोर्टल छत्तीसगढ़ में डिजिटल कृषि शासन की रीढ़ बन गया है, जिसने किसानों की पहुँच को सरल बनाया है और डेटा-आधारित नीतिगत निर्णयों का समर्थन किया है।

कंप्यूटरीकृत धान खरीद प्रणाली

छत्तीसगढ़ ने 2007 में अपनी कंप्यूटरीकृत धान खरीद प्रणाली की शुरुआत की, जिसने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाते हुए 25.49 लाख किसानों को लाभ पहुँचाया।

शुरुआती चरण में, अधिकांश केंद्रों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी थी, इसलिए खरीद, मिलर को जारी करने और रसीदों को संभालने के लिए एक स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया। अभिनव रनर्स मॉड्यूल के तहत लगभग 250 मोटरसाइकिल सवारों को तैनात किया गया, जो केंद्रों से ब्लॉक मुख्यालयों तक दैनिक डेटा ले जाते थे, जहाँ इसे एनआईसीनेट के माध्यम से अपलोड किया जाता था। सी.जी.एस.सी.एस.सी. और एफसीआई के सीएमआर केंद्र भी इसी तरह के ऑफ़लाइन सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते थे जो सर्वर के साथ स्वतः सिंक हो जाता था। पूर्ण कंप्यूटरीकरण ने किसानों को चेक से तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया।

आज, सभी खरीद संचालन—मिल पंजीकरण, अनुमति, समझौते, प्रतिभूतियाँ, डिलीवरी ऑर्डर, और रसीदें/इश्यू—पूरी तरह से ऑनलाइन हैं। किसानों और मिलरों को भुगतान पी.एफ.एम.एस. और एसबीआई एसएफजी सर्वर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित किया जाता है।

खरीद टोकन के लिए लगने वाली कतारों को समाप्त करने के लिए, एनआईसी ने 'तुँहर टोकन' ऐप लॉन्च किया, जिससे किसान स्वयं टोकन जनरेट कर सकते हैं और केंद्र-वार विवरण की जाँच कर सकते हैं। समितियों के माध्यम से ऑफ़लाइन टोकन विकल्प अभी भी उपलब्ध हैं।

किसान पंजीकरण अब राष्ट्रीय एग्रीस्टैक पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, जिसमें पहले ही 26.49 लाख किसान एग्रीस्टैक आईडी के साथ यूनिफाइड फार्मर्स पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, और खरीद 15 नवंबर 2025 से शुरू होगी।

मुख्य विशेषताएँ

- राज्य भर में 2,739 खरीद केंद्र
- 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद
- 87 भंडारण केंद्रों, 296 सीएमआर डिपो और 2,889 चावल मिलों के साथ एकीकृत
- 64% किसानों ने टोकन बुकिंग के लिए मोबाइल ऐप का सक्रिय रूप से उपयोग किया

भूमि अभिलेख, बैंक खातों और उपार्जन डेटा के एकीकरण से छत्तीसगढ़ ने एक पारदर्शी, कुशल और किसान-हितैषी डिजिटल प्रणाली विकसित की है—जो डिजिटल कृषि प्रशासन का एक आदर्श मॉडल बन चुकी है।

ए.ई.पी.डी.एस और आर.सी.एम.एस.

https://epos.cg.gov.in/

आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (एईपीडीएस) और राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) छत्तीसगढ़ की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का संपूर्ण स्वचालन प्रदान करती है, जिससे एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

मुख्य विशेषताएँ

- **व्यापक कवरेज:** 13,940 एफ़पीएस में 81 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक
- **आधार प्रमाणीकरण:** दोहराव को समाप्त करता है और वास्तविक लाभार्थियों की पहुँच सुनिश्चित करता है
- **पोर्टेबिलिटी:** ओ.एन.ओ.आर.सी. के अंतर्गत किसी भी एफ़पीएस से राशन उपलब्ध है
- **रीयल-टाइम निगरानी:** डिजिटल पीओएस उपकरण एमआईएस डैशबोर्ड के लिए लेनदेन को रिकॉर्ड करते हैं
- **योजना-वार ट्रैकिंग:** एन.एफ.एस.ए., सी.जी.एफ.एस.ए., अंत्योदय और अन्य श्रेणियों का समर्थन करता है

प्रभाव

- 81.03 लाख कार्ड और 2.6 करोड़ से अधिक लाभार्थी
- सभी एफपीएस पर स्वचालित लेनदेन
- खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि

इस प्रणाली ने छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक नागरिक-केंद्रित, जवाबदेह और पोर्टेबल नेटवर्क में बदल दिया है, जिससे निवासियों और प्रवासी परिवारों दोनों को लाभ हो रहा है।

श्रम विभाग पोर्टल

https://shramevjayate.cg.gov.in/

छत्तीसगढ़ का श्रम विभाग पोर्टल पंजीकरण, कल्याणकारी योजनाओं, उपकर संग्रह और अनुपालन निगरानी को एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर एकीकृत करता है। यह श्रमिकों, नियोक्ताओं और ठेकेदारों के लिए संपूर्ण स्वचालन प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है।

मुख्य विशेषताएँ

- **श्रमिक पंजीकरण:** आधार-आधारित सत्यापन के साथ निर्माण, संगठित और असंगठित श्रमिकों को शामिल करता है
- **क्यूआर-कोडेड स्मार्ट कार्ड:** श्रमिकों को पहचान और योजना तक पहुँच के लिए जारी किए जाते हैं
- **ऑनलाइन उपकर और शुल्क संग्रह:** व्यापार में आसानी के लिए एकीकृत भुगतान गेटवे
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:** छात्रवृत्ति, मातृत्व, पेंशन और आवास लाभ सीधे श्रमिक खातों में जमा किए जाते हैं
- **जोखिम-आधारित निरीक्षण:** पारदर्शिता के लिए स्वचालित ऑनलाइन निरीक्षण
- **एकल खिड़की:** नियोक्ताओं, ठेकेदारों, कारखानों और ट्रेड यूनियनों के लिए एकीकृत सेवाएँ

प्रभाव

- 49.3 लाख श्रमिक पंजीकृत (29 लाख निर्माण, 17 लाख असंगठित, 2 लाख संगठित)
- 20,426 नियोक्ता/ठेकेदार जुड़े
- ₹1,300+ करोड़ उपकर और ₹33+ करोड़ कल्याणकारी निधि प्रतिवर्ष एकत्रित
- 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) आधारित योजना लाभ प्राप्त हुए

पंजीकरण, योजना लाभ और अनुपालन को डिजिटल बनाकर, यह पोर्टल एक वन-स्टॉप श्रम शासन समाधान के रूप में उभरा है, जो श्रमिकों को सशक्त बनाते हुए उद्योग के लिए नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।

ई-आवास

https://cghb.gov.in

ई-आवास प्रणाली छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति प्रबंधन प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाती है, जिससे आवंटन में पारदर्शिता और कुशल संपत्ति संचालन सुनिश्चित होता है।

मुख्य विशेषताएँ

- **संपत्ति और लेखा प्रबंधन:** आवंटन, वसूली और वित्त के लिए कार्यप्रवाह-आधारित मॉड्यूल
- **ऑनलाइन संपत्ति खोज (समृद्धि):** नागरिक संपत्तियों की खोज, उपलब्धता की जाँच और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
- **डिजिटल भुगतान:** किश्तों और शुल्कों के लिए एकीकृत भुगतान गेटवे
- **पारदर्शिता:** आवेदन से लेकर आवंटन तक डिजिटल ट्रैकिंग

प्रभाव

- हज़ारों संपत्ति आवेदनों का डिजिटल रूप से प्रसंस्करण
- कम कागजी कार्रवाई, तेज़ अनुमोदन और नागरिकों की सुविधा
- आवास बोर्ड के लेन-देन में जवाबदेही बढ़ी है

इस प्रणाली ने संपत्ति प्रबंधन को नागरिक-अनुकूल, पारदर्शी और पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया में बदल दिया है।

ई-आबकारी

https://excise.cg.nic.in

छत्तीसगढ़ की ई-आबकारी परियोजना एक अग्रणी पहल है जो लाइसेंस जारी करने से लेकर आपूर्ति श्रृंखला ट्रैकिंग, राजस्व संग्रहण और प्रवर्तन तक संपूर्ण आबकारी मूल्य श्रृंखला को कवर करती है

मुख्य विशेषताएँ

- **एंड-टू-एंड ऑटोमेशन:** लाइसेंस/परमिट/एनओसी जारी करना, नवीनीकरण और अनुमोदन ऑनलाइन।
- **आपूर्ति श्रृंखला ट्रैकिंग:** शराब की सूची के लिए बारकोडिंग और क्यूआर कोडिंग; जीपीएस-सक्षम वाहन ट्रैकिंग।
- **राजस्व संग्रहण:** ऑनलाइन आबकारी शुल्क संग्रहण, नकद प्रबंधन और वास्तविक समय निगरानी।
- **प्रवर्तन और पारदर्शिता:** आर.एफ.आई.डी.-सक्षम नकदी ट्रैकिंग, सी.सी.टी.वी. एकीकरण और यादृच्छिक निरीक्षण।
- **मोबाइल ऐप्स:** बार मालिकों, स्टॉक ऑर्डरिंग और कर्मचारी उपस्थिति (ए.ई.बी.ए.एस.) के लिए।

प्रभाव

- 43,1585 परमिट और 61,586 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी
- डिजिटल माध्यमों से ₹40,271 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ
- परिवहन वाहनों में 520 जीपीएस उपकरण लगाए गए और 100 से अधिक निगरानी कैमरे लगाए गए
- नकदी प्रबंधन के लिए 530 आर.एफ.आई.डी. कार्ड जारी किए

हर कदम को डिजिटल बनाकर, ई-आबकारी ने छत्तीसगढ़ को आबकारी प्रशासन में भारत के सबसे उन्नत राज्यों में से एक बना दिया है, जिससे पारदर्शिता, उच्च राजस्व और सख्त अनुपालन सुनिश्चित हुआ है।

विश्वविद्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली

https://igkv.ac.in

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आई.जी.के.वी.) में विश्वविद्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली एक संपूर्ण स्वचालन प्लेटफ़ॉर्म है जो प्रवेश, शैक्षणिक, वित्त, मानव संसाधन, अनुसंधान और डिजिटल लाइब्रेरी सेवाओं को कवर करता है।

मुख्य विशेषताएँ

- **प्रवेश एवं शैक्षणिक:** ऑनलाइन आवेदन, ओएमआर-आधारित परीक्षाएँ, शिकायत निवारण और परिणाम प्रसंस्करण।
- **वित्त एवं मानव संसाधन:** कम्प्यूटरीकृत बिल स्वीकृति, पेरोल, सेवा पुस्तिकाएँ और सीआर प्रबंधन।
- **भर्ती:** प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती।
- **डिजिटल पुस्तकालय एवं अनुसंधान:** आई.जी.के.वी. वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध निष्कर्षों और नवाचारों तक सीधी पहुँच।
- **मोबाइल ऐप्स:** क्रॉप डॉक्टर, ई-कृषि पाठशाला, ई-हाट और किसानों के लिए कस्टम हायरिंग।

प्रभाव

- 2,000 से अधिक आवेदनों का डिजिटल रूप से निपटाया गया
- 9.6 लाख किसानों के प्रश्नों का समाधान किया गया।
- 4.4 लाख वित्तीय बिल तैयार किए गए।
- कृषि परामर्श और मशीनीकरण सेवाओं के माध्यम से किसानों को सीधा लाभ।

इस प्रणाली ने आई.जी.के.वी. को एक डिजिटल रूप से सक्षम कृषि विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया है, जो शिक्षाविदों, प्रशासन और किसानों तक पहुँच को एक मंच पर जोड़ता है।

स्वास्थ्य सेवा आईटी प्रणालियाँ

छत्तीसगढ़ ने अस्पताल स्वचालन, स्वास्थ्य कर्मियों के भुगतान, मातृ देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को आईसीटी प्लेटफार्मों में एकीकृत करके एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है। ये पहलें यह सुनिश्चित करती हैं कि स्वास्थ्य सेवा वितरण कुशल, जवाबदेह और सुलभ हो, खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में।

नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल

https://nextgen.ehospital.gov.in

नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल प्रणाली एक संपूर्ण अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एच.एम.आई.एस.) है जो राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में स्थापित है। यह मरीजों, अस्पतालों और डॉक्टरों को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ती है।

- **विशेषताएँ:** आभा से जुड़ा ओपीडी/आईपीडी पंजीकरण, टोकन और कतार प्रबंधन, ई-प्रिस्क्रिप्शन, फार्मेसी, डायग्नोस्टिक्स, ओटी शेड्यूलिंग, लैब एकीकरण, बिलिंग और डिस्चार्ज।
- **प्रभाव:** 306 अस्पतालों को इसमें शामिल किया गया है, जिनमें जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेज आदि शामिल हैं, जिससे सुचारू कार्यप्रवाह और तेज़ रोगी देखभाल सुनिश्चित हुई है।

एनएचएम डीबीटी पोर्टल

https://nhmdbt.cg.nic.in

एनएचएम डीबीटी पोर्टल अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को समय पर प्रोत्साहन भुगतान सुनिश्चित करता है।

- **कवरेज:** 33 जिलों और 21,000 गाँवों में 71,000 से अधिक मितानिनें और 3,000 प्रशिक्षक शामिल हैं।
- **प्रभाव:** ₹40 करोड़ से अधिक का मासिक डीबीटी, सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाता है, जिससे ज़मीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा को मज़बूती मिलती है।

राज्य स्वास्थ्य प्रणालियाँ

- **उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था निगरानी:** समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए मातृ स्वास्थ्य पर नज़र रखता है।
- **सीएम हाट बाज़ार क्लीनिक:** मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ साप्ताहिक आदिवासी बाज़ारों में सेवाएँ प्रदान करती हैं, दूरस्थ आबादी तक पहुँचती हैं।
- **एस.ओ.टी.टी.ओ. (राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन):** अंग और ऊतक दान की निगरानी करता है, पारदर्शी आवंटन सुनिश्चित करता है।
- **स्वास्थ्य इन्वेंट्रैक:** दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद, भंडारण और वितरण का प्रबंधन करता है।
- **ई-कल्याणी:** एमटीपी अधिनियम के अनुपालन के लिए गर्भपात सेवाओं की ऑनलाइन निगरानी।
- **पोषण पुनर्वास केंद्र:** गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से ग्रस्त 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रदान की जाने वाली देखभाल की डिजिटल निगरानी।

लाभ

- **नागरिकों के लिए:** स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुँच, कम प्रतीक्षा समय और बेहतर मातृ एवं शिशु देखभाल।
- **स्वास्थ्य कर्मियों के लिए:** समय पर भुगतान, बेहतर निगरानी और कम प्रशासनिक बोझ।
- **प्रशासन के लिए:** रीयल-टाइम डैशबोर्ड, बेहतर निधि उपयोग और डेटा-आधारित नीति नियोजन।

इन आईसीटी प्रणालियों ने मिलकर छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवा को एक डिजिटल रूप से सक्षम, नागरिक-केंद्रित नेटवर्क में बदल दिया है, जिससे शहरी अस्पतालों और ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों, दोनों में समान पहुँच सुनिश्चित हुई है।

अन्य राज्य स्वास्थ्य प्रणालियाँ

- **राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण:** मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और निगरानी को विनियमित करता है
- **ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस एमआईएस:** आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं का रिकॉर्ड रखता है
- **राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम:** रोकथाम और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए किफायती मुख स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करता है
- **छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड:** दवाओं, शल्य चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सा उपकरणों की केंद्रीकृत खरीद और वितरण
- **स्वास्थ्य डैशबोर्ड (बजट और योजनाएँ):** बेहतर योजना के लिए धन आवंटन/उपयोग और योजना की प्रगति की वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करता है।

ये सभी पहल मिलकर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल रूप से सक्षम, समावेशी और नागरिक-अनुकूल बनाती हैं, जिससे नीति और अंतिम छोर तक पहुँच के बीच की खाई को पाटा जा सकता है।

राज्य में कार्यान्वित केंद्रीय परियोजनाएँ

छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) को अपनाने और लागू करने में सक्रिय रहा है, और उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालते हुए नागरिकों की सुविधा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर रहा है।

▼ चित्र 2.2 : कागज रहित शासन के लिए पुलिस कर्मचारियों को ई-ऑफिस पर प्रशिक्षित किया गया

वाहन 4.0 और सारथी 4.0

वाहन 4.0 और सारथी 4.0 सभी 28 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में पूरी तरह से लागू हैं। ये वाहन पंजीकरण, परमिट, कर संग्रह, फिटनेस प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस /लर्निंग लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण और स्वामित्व हस्तांतरण के लिए फेसलेस, पेपरलेस सेवाएँ प्रदान करते हैं। राज्य अब 33 फेसलेस वाहन सेवाएँ और 24 फेसलेस सारथी सेवाएँ प्रदान करता है, जिससे आरटीओ में आने वाले लोगों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।

वाहन के माध्यम से 90 लाख से अधिक वाहनों से संबंधित 2 करोड़ लेनदेन संसाधित किए गए हैं, जिनका मूल्य ₹13,000 करोड़ है। सारथी ने 36 लाख ड्राइविंग लाइसेंस और 23 लाख लर्निंग लाइसेंस जारी किए हैं, जिससे ₹311 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए, 555 परिवहन सेवा केंद्र और 238 पीयूसीसी केंद्र (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र केंद्र) कार्यरत हैं।

एचएसआरपी फिक्सेशन दो वेंडरों की तैनाती के साथ जिलों में अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। वी.एल.टी.डी प्रणालियाँ, 8 स्वचालित परीक्षण स्टेशन , आई.आर.ए.डी , और दो स्मार्ट शहरों में आई.टी.एम.एस पूरी तरह से कार्यशील हैं।

वी-कोर्ट 45/90 दिनों के बाद भुगतान न किए गए चालानों को स्वचालित रूप से संसाधित करता है, जिसकी चालान संबंधी जानकारी एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाती है। एएनपीआर और टोल प्लाजा कैमरों का उपयोग करके ई-डिटेक्शन स्वचालित प्रवर्तन सुनिश्चित करता है।

स्वच्छ गतिशीलता की ओर राज्य के प्रयास को मजबूत करते हुए, एक ईवी सब्सिडी पोर्टल भी कार्यशील है।

एन.जी.डी.आर.एस.

एन.जी.डी.आर.एस. (राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली) परियोजना एक राष्ट्र, एक पंजीकरण ढांचे के तहत डिजिटल संपत्ति पंजीकरण और नामांतरण को सक्षम बनाती है।

- **कवरेज:** छत्तीसगढ़ के सभी 102 उप-पंजीयक कार्यालयों में कार्यान्वित
- **एकीकरण:** वास्तविक समय सत्यापन और स्वचालित नामांतरण के लिए भुइयां (भूमि अभिलेख) से जुड़ा
- **लाभ:** नागरिक ऑनलाइन दस्तावेज़ तैयार, जमा और ट्रैक कर सकते हैं, जिससे धोखाधड़ी और देरी कम होती है

नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल

राज्य के 306 सरकारी अस्पतालों में स्थापित, नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल प्रणाली अस्पताल के कार्यप्रवाह का संपूर्ण स्वचालन प्रदान करती है।

- **विशेषताएँ:** ओपीडी/आईपीडी पंजीकरण, एबीएचए एकीकरण, निदान, फार्मेसी और बिलिंग
- **प्रभाव:** 2.16 करोड़ से ज़्यादा ओपीडी पंजीकरण और 14.6 लाख आईपीडी मामले डिजिटल रूप से दर्ज किए गए, जिससे स्वास्थ्य सेवा वितरण में दक्षता में सुधार हुआ

सी.सी.एम.एस

सी.सी.एम.एस छत्तीसगढ़ सरकार के विरुद्ध दायर किए गए अदालती मामलों की शुरुआत से लेकर निपटान तक निगरानी के लिए एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है। यह मामला डेटा को केंद्रीकृत करता है, फाइलिंग से लेकर निपटान तक की कार्यवाही को ट्रैक करता है, और समय पर निर्णय लेने के लिए वास्तविक समय के अपडेट, डैशबोर्ड और स्वचालित रिपोर्ट प्रदान करता है।

मुख्य विशेषताएँ:

- वास्तविक समय में मामलों के सिंक्रनाइज़ेशन के लिए नेपिक्स–एनजेडीजी एकीकरण
- भूमिका-आधारित डैशबोर्ड और अनुकूलन योग्य एमआईएस रिपोर्ट
- सभी लंबित और निपटाए गए मामलों का केंद्रीकृत भंडार
- जवाब, अनुपालन और समय-सीमा की स्वचालित ट्रैकिंग
- सुनवाई और अनुपालन के लिए एसएमएस अलर्ट
- किसी भी समय मामलों तक पहुँच के लिए मोबाइल ऐप

प्रभाव (2025):

- 45 विभागों में 3,206 उपयोगकर्ताओं द्वारा 77,038 मामलों की डिजिटल रूप से निगरानी की गई
- स्वचालित अलर्ट के माध्यम से तेज़ अनुपालन
- वास्तविक समय डेटा से शासन और समन्वय में सुधार
- डिजिटल वर्कफ़्लो के माध्यम से कागज़ी कार्रवाई में कमी

आई.सी.जे.एस.

छत्तीसगढ़ ने अपने न्यायिक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय आईसीजेएस (इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत किया है, जिसमें ई-कोर्ट, ई-फ़ोरेंसिक, ई-अभियोजन, ई-कारागार और ई-समन शामिल हैं।

- **लाभ:** पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और फ़ोरेंसिक विभागों के बीच निर्बाध डेटा आदान-प्रदान संभव
- **प्रभाव:** तेज़ जाँच, बेहतर केस ट्रैकिंग और न्याय हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय

आई.वी.एफ.आर.टी.

आई.वी.एफ.आर.टी. (अप्रवासन, वीज़ा और विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग) परियोजना सभी जिला-स्तरीय विदेशी पंजीकरण कार्यालयों (एफआरओ) में लागू की गई है।

- **सेवाएँ:** ऑनलाइन पंजीकरण, वीज़ा विस्तार, और विदेशी नागरिकों की ट्रैकिंग
- **प्रभाव:** राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि, सुव्यवस्थित प्रक्रिया, और विदेशी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मुलाक़ातों में कमी

मनरेगासॉफ्ट

मनरेगासॉफ्ट प्लेटफ़ॉर्म राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के पूर्ण डिजिटलीकरण को सक्षम बनाता है।

- **कवरेज:** सभी 33 ज़िलों में लागू
- **प्रभाव:** 32.5 लाख से ज़्यादा जॉब कार्ड जारी किए गए और 4.7 करोड़ मज़दूरी भुगतान लेनदेन डीबीटी के माध्यम से संसाधित किए गए, जिससे श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हुआ

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण

छत्तीसगढ़, पी.एम.ए.वाई.-जी. के अंतर्गत आवास वितरण की निगरानी के लिए आवाससॉफ्ट और आवासऐप का उपयोग करता है।

- **कवरेज:** लाभार्थी चयन, आवास निर्माण और धन वितरण की ऑनलाइन ट्रैकिंग
- **प्रभाव:** पारदर्शी निगरानी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के साथ ग्रामीण परिवारों के लिए 11 लाख से अधिक पक्के घर बनाए गए

ई-प्रोक्योरमेंट (केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल)

सी.पी.पी.पी. प्लेटफ़ॉर्म को छत्तीसगढ़ में संचालित केंद्रीय संस्थानों और उद्यमों द्वारा अपनाया गया है।

- **उपयोगकर्ता:** एम्स रायपुर, आईआईटी भिलाई, एनटीपीसी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.), और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएँ
- **लाभ:** सरकारी खरीद में पारदर्शिता, जवाबदेही और खुली प्रतिस्पर्धा लाता है

अन्य शासन एवं नागरिक सेवाएँ

प्रमुख पहलों के साथ-साथ, छत्तीसगढ़ ने कई सहायक आईसीटी प्लेटफ़ॉर्म लागू किए हैं जो शासन, नागरिक सेवाओं और विभागीय दक्षता को विभिन्न क्षेत्रों में मज़बूत बनाते हैं।

शासन एवं न्याय

- **रेवकेस ऐप:** राजस्व न्यायालयों के लिए मोबाइल-सक्षम केस ट्रैकिंग और स्थगन प्रणाली, एसएमएस अलर्ट और डिजिटल ऑर्डर शीट के साथ
- **कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम (सी.सी.एम.एस.):** उच्च न्यायालय में सरकारी मामलों की निगरानी के लिए केंद्रीकृत संग्रह; विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड और अनुपालन ट्रैकिंग
- **विधानसभा प्रणाली (ई-प्रश्न, ई-उत्तर, ई-प्रश्नोत्तरी):** प्रश्न प्रस्तुत करने, उत्तर देने और विधायी दस्तावेज़ प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, विधानसभा कार्यवाही में पारदर्शिता बढ़ाते हैं
- **लोक शिकायत पोर्टल:** मुख्यमंत्री कार्यालय, जन शिकायत और राज्यपाल कार्यालय के लिए एकीकृत शिकायत प्रणाली, रीयल-टाइम ट्रैकिंग और पारदर्शी समाधान के साथ

वित्त एवं कोषागार

- **आभार (ई-पेंशन) और ईकोश लाइट:** पारदर्शिता और दक्षता के लिए पेंशन वितरण और कोषागार भुगतान का डिजिटलीकरण
- **आई.एफ.एम.आई.एस. और एसएनए स्पर्श:** एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली जो सीएसएस और राज्य योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित करती है डीबीटी से जुड़े भुगतानों के साथ
- **ई-चालान और ई-वाउचर:** इलेक्ट्रॉनिक रसीद और व्यय प्रणालियाँ आरबीआई ई-कुबेर प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत

वाणिज्य एवं उद्योग

- **उद्यम आकांक्षा पोर्टल:** एम.एस.एम.ई. और उद्योगों के लिए एकल-खिड़की पंजीकरण, सीएएफ जनरेशन और क्यूआर-कोडेड डिजिटल प्रमाणपत्रों के साथ
- **एकल-खिड़की प्रणाली:** विभिन्न विभागों में अनुमोदन के लिए एक ही आवेदन पत्र, व्यापार करने में आसानी को सक्षम बनाता है
- **फर्म और सोसायटी पोर्टल:** फर्मों और सोसायटी के पंजीकरण और संशोधन के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया, क्यूआर-कोडेड प्रमाणपत्रों के साथ
- **बॉयलर निरीक्षणालय पोर्टल:** बॉयलरों का ऑनलाइन पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण, एकीकृत शुल्क भुगतान और तृतीय-पक्ष सत्यापन के साथ

ये पहल मिलकर प्रमुख परियोजनाओं का पूरक हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय वितरण, शिकायत निवारण, वित्तीय सुधार और औद्योगिक विकास मजबूत डिजिटल प्लेटफार्मों द्वारा समर्थित हैं - व्यापक डिजिटल शासन में अग्रणी के रूप में छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा को मजबूत करते हैं।

मोबाइल ऐप्स

सीजी वीएचएसएनडी ऐप

सीजी वीएचएसएनडी ऐप स्वास्थ्य विभाग को आँगनवाड़ी और

शहरी-वार्ड स्तर पर स्वास्थ्य, प्रारंभिक बचपन विकास, पोषण और स्वच्छता सेवाओं की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। भविष्य में आसान पहुँच के लिए उपयोगकर्ता अपनी एचआरएमआईएस आईडी के साथ एक बार लॉगिन करके एक एमपीआईएन जनरेट करते हैं। स्वास्थ्य सचिव और निदेशक के लिए राज्य-स्तरीय लॉगिन वीएचएसएनडी डेटा की केंद्रीकृत निगरानी और विश्लेषण का समर्थन करते हैं।

छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप

माननीय उप मुख्यमंत्री डॉ. विजय शर्मा द्वारा 14 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया, छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप बेरोजगार युवाओं को सीधे अपने मोबाइल फोन से रोजगार सहायता के लिए पंजीकरण करने में सक्षम बनाता है। त्वरित और सुरक्षित पंजीकरण के लिए आधार ओटीपी आधारित सत्यापन का उपयोग किया जाता है।

यह नया पंजीकरण, नवीनीकरण और रिक्ति जानकारी को सुविधाजनक बनाता है, जिससे किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। पंजीकरण के बाद, उपयोगकर्ताओं को उनका पंजीकरण संख्या, उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग ई-रोजगार पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए भी किया जा सकता है।

जॉब चाहने वाले ऐप के माध्यम से राज्य और जिला-स्तरीय रोजगार मेलों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

अन्य मोबाइल ऐप्स

आई.जी.एम.आई.एस. (एकीकृत शिकायत एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली) परियोजना के अंतर्गत, एनआईसी छत्तीसगढ़ ने किसान- और छात्र-केंद्रित मोबाइल एप्लिकेशन का एक समूह विकसित किया है, जो आवश्यक सेवाओं को सीधे स्मार्टफ़ोन पर उपलब्ध कराता है।

प्रमुख ऐप्स:

- **क्रॉप डॉक्टर:** कीटों, रोगों और पोषक तत्वों की कमी की छवि-आधारित पहचान के लिए एआई-सक्षम ऐप, ऑनलाइन विशेषज्ञ सलाह के साथ। समय पर फसल प्रबंधन के लिए किसानों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है
- **ई-कृषि पाठशाला:** एक डिजिटल कक्षा जो कृषि छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री, वीडियो व्याख्यान, असाइनमेंट और ऑनलाइन परीक्षाएँ प्रदान करती है। 50,000 से ज़्यादा डाउनलोड के साथ, यह मोबाइल पर एक वर्चुअल विश्वविद्यालय बन गया है
- **ई-हाट:** एक मार्केटप्लेस ऐप जो बिचौलियों पर निर्भरता कम करके किसानों को उत्पाद बेचने के लिए सीधे खरीदारों से जोड़ता है
- **कस्टम हायरिंग ऐप:** कृषि मशीनरी की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है

जिससे किसान स्थानीय स्तर पर उपकरण किराए पर ले सकते हैं और मशीनीकरण में सुधार कर सकते हैं।

प्रभाव (2025):

- किसान-केंद्रित ऐप्स में 1.35 लाख से ज़्यादा डाउनलोड
- फसल प्रबंधन, शिक्षा, विपणन और कृषि मशीनरी तक पहुँच में किसानों को सीधा लाभ
- कृषि सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ी और लागत कम हुई

सलाह, शिक्षा, विपणन और मशीनीकरण सहायता को एकीकृत करके, इन मोबाइल ऐप्स ने किसानों और छात्रों को सशक्त बनाया है, जिससे छत्तीसगढ़ डिजिटल कृषि और कृषि-शिक्षा सेवाओं में अग्रणी बन गया है।

▲ चित्र 2.3 : एनआईसी, छत्तीसगढ़ के ई-मानचित्र विज्ञान को सीएसआई मान्यता पुरस्कार प्राप्त हुआ

नेटवर्क और बुनियादी ढाँचा

छत्तीसगढ़ में निकनेट, एनकेएन और उन्नत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाओं के माध्यम से एक मज़बूत डिजिटल ढांचा स्थापित किया गया है, जिससे शासन, शिक्षा, अनुसंधान और न्याय वितरण के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित हुई है।

निकनेट और एनकेएन

- **ज़िला कनेक्टिविटी:** सभी 27 ज़िले 34 एम.बी.पी.एस./100 एम.बी.पी.एस. बी.एस.एन.एल. लिंक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, छह ज़िलों में 1 जी.बी.पी.एस. रेलटेल बैकअप लिंक के साथ
- **कोषागार और विभाग:** एम.पी.एल.एस. लाइनें 67 कोषागारों/उप-कोषागारों और 13 राज्य पेय पदार्थ निगम स्थानों को सुरक्षित लेनदेन के लिए समर्थन प्रदान करती हैं
- **न्यायपालिका और शिक्षा:** लीज़्ड लाइन कनेक्टिविटी 88 न्यायालय परिसरों, 36 विश्वविद्यालयों और संस्थानों और राज्य मुख्यालयों को प्रदान की गई है
- **कोर बैकबोन:** नेटवर्क बैकबोन पी.जी.सी.आई.एल., बी.एस.एन.एल. और रेलटेल से 10 जी.बी.पी.एस. लिंक को एकीकृत करता है, जो उच्च गति और लचीली कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है
- **स्वान एकीकरण:** 25 ज़िलों से जुड़ा है, जो राज्यव्यापी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को और मज़बूत करता है

यह बुनियादी ढाँचा सुरक्षित सरकारी संचार, उन्नत अनुसंधान और ई-गवर्नेंस सेवाओं की डिलीवरी में सुधार, जिससे छत्तीसगढ़ देशव्यापी हाई-स्पीड डिजिटल ग्रिड का हिस्सा बन गया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएँ

एनआईसी का अत्याधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) प्लेटफ़ॉर्म छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण बन गया है।

- **उपयोग:** 2019-2025 के बीच 3.5 लाख से ज़्यादा वीसी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री की प्रगति समीक्षाएं, नीति आयोग परामर्श, विभागीय समीक्षाएं और न्यायिक सुनवाई शामिल थीं
- **न्यायपालिका:** न्यायालय परिसर जेलों और अन्य स्थानों से मामलों की सुनवाई के लिए वीसी का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं, जिससे देरी और लागत कम होती है
- **मान्यता:** राज्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए पूर्वी क्षेत्र (2025) में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया

उच्च गति वाले नेटवर्क और उन्नत वीसी सेवाओं के संयोजन ने छत्तीसगढ़ को एक डिजिटल रूप से सशक्त राज्य के रूप में स्थापित किया है, जिससे वास्तविक समय में निर्णय लेने, बेहतर सेवा वितरण और शासन तक समावेशी पहुँच संभव हुई है।

पुरस्कार और सम्मान

छत्तीसगढ़ की आईसीटी-आधारित पहलों ने कृषि, शिक्षा, शासन और आईसीटी अवसंरचना के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है।

प्रमुख पुरस्कार:

- **2025** - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उत्कृष्टता: उत्कृष्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाओं के लिए पूर्वी क्षेत्र का प्रथम पुरस्कार; 3.5 लाख से अधिक सत्रों ने शासन समीक्षा, न्यायिक कार्यवाही और राष्ट्रीय परामर्श को सुगम बनाया
- **2023 – राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार:** क्रॉप डॉक्टर ऐप (आई.जी.के.वी., रायपुर) के लिए, जो एआई- आधारित फसल निदान और किसान सलाह को सक्षम बनाता है
- **2023 – एमबिलियनथ पुरस्कार:** एआई-संचालित स्कूल मूल्यांकन उपकरण, निकलर के लिए
- **2022 – सीएसआई एसआईजी ई-गवर्नेंस पुरस्कार:** टेलीप्रैक्टिस और ई-मानचित्र विज्ञान (भू-कृषि निगरानी) के लिए
- **2022 – आईएमसी डिजिटल पुरस्कार:** ई-प्रश्न और ई-उत्तर, विधायी प्रश्न प्रबंधन व विधानसभा की डिजिटल प्रणाली के लिए
- **2022 – डिजिटल प्रौद्योगिकी सभा पुरस्कार:** पीएमएस पोर्टल (पेंशन प्रबंधन) और सी.एस.ई.आर.सी. ई-याचिका प्रणाली के लिए

ये मान्यताएँ डिजिटल शासन में अग्रणी के रूप में छत्तीसगढ़ की भूमिका की पुष्टि करती हैं, जो कृषि, शिक्षा, विधायिका और बुनियादी ढाँचे में नवाचारों को आगे बढ़ा रही है।

अग्रिम दिशा

एनआईसी छत्तीसगढ़ डिजिटल शासन को गति दे रहा है। इसमें भूमि और वित्त प्रणालियों को सुव्यवस्थित करना, कृषि सेवाओं को मजबूत करना, स्वास्थ्य सेवा का डिजिटलीकरण करना और स्कूलों में ई-लर्निंग का विस्तार करना शामिल है। यह बेहतर शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म, डिजिटल हस्ताक्षर और डेटा-संचालित निर्णय लेने के माध्यम से नागरिक सेवाओं को भी बढ़ा रहा है—जिससे एक सहज, समावेशी, नागरिक-केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो रहा है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी छत्तीसगढ़ राज्य केंद्र
14,15,16 प्रशासनिक खंड, द्वितीय तल, महानदी भवन
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492002
ईमेल: sio-cg@nic.in फ़ोन: 0771-2221238

अहिल्यानगर, महाराष्ट्र

डिजिटल नवाचार के माध्यम से ई-गवर्नेंस में तेजी

संपादित : **सुषमा मिश्रा**

अहिल्यानगर डिजिटल शासन और आईसीटी-संचालित विकास में महाराष्ट्र के अग्रणी जिलों में से एक के रूप में उभरा है। पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक-केंद्रित सेवाएँ लाने के दृष्टिकोण से, जिले ने वास्तविक समय जल प्रबंधन प्रणालियों से लेकर घर-घर सरकारी सेवाओं की डिलीवरी तक, तकनीकी पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला को अपनाया है।

एआई-संचालित उपस्थिति प्रणालियों, ओपन डेटा प्लेटफ़ॉर्म, मोबाइल एप्लिकेशन और जीआईएस-आधारित निगरानी उपकरणों को एकीकृत करके, अहिल्यानगर इस बात में नए मानक स्थापित कर रहा है कि कैसे तकनीक ज़मीनी स्तर पर शासन को मज़बूत कर सकती है।

ऐतिहासिक रूप से,इस ज़िले का इतिहास 1494 ईस्वी से जुड़ा है, जब मलिक अहमद ने अहमदनगर को निज़ामशाही वंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। सदियों से, इसकी सीमाएँ विकसित होती रहीं, और अक्टूबर 2024 में, महारानी अहिल्याबाई होल्कर के सम्मान में ज़िले का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर रखा गया।

जिले में आईसीटी पहल

अहिल्यानगर जिला वेबसाइट

ahilyanagar.maharashtra.gov.in

आधिकारिक अहिल्यानगर जिला वेबसाइट, जो एस3वास फ्रेमवर्क पर निर्मित है, एक बहुभाषी, मोबाइल-अनुकूल पोर्टल है जो सरकारी सेवाओं और सूचनाओं के लिए वन-स्टॉप गेटवे के रूप में कार्य करता है।

यह बताता है:

- **इतिहास और विरासत:** जिले की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रदर्शन।
- **जनसांख्यिकी और शासन:** जनसंख्या, प्रशासनिक व्यवस्था और संसाधनों की विस्तृत जानकारी।

पवन रामलाल टेम्भुर्ने
वैज्ञानिक/ तकनीकी
सहायक - ए व डीआईओ
pr.tembhurne@nic.in

अहिल्यानगर डिजिटल शासन में अग्रणी बनकर उभरा है, जहाँ सेवाओं को तेज़, पारदर्शी और अधिक सुलभ बनाने के लिए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जलदूत की रीयल-टाइम वाटर टैंकर ट्रैकिंग, सेवादूत द्वारा प्रमाणपत्रों की घर-घर डिलीवरी, चेहरे से पहचान के साथ ए.ई.बी.ए.एस., सड़क सुरक्षा के लिए आई.आर.ए.डी. और ओपन डेटा प्लेटफ़ॉर्म जैसी पहल नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति जिले की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। नवाचार को जवाबदेही के साथ जोड़कर, जिला यह प्रदर्शित कर रहा है कि कैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) दैनिक शासन को बदल सकती है।

- **निविदाएँ और भर्ती:** अनुबंधों और रोज़गार के अवसरों पर पारदर्शी अपडेट।
- **नागरिक सेवाएँ:** प्रमाणपत्रों, कल्याणकारी योजनाओं, शिकायत निवारण और आवेदन ट्रैकिंग तक आसान पहुँच।
- **पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था:** पर्यटन स्थलों, त्योहारों और निवेश के अवसरों की जानकारी।

जी.आई.जी.डब्ल्यू. सुगम्यता मानकों के अनुरूप, यह पोर्टल समावेशिता, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित ई-गवर्नेंस सुनिश्चित करता है।

जलदूत

jaldoot.ahmednagar.gov.in

जलदूत पोर्टल, अहिल्यानगर की प्रमुख डिजिटल पहल है जो वास्तविक समय में टैंकर प्रबंधन के माध्यम से जल संकट से निपटने के लिए है। यह तकनीक और शासन को एक साथ जोड़कर यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी समुदायों तक पानी कुशल, पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से पहुँचे।

मुख्य विशेषताएँ:

- **डिजिटल अनुरोध प्रणाली:** ग्राम सेवक (गाँव) और उप-अभियंता (शहरी क्षेत्र) टैंकर अनुरोध ऑनलाइन जमा करते हैं।

एनआईसी आईसीटी गतिविधियों में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। इसने आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने और राज्य एवं केंद्र दोनों ई-गवर्नेंस कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे अहिल्यानगर में आयोजित कैबिनेट बैठक के लिए आईटी सहायता प्रदान करना। ई-ऑफिस, एआई-संचालित नवाचारों जैसे भाषिणी, चेहरा पहचान सक्षम जिला प्रशासन के साथ ए.ई.बी.ए.एस. और कई अन्य आईसीटी कार्यान्वयन में इसका योगदान इसकी उत्कृष्टता को दर्शाता है। मैं एनआईसी अहिल्यानगर को बधाई देता हूँ और सफलता की कामना करता हूँ। मैं भविष्य में और भी कई ई-गवर्नेंस पहलों की आशा करता हूँ।

डॉ. पंकज आशिया, आईएएस
जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, अहिल्यानगर

- **स्वचालित ऑर्डर जनरेशन:** अनुरोधों को स्वीकृत किया जाता है और टैंकर ऑर्डर तुरंत जनरेट किए जाते हैं।
- **रीयल-टाइम ट्रैकिंग:** टैंकर जीपीएस-सक्षम होते हैं, और अधिकारियों द्वारा एक मोबाइल ऐप के माध्यम से उनकी आवाजाही की निगरानी की जाती है।
- **कुशल प्रेषण:** खंड विकास अधिकारी शेड्यूलिंग और वितरण का समन्वय करते हैं।
- **नागरिक पहुँच:** निवासी टैंकरों के लिए आवेदन कर सकते हैं और समर्पित जलदूत मोबाइल ऐप के माध्यम से डिलीवरी को

ट्रैक कर सकते हैं।

अनुमोदन कार्यप्रवाह, जीपीएस ट्रैकिंग और नागरिक भागीदारी को एकीकृत करके, जलदूत ने जिले में जल संकट के प्रबंधन के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल ढांचा तैयार किया है।

जी.एम. सेवादूत

gmsevadoot.ahmednagar.gov.in

जी.एम. सेवादूत एक ई-गवर्नेंस पहल है जो प्रशिक्षित ग्राम-स्तरीय एजेंटों के माध्यम से सरकारी सेवाओं को सीधे नागरिकों के दरवाजे तक पहुँचाती है। यह प्लेटफ़ॉर्म सरकारी कार्यालयों में प्रत्यक्ष रूप से जाने की आवश्यकता को कम करता है, जिससे सुविधा, दक्षता और आवश्यक सेवाओं तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित होती है।।

यह कैसे काम करता है:

- **ऑनलाइन अपॉइंटमेंट:** नागरिक पोर्टल के माध्यम से निवास या आय प्रमाण पत्र जैसी सेवाएँ बुक कर सकते हैं।
- **जीएम सहायता:** एक ग्राम मंत्री या ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) नागरिक के घर जाकर दस्तावेज़ एकत्र करता है।
- **डिजिटल प्रसंस्करण:** आवेदनों का प्रसंस्करण संबंधित सरकारी पोर्टलों के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है।
- **होम डिलीवरी:** अंतिम डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र आवेदक के निवास पर डाक द्वारा भेजे जाते हैं।

प्रौद्योगिकी को अंतिम-मील सेवा वितरण के साथ जोड़कर, जीएम सेवादूत यह सुनिश्चित करता है कि शासन समावेशी, नागरिक-केंद्रित और वास्तव में सुलभ हो।

मुख्यमंत्री के 150 दिवसीय कार्यक्रम की पहल

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ज़िले ने प्रमुख ई-गवर्नेंस उपकरण लॉन्च किए, जिनमें शामिल हैं:

- **ज़िला वेबसाइट अपडेट:** अधिक पारदर्शिता के लिए आरटीआई एकीकरण के साथ उन्नत।
- **व्हाट्सएप चैटबॉट:** सरकारी सेवाओं तक त्वरित और उपयोगकर्ता-अनुकूल पहुँच प्रदान करना।
- **लुकर स्टूडियो डैशबोर्ड:** कलेक्टर को वास्तविक समय में ज़िले की गतिविधियों की निगरानी करने की सुविधा प्रदान करना।

▲ चित्र 3.2 : एनआईसी अहिल्यानगर ने 6 मई 2025 को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल बैठक में तकनीकी सहयोग दिया, जिसमें अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती और विरासत संरक्षण पर केंद्रित विकास योजनाएँ रेखांकित की गईं

ओपन डेटा पहल

data.gov.in पर एक मुख्य डेटा अधिकारी (सीडीओ) खाता बनाया गया है, जिससे जिला डेटासेट को खुले, मशीन-पठनीय प्रारूपों में प्रकाशित कर सकेगा। इससे पारदर्शिता, नवाचार और जनभागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

प्रमुख कार्यक्रम

जामखेड में कैबिनेट बैठक

महारानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में, महायुति मंत्रिमंडल ने 06 मई 2025 को उनके जन्मस्थान चोंडी, जामखेड में एक विशेष बैठक बुलाई। इस बैठक में एक दूरदर्शी शासक के रूप में उनकी विरासत को रेखांकित किया गया और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने में जिले की भूमिका पर ज़ोर दिया गया। इस बैठक के एजेंडे में एक व्यापक विकास पैकेज पर चर्चा शामिल थी, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया:

- ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार और संरक्षण।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विस्तार।
- अहिल्याबाई के समावेशी शासन मॉडल को प्रतिबिंबित करने के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं को सुदृढ़ बनाना।

▼ चित्र 3.1 : आई.आर.ए.डी. परियोजना के तहत, एनआईसी जिला केंद्र ने 32 पुलिस थानों, दो आरटीओ तथा अन्य कार्यालयों में 1,472+ कर्मचारियों को 131+ प्रशिक्षण प्रदान किए

मुख्यमंत्री का विशेष कार्यक्रम

6 मई 2025 को, महायुति मंत्रिमंडल ने महारानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में अपनी बैठक आयोजित की। इस बैठक के एजेंडे में एक व्यापक जिला विकास पैकेज को मंजूरी देना शामिल था, जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं और ऐतिहासिक स्मारकों का नवीनीकरण शामिल था।

एईबीएएस प्रशिक्षण

1 अगस्त 2025 को, जिला प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए उपस्थिति ट्रैकिंग को आधुनिक बनाने हेतु चेहरे से प्रमाणीकरण के साथ आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू की। प्रशिक्षण सत्र सुचारू रूप से अपनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और प्रॉक्सी उपस्थिति को न्यूनतम करने के लिए आयोजित किए गए।

मानव संपदा

कलेक्टर कार्यालय ने डिजिटल अवकाश प्रबंधन के लिए मानव संपदा लागू की है, जिससे कुशल ट्रैकिंग, अनुमोदन और रिकॉर्ड-कीपिंग संभव हो पाई है। यह जिले में कागज रहित प्रशासन और बेहतर मानव संसाधन दक्षता की दिशा में एक और कदम है।

अग्रिम दिशा

भविष्य की ओर देखते हुए, अहिल्यानगर का लक्ष्य नागरिक-केंद्रित सेवाओं का विस्तार करना, डेटा-साझाकरण पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना और स्वास्थ्य, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के लिए एआई, आईओटी और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों का अन्वेषण करना है। अधिकारियों की सतत क्षमता-वृद्धि के साथ-साथ बेहतर कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता के माध्यम से डिजिटल विभाजन को मिटाने के प्रयास भी प्रमुख रहेंगे। इन पहलों को आगे बढ़ाकर, ज़िला भारत में ई-गवर्नेंस के लिए एक डिजिटल रूप से सशक्त मॉडल के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत कर सकता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी अहिल्यानगर जिला केंद्र
पाँचवीं मंजिल, बी विंग, जिला कलेक्टर कार्यालय
सवेदी, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र - 414003
ईमेल: dio-ahn@nic.in, फोन: 0241 - 2343328

जामताड़ा, झारखंड

साइबर अपराध केंद्र से साइबर सुरक्षा केंद्र तक

संपादित : **सुषमा मिश्रा**

जामताड़ा, जो कभी साइबर अपराध के लिए कुख्यात था, अब प्रौद्योगिकी-आधारित परिवर्तन के माध्यम से एक शक्तिशाली बदलाव की कहानी लिख रहा है। 2001 से, एनआईसी जामताड़ा जिला केंद्र ऐसी डिजिटल पहलों का नेतृत्व कर रहा है जो सीधे शासन और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती हैं। ई-गवर्नेंस समाधानों से लेकर सार्वजनिक सेवा पोर्टलों तक, एनआईसी जामताड़ा ने जिला प्रशासन की डिजिटल रीढ़ को लगातार मजबूत किया है।

मजबूत आईसीटी अवसंरचना का निर्माण, नागरिक-केंद्रित अनुप्रयोगों की शुरुआत, और डिजिटल साक्षरता के लिए मंच तैयार करके, एनआईसी जामताड़ा ने जिले को डिजिटल भारत के दृष्टिकोण के साथ जोड़ा है। सभी 72 उच्च विद्यालयों में साइबर सुरक्षा क्लबों के शुभारंभ ने जामताड़ा की छवि को और भी नया रूप दिया है- साइबर अपराध केंद्र कहे जाने से लेकर साइबर सुरक्षा, डिजिटल जागरूकता और नवाचार के केंद्र के रूप में उभरने तक।

जिले में आईसीटी पहलें

स्कूलों में साइबर सुरक्षा क्लब

जामताड़ा के बहत्तर उच्च विद्यालयों में साइबर सुरक्षा क्लब स्थापित किए गए हैं ताकि ऑनलाइन खतरों के प्रति जागरूकता और लचीलापन पैदा किया जा सके। उपायुक्त रवि आनंद, आईएएस द्वारा उद्घाटन किए गए इस कार्यक्रम में प्रत्येक विद्यालय के नोडल अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे, जबकि छात्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। क्लबों का उद्देश्य छात्रों और नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना, उन्हें साइबर जोखिमों को पहचानने, रोकने और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के कौशल से लैस करना है, जिससे ज़िले में एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण का निर्माण हो सके।

आगंतुक प्रबंधन प्रणाली और जनता दरबार पोर्टल

ejmt.jharkhand.gov.in

आगंतुक प्रबंधन प्रणाली और जनता दरबार पोर्टल जामताड़ा के जिला, उपखंड, ब्लॉक और अंचल कार्यालयों में त्वरित और

संतोष कुमार घोष
वैज्ञानिक - बी व डीआईओ
ghosh.santosh@nic.in

कभी साइबर अपराध के लिए जाना जाने वाला जामताड़ा अब एनआईसी के नेतृत्व वाली डिजिटल पहलों के माध्यम से अपनी पहचान को नया रूप दे रहा है। 72 स्कूलों में साइबर सुरक्षा क्लबों से लेकर भूमि, स्वास्थ्य सेवा, शिकायत निवारण और नागरिक सेवाओं के पोर्टलों तक, यह ज़िला पारदर्शिता, साक्षरता और शासन को मज़बूत कर रहा है। ई-लाइब्रेरी और एन.आई.ई.एल.आई.टी संस्थान जैसी आगामी परियोजनाओं के साथ, जामताड़ा लगातार साइबर सुरक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण के केंद्र के रूप में बदल रहा है।

पारदर्शी शिकायत निवारण प्रदान करते हैं। उपायुक्त के मार्गदर्शन में एनआईसी द्वारा विकसित यह प्रणाली न नेटवर्क के माध्यम से संचालित होती है और जल्द ही इसे बेहतर क्षमता और मापनीयता के लिए राज्य डेटा केंद्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

आबकारी ई-लॉटरी पोर्टल

https://exciselottery.jharkhand.gov.in/

झारखंड आबकारी ऑनलाइन लॉटरी पोर्टल झारखंड आबकारी नियम, 2025 के तहत खुदरा शराब की दुकानों के निष्पक्ष आवंटन के लिए एक पारदर्शी और कुशल मंच है। लॉटरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर, यह विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, मैन्युअल हस्तक्षेप को समाप्त करता है, और आबकारी प्रशासन में जनता का विश्वास मजबूत करता है।

सामुदायिक पुस्तकालय पोर्टल

जामताड़ा भारत का एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ सभी 118 ग्राम पंचायतों में सुसज्जित सामुदायिक पुस्तकालय हैं। एनआईसी जामताड़ा द्वारा विकसित यह पोर्टल (jamtaradistrict.in) इन पुस्तकालयों को डिजिटल रूप से जोड़ता है, जिससे ग्रामीण नागरिकों को पुस्तकों, ई-लर्निंग संसाधनों और डिजिटल सामग्री तक पहुँच मिलती है, जिससे साक्षरता और ज़मीनी स्तर पर ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलता है।

ऑनलाइन कंप्यूटर दक्षता परीक्षाएँ

डिजिटल रूप से साक्षर कार्यबल तैयार करने के लिए, एनआईसी जामताड़ा संविदा या अनुकंपा के आधार पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर दक्षता परीक्षाएँ आयोजित करता है। ये मूल्यांकन सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक नए कर्मचारी के पास आधुनिक शासन और सेवा वितरण को सहयोग देने के लिए आवश्यक आवश्यक आईसीटी कौशल हों।

एनआईसी जामताड़ा जिला केंद्र जिला प्रशासन को निर्बाध सहायता प्रदान करता रहता है, जिससे जमीनी स्तर पर नागरिकों के लाभ के लिए सेवाओं का पारदर्शी, कुशल और शीघ्र वितरण सुनिश्चित होता है। प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, केंद्र भविष्य में और अधिक प्रभावी और नवीन डिजिटल पहलों के माध्यम से जिला प्रशासन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री रवि आनंद, आईएएस
उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट और
जिला कलेक्टर, जामताड़ा

एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (आई. आर.ए.डी/ ई-डार)

https://irad.parivahan.gov.in/

एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस, जिसे अब ई-विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डार) के रूप में जाना जाता है, को सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए जामताड़ा में लागू किया गया है। पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य और सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों से दुर्घटना संबंधी आँकड़े एकत्र करके, यह प्रणाली सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के

लिए सटीक विश्लेषण और साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेप को सक्षम बनाती है।

झारभूमि पोर्टल
https://jharbhoomi.jharkhand.gov.in/

झारभूमि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करता है। जामताड़ा में, यह पोर्टल एमआईएस, झारभूलगान, झारभूनक्शा, यू.एल.पी.आई.एन. और परिशोधन जैसे मॉड्यूल का समर्थन करता है, जिससे भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना, स्वचालित म्यूटेशन और राजस्व एवं पंजीकरण प्रणालियों के बीच सहज एकीकरण संभव हो पाता है।

नेक्स्ट जेन ई-हॉस्पिटल
https://nextgen.ehospital.gov.in/

नेक्स्ट जेन ई-हॉस्पिटल प्लेटफॉर्म को जामताड़ा के सदर अस्पताल में लागू किया गया है। वर्तमान में, पंजीकरण, ई-प्रिस्क्रिप्शन और प्रयोगशाला सेवाओं के लिए मॉड्यूल सक्रिय हैं, जो अस्पताल के कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करते हैं और तेज़, अधिक कुशल सेवा वितरण के माध्यम से रोगी देखभाल में सुधार करते हैं।

बीओआर परीक्षा पोर्टल
https://borexam.jharkhand.gov.in/

बीओआर पोर्टल झारखंड सरकार के कर्मचारियों के लिए विभागीय परीक्षाओं को सरल बनाता है। कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपनी स्थिति पर नज़र रख सकते हैं, और पोर्टल के माध्यम से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी, कुशल और सुलभ हो जाती है।

शस्त्र लाइसेंसों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एन.डी.ए.एल.-ए.एल.आई.एस.)
https://ndal-alis.gov.in/

एन.डी.ए.एल.-ए.एल.आई.एस. पोर्टल शस्त्र लाइसेंस और संबंधित परमिट जारी करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाता है। 29 सेवाएँ प्रदान करते हुए, यह व्यक्तियों, उद्यमियों और उद्योगों को सहायता प्रदान करता है, साथ ही भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" और व्यवसाय सुगमता पहलों को भी बढ़ावा देता है।

▲ चित्र 4.2 : साइबर सुरक्षा क्लब का उद्घाटन श्री रवि आनंद, आईएएस, उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट, जामताड़ा द्वारा किया गया

झारसेवा पोर्टल
https://jharsewa.jharkhand.gov.in/

झारसेवा एक नागरिक-अनुकूल पोर्टल है जो सर्विसप्लस ढांचे पर आधारित है और आय, जाति, निवास और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण पत्र जैसी सेवाएँ प्रदान करता है। आवेदन ऑनलाइन, सीएससी के माध्यम से, या पंचायत स्वयं सेवकों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं, और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सीधे नागरिकों को वितरित किए जाते हैं, जिससे पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होती है।

वी.वी.आई.पी. कार्यक्रमों के लिए आईसीटी सहायता

एनआईसी जामताड़ा ने प्रमुख वी.वी.आई.पी. कार्यक्रमों के लिए आईसीटी सहायता प्रदान की है, जिसमें झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेलुवा में एक विद्युत संयंत्र के उद्घाटन के दौरान दो-तरफ़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी शामिल है। इस सहायता से उच्च-स्तरीय कार्यक्रमों का सुचारू संचालन सुनिश्चित होता है।

▼ चित्र 4.1 : डिजिटल रूप से सक्षम सामुदायिक पुस्तकालय में पढ़ते छात्र। जामताड़ा भारत का एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ सभी 118 ग्राम पंचायतों में ऐसे पुस्तकालय हैं, जो एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल द्वारा संचालित हैं

चुनावों के लिए आईसीटी सहायता

चुनावों के दौरान, एनआईसी जामताड़ा ने पूरी तरह से आईसीटी सहायता प्रदान की है, जिसमें मतदान दल यादृच्छिकीकरण, वाहन और सामग्री प्रबंधन, पुलिस कर्मियों का आवंटन, पर्यवेक्षक और एनकोर पोर्टल, ई-शपथपत्र, ई.टी.पी.बी.एम.एस., सी-विजिल, ईएमएस, जब्ती प्रबंधन और मतदान दिवस की लाइव निगरानी जैसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लागू किया गया है। इन प्रणालियों ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की है।

निकनेट और एनकेएन सेवाएँ

एनआईसी जामताड़ा, जिला प्रशासन और सरकारी कार्यालयों को चौबीसों घंटे आईसीटी और नेटवर्क सहायता प्रदान करता है। यह शैक्षणिक संस्थानों को एनकेएन कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है, जिससे शैक्षणिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए डिजिटल संसाधनों तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित होती है।

अग्रिम दिशा

एनआईसी जामताड़ा डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाते हुए ई-लाइब्रेरी, एन.आई.ई.एल.आई.टी. संस्थान और पॉडकास्ट रूम जैसी परिवर्तनकारी परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। यह ई-लाइब्रेरी डिजिटल संसाधनों तक पहुँच का विस्तार करेगी, ई-लर्निंग को बढ़ावा देगी और जामताड़ा को साइबर अपराध केंद्र से साइबर सुरक्षा केंद्र में बदलने की दिशा में मज़बूती प्रदान करेगी। प्रस्तावित एन.आई.ई.एल.आई.टी. संस्थान आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रदान करेगा - एससी/एसटी छात्रों के लिए निःशुल्क और अन्य के लिए किफ़ायती - जिससे स्थानीय युवाओं के लिए समावेशी अवसर सुनिश्चित होंगे। विभिन्न विभागों में आईसीटी सेवाओं को लागू करके, एनआईसी जामताड़ा एक मज़बूत डिजिटल बुनियादी ढाँचा तैयार कर रहा है और जिले को शासन और विकास के लिए उभरती तकनीकों का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहा है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी जामताड़ा जिला केंद्र
प्रथम तल, कलेक्ट्रेट कार्यालय
जामताड़ा, झारखंड - 815351
ईमेल: dio-jmt@nic.in, फ़ोन: 6261066328

टोंक, राजस्थान

उन्नत आईसीटी और एआई समाधानों के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व

संपादित : **विनोद कुमार गर्ग**

एनआईसी टोंक ने एक मज़बूत आईसीटी बुनियादी ढाँचा तैयार किया है, जिससे विभागों को तकनीक-संचालित समाधान और ई-गवर्नेंस पहलों से सक्षम बनाया गया है, जिनसे सेवा वितरण, पारदर्शिता और नागरिक पहुँच में सुधार हुआ है। एक प्रमुख उपलब्धि है पढाई विथ एआई, जो एक एआई-संचालित वेब प्लेटफ़ॉर्म है जो 353 स्कूलों में 10वीं कक्षा के गणित शिक्षण का समर्थन करता है।

साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्रमाणीकरण और डेटा-संचालित योजना में विशेषज्ञता के साथ, एनआईसी टोंक कुशल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में ज़िले के परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है।।

जिले में आईसीटी पहलें

पढ़ाई विद एआई

पढ़ाई विद एआई एक एआई-आधारित व्यक्तिगतट्यूशन पहल है जिसकी संकल्पना और क्रियान्वयन जिला प्रशासन, टोंक द्वारा,एनआईसी टोंक के सहयोग से किया गया है। लक्ष्य 2025 अभियान के तहत शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में कक्षा 10 की आरबीएसई बोर्ड परीक्षा के परिणामों में सुधार करना है।

मुख्य विशेषताएँ :

- टोंक जिले के सभी 353 सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का कवरेज
- कक्षा 10 के 11,977 छात्रों को शामिल किया गया
- द्विभाषी सहायता (हिंदी/अंग्रेजी) के साथ एआई-संचालित व्यक्तिगत ट्यूशन
- हिंदी माध्यम के स्कूलों पर विशेष ध्यान, जो सबसे बड़ा लाभार्थी समूह है
- स्कूल, ब्लॉक और जिला स्तर पर व्यापक विश्लेषण डैशबोर्ड
- 6-सप्ताह के अभियान के रूप में संचालित (जनवरी-फरवरी 2025)

सुशील कुमार अग्रवाल
वैज्ञानिक - सी व डीआईओ
agrawal.sushil@nic.in

एनआईसी टोंक ने पढ़ाईविदएआई, आई.आर.ए.डी आधारित एंबुलेंस पुनर्स्थापन, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, ईएमएस और डी.आई. एल.आर.एम.पी जैसी नवाचारपूर्ण आईसीटी पहलों के माध्यम से टोंक जिले के डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व किया है। इन पहलों ने पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार किया है। नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित एनआईसी टोंक, डेटा-संचालित, समावेशी और नागरिक-केंद्रित शासन के माध्यम से डिजिटल इंडिया की दृष्टि को आगे बढ़ा रहा है।

- कक्षा 10 के गणित के परिणामों में अभूतपूर्व सुधार हुआ - राज्य के औसत और पिछले जिले के प्रदर्शन दोनों को पार करते हुए।
- इस पहल को व्यापक मान्यता मिली है, जिसमें नीति आयोग के अधिकारियों की सराहना भी शामिल है और प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है जैसे:
- राष्ट्रीय संगोष्ठी, विज्ञान भवन, नई दिल्ली (अगस्त 2025)
- विकसित भारत प्रदर्शन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली (सितंबर 2025) - माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और वरिष्ठ सरकारी नेतृत्व द्वारा सराहना की गई।

बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बीएएस)

एनआईसी टोंक राजस्थान में बीएएस के लिए राज्य नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करता है और सरकारी कार्यालयों में इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। इसकी ज़िम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं:

- हितधारक समन्वय और निगरानी
- बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा प्रदान करना
- उपस्थिति रिपोर्ट तैयार करना और उसका विश्लेषण करना
- डिवाइस की स्थापना और कॉन्फ़िगरेशन की देखरेख करना

आई.आर.ए.डी

टोंक भारत का पहला जिला बन गया है जिसने एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (आई.आर.ए.डी) का उपयोग करके दुर्घटनाग्रस्त ब्लैक स्पॉट के पास 108 एम्बुलेंसों को पुनः स्थापित किया है।

- आई.आर.ए.डी विश्लेषण के माध्यम से चार उच्च-जोखिम वाले स्थलों की पहचान की गई

पढ़ाई विथ एआई ने टोंक के स्कूलों में एआई-संचालित उपकरणों के माध्यम से गणित सीखने में क्रांति ला दी है। यह अभिनव प्रयास शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षकों को सशक्त बनाने और छात्रों के परिणामों को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए एनआईसी टोंक और उनकी समर्पित टीम की सराहना करता हूँ और कामना करती हूँ कि वे शिक्षा उत्कृष्टता और डिजिटल नवाचार को आगे बढ़ाने में निरंतर सफलता प्राप्त करते रहें।

श्रीमती कल्पना अग्रवाल, आईएएस
जिला कलेक्टर, टोंक

- एम्बुलेंस प्रतिक्रिया समय घटाकर 3-5 मिनट कर दिया गया (पहले 15-20 मिनट लगते थे)
- अतिरिक्त वाहनों के बिना, डेटा-आधारित योजना के माध्यम से दक्षता प्रदर्शित करते हुए, यह उपलब्धि हासिल की गई
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एम.ओ.आर.टी.एच) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त

चुनाव प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)

एनआईसी टोंक पूरे जिले में चुनाव कार्यों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चुनाव प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के माध्यम से, यह कार्मिकों की तैनाती, मतदान दिवस समन्वय, मतगणना और परिणामों के प्रसार की देखरेख करता है। इसके अलावा, एनआईसी टोंक, चुनाव आयोग के अनुप्रयोगों को प्रभावी ढंग से सुगम और एकीकृत करके, चुनाव पूर्व और चुनाव पश्चात की प्रक्रियाओं को निर्बाध सुनिश्चित करता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ती है।

डीआईएलआरएमपी

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डी.आई.एल.आर.एम.पी) के अंतर्गत, जिले की सभी नौ तहसीलों के भूमि अभिलेखों को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। नागरिक अब तहसील कार्यालयों, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अधिकार अभिलेखों तक आसानी से पहुँच सकते हैं, जिससे पारदर्शिता, दक्षता और सेवा वितरण में आसानी सुनिश्चित होती है।

अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों के दौरान आईसीटी सहायता

एनआईसी टोंक ने माननीय प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के दौरों के दौरान सफलतापूर्वक आईसीटी सहायता प्रदान की है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है:

- सुरक्षित संचार नेटवर्क
- रीयल-टाइम निगरानी प्रणाली
- बेहतर कनेक्टिविटी वाले आईसीटी-सक्षम सुरक्षित घर
- प्रोटोकॉल निष्पादन हेतु निर्बाध समन्वय

एनआईसी टोंक ने कई अन्य प्रमुख ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो सेवा वितरण को सुदृढ़ बनाती हैं और पारदर्शिता में सुधार लाती हैं। इनमें एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) और गर्भावस्था एवं शिशु ट्रैकिंग प्रणाली (पीसीटीएस) शामिल हैं। ई-परिवहन (वाहन और सारथी), शस्त्र लाइसेंस जारी करने की प्रणाली और नागरिक पंजीकरण प्रणाली (पहचान) जैसी पहलों के माध्यम से नागरिक

▲ चित्र 5.2 :पढ़ाई विद एआई कक्षा

सेवाओं को और अधिक सुव्यवस्थित किया गया है। शैक्षिक और संस्थागत सुधारों को संस्था आधार, शाला दर्पण, निजी स्कूल पोर्टल और ज्ञान संकल्प द्वारा समर्थित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एनआईसी टोंक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), ई-पंजीकरण और ई-ग्राम के माध्यम से कल्याणकारी और प्रशासनिक सेवाओं को बढ़ाया है, जिससे प्रमुख क्षेत्रों में डिजिटल पहुँच और दक्षता सुनिश्चित हुई है।

पुरस्कार और सम्मान

- **2025:** जिला प्रशासन द्वारा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (डीआईओ) को "पढ़ाईविदएआई" के विकास और कार्यान्वयन के लिए सम्मानित किया गया।
- **2025:** माननीय उपमुख्यमंत्री श्री प्रेम चंद बैरवा द्वारा आईसीटी नवाचार में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया।
- **2020, 2021, 2024:** उत्कृष्ट आईटी पहलों के लिए जिला स्तरीय पुरस्कार

अग्रिम दिशा

अपनी प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, एनआईसी टोंक आईसीटी-सक्षम सेवाओं के बारे में जागरूकता और अपनाने को बढ़ावा देना जारी रखेगा, और डिजिटल इंडिया विज़न के साथ अपने संरेखण को और मज़बूत करेगा। आगे का ध्यान सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने, नागरिकों को सुलभ डिजिटल समाधानों से सशक्त बनाने और वैश्विक डिजिटल लीडर बनने की दिशा में भारत की यात्रा में योगदान देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर है।

एनआईसी टोंक ने जिला प्रशासन द्वारा 'पढ़ाई विद एआई' पहल के सफल विकास और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने जिले भर के छात्रों के एआई-संचालित उपकरणों के माध्यम से गणित से जुड़ने के तरीके को बदल दिया है। एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने से लेकर सभी स्कूलों में सुचारू तैनाती सुनिश्चित करने तक, एनआईसी की तकनीकी विशेषज्ञता और समर्पण सराहनीय रहा है। मैं अपने शिक्षा-केंद्रित डिजिटल नवाचार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए डीआईओ एनआईसी टोंक के प्रयासों की तहे दिल से सराहना करती हूँ और कामना करती हूँ कि वे जिले भर में प्रभावशाली ई-गवर्नेंस और आईसीटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में निरंतर सफलता प्राप्त करें।

डॉ. सौम्या झा, आईएएस
निदेशक, चिकित्सा (आईईसी), राजस्थान और
पूर्व जिला कलेक्टर, टोंक

▼ चित्र 5.1 : नीति आयोग की प्रस्तुति में डॉ. सौम्या झा (आईएएस), श्रीमती कल्पना अग्रवाल (आईएएस) और एनआईसी के अधिकारी

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी टोंक जिला केंद्र
कलेक्ट्रेट परिसर, बहिर कॉलोनी
टोंक, राजस्थान - 304001
ईमेल: dio-tnk@nic.in, फ़ोन: 01432-244344

नशा मुक्ति रजिस्ट्री पोर्टल

पंजाब में नशीली दवाओं की चोरी पर नकेल कसना

संपादित : **विनोद कुमार गर्ग**

पंजाब लंबे समय से ओपिओइड की लत के खिलाफ भारत के संघर्ष में अग्रणी रहा है। इस संकट का सामना करने के लिए, राज्य ने आउटपेशेंट ओपिओइड सहायता प्राप्त उपचार (ओ.ओ.ए.टी) केंद्रों का एक व्यापक नेटवर्क बनाया है और सुरक्षित, किफ़ायती और निरंतर उपचार प्रदान करने के लिए निजी सुविधाओं के साथ साझेदारी की है। इन केंद्रों को आशा के केंद्र के रूप में डिज़ाइन किया गया था - जहाँ मरीज़ निर्भरता से उबरने की कठिन यात्रा शुरू कर सकते थे।

लेकिन इस प्रगति के साथ-साथ कई छिपी चुनौतियाँ भी उभरीं। जिन दवाओं का उद्देश्य इलाज करना था, वे चोरी और हेराफेरी की चपेट में थीं। कुछ मामलों में, मरीज़ों को दोहरी पहचान के तहत नामांकित किया गया था; अन्य मामलों में, मैन्युअल रिकॉर्ड-कीपिंग में खामियों के कारण आपूर्ति श्रृंखला में लीकेज हो गई। फर्जी लाभार्थियों, फर्जी नामांकनों और बिना निगरानी वाली दवाओं के भंडार ने व्यवस्था को कमज़ोर कर दिया, जिससे जवाबदेही पर संदेह पैदा हुआ और मरीज़ों और नागरिकों, दोनों का भरोसा कमज़ोर हुआ।

यह स्पष्ट था कि केवल उपचार ही पर्याप्त नहीं था - राज्य को अपने नशामुक्ति तंत्र की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए एक डिजिटल सुरक्षा कवच की आवश्यकता थी। पंजाब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने, एनआईसी पंजाब के सहयोग से, एक ऐसे नवाचार के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की जो शासन और तकनीक को जोड़ता है: ड्रग डी-एडिक्शन रजिस्ट्री पोर्टल (डी.डी.आर.पी.)। आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, एआई-संचालित चेहरा पहचान और वास्तविक समय सूची प्रबंधन को शामिल करके, डी.डी.आर.पी. यह सुनिश्चित करता है कि दवाएँ केवल वास्तविक मरीजों तक पहुँचें, हर रिकॉर्ड पारदर्शी हो, और हर खुराक का हिसाब हो।

विवेक वर्मा
उप महानिदेशक व एसआईओ
vivek.verma@nic.in

धर्मेश कुमार
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एएसआईओ
dharmesh.sharma@nic.in

संजय पुरी
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
sanjay.puri@nic.in

पंजाब का नशा मुक्ति रजिस्ट्री पोर्टल (डी.डी.आर.पी.) राज्य की ओपिओइड की लत के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी छलांग है। आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, एआई-संचालित चेहरा पहचान, और वास्तविक समय दवा इन्वेंट्री प्रबंधन को एकीकृत करते हुए, डी.डी.आर.पी. फर्जी नामांकन को समाप्त करता है, दवा चोरी को रोकता है, और पारदर्शी उपचार वितरण सुनिश्चित करता है। एकीकृत डिजिटल रजिस्ट्री रोगियों को केंद्र-दर-केंद्र पहुँच प्रदान करती है और प्रशासकों को विसंगतियों की तुरंत निगरानी करने में सक्षम बनाती है। प्रौद्योगिकी को शासन के साथ मिलाकर, डी.डी.आर.पी. जवाबदेही को मजबूत करता है, सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा करता है, और पंजाब के नशा मुक्ति पारिस्थितिकी तंत्र में नए सिरे से विश्वास का निर्माण करता है।

यह पहल एक सॉफ्टवेयर प्रणाली से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। यह डिजिटल शासन की शक्ति के माध्यम से विश्वास बहाल करने, संसाधनों की सुरक्षा करने और व्यसन के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत करने की प्रतिबद्धता है।

चुनौती

हालाँकि पंजाब ने बाह्य-रोगी ओपिओइड सहायता उपचार (ओ.ओ.ए.टी.) केंद्रों और निजी सुविधाओं के एक नेटवर्क में निवेश किया है, लेकिन प्रणालीगत कमियों के कारण यह कार्यक्रम कमज़ोर पड़ गया है:

- **चोरी और हेराफेरी :** मरीज़ों के लिए बनी दवाइयाँ अक्सर कमज़ोर आपूर्ति नियंत्रण के कारण अवैध बाज़ार में लीक हो जाती थीं।
- **नकली और दोहरा नामांकन :** फर्जी लाभार्थी, जाली पहचान और कई पंजीकरण, देखभाल प्रदान किए बिना संसाधनों का दुरुपयोग करते थे।
- **मैन्युअल और खंडित डेटा :** कागज़-आधारित रजिस्टर और अलग-अलग रिकॉर्ड के कारण दोहराव, देरी और खराब दृश्यता होती थी।
- **मरीज़ों की सीमित पहुँच :** मरीज़ों को एक ही केंद्र से बाँध दिया जाता था, और अगर वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती थीं, तो इलाज की निरंतरता टूट जाती थी।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग का खतरा हमारे समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक गंभीर चुनौती है। पंजाब ने नशा मुक्ति केंद्रों पर नशीली दवाओं के वितरण को सुरक्षित करने के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और एआई-सक्षम चेहरा पहचान जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाकर एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। नशा मुक्ति रजिस्ट्री पोर्टल (डी.डी.आर.पी.) एक अनुकरणीय पहल है जो न केवल चोरी को रोकती है बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर रोगी देखभाल भी सुनिश्चित करती है। यह नवाचार जटिल सामाजिक मुद्दों के समाधान में डिजिटल शासन की शक्ति को प्रदर्शित करता है और पूरे देश में अनुकरण के लिए एक आदर्श के रूप में खड़ा है। मैं एनआईसी पंजाब और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक स्वस्थ और नशा मुक्त समाज के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में उनकी प्रतिबद्धता के लिए बधाई देता हूँ।

श्री कुमार राहुल, आईएएस
प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

- **कमज़ोर जवाबदेही :** वास्तविक समय की निगरानी के बिना, विसंगतियाँ केवल आवधिक ऑडिट के दौरान ही पता चलती थीं।

समाधान

ड्रग डी-एडिक्शन रजिस्ट्री पोर्टल (डी.डी.आर.पी.) डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोण के माध्यम से इन समस्याओं का सीधे समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया:

- आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके सुरक्षित पहचान जाँच, जिसे एआई-संचालित फेस रिकग्निशन और जियोफेंसिंग द्वारा सुदृढ़ किया गया है।
- ई-औषधि के साथ सहज एकीकरण, वास्तविक समय में इन्वेंट्री प्रबंधन सुनिश्चित करता है और दवाओं के रिसाव को रोकता है।
- पूरे राज्य में एक एकीकृत डिजिटल रजिस्ट्री जो दोहराव को दूर करती है और पारदर्शी रोगी रिकॉर्ड बनाए रखती है।
- क्रॉस-सेंटर उपचार लचीलापन, जिसके तहत मरीज किसी भी उपलब्ध स्टॉक वाले केंद्र से दवा प्राप्त कर सकते हैं — इससे सुविधा बढ़ती है और उपचार छोड़ने की संभावना घटती है।
- स्वचालित डैशबोर्ड और अलर्ट जो प्रशासकों को खपत, असंगतियों और स्टॉक की गतिविधियों के बारे में लाइव जानकारी देते हैं।

साथ मिलकर, ये विशेषताएँ डी.डी.आर.पी. को केवल एक निगरानी उपकरण से कहीं अधिक में बदल देती हैं - यह एक डिजिटल ढाल बन जाती है जो संसाधनों की सुरक्षा करती है, जवाबदेही का निर्माण करती है, और नशामुक्ति प्रणाली में रोगी के विश्वास को मजबूत करती है।

डी.डी.आर.पी. के पीछे की प्रौद्योगिकियाँ

डी.डी.आर.पी. का मूल एक सुरक्षित, स्केलेबल और किफायती आर्किटेक्चर है, जिसे ओपन-सोर्स तकनीकों से विकसित किया गया है और राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ एकीकृत किया गया है। इसके प्रत्येक घटक को दो प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है - मरीज की सुरक्षा और प्रणाली की जवाबदेही।

- **ओपन-सोर्स आधार :** पीएचपी 8.3 और पोस्टग्रेएसक्यूएल 14.4 का उपयोग करके विकसित, डी.डी.आर.पी. हल्का, मापनीय और किफायती है, जिससे इसका रखरखाव और विस्तार करना आसान हो जाता है।
- **आधार डेटा वॉल्ट :** संवेदनशील पहचान जानकारी सुरक्षित रूप से संग्रहीत की जाती है, जिससे गोपनीयता दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित होता है और रोगी डेटा के दुरुपयोग को रोका जा सकता है।

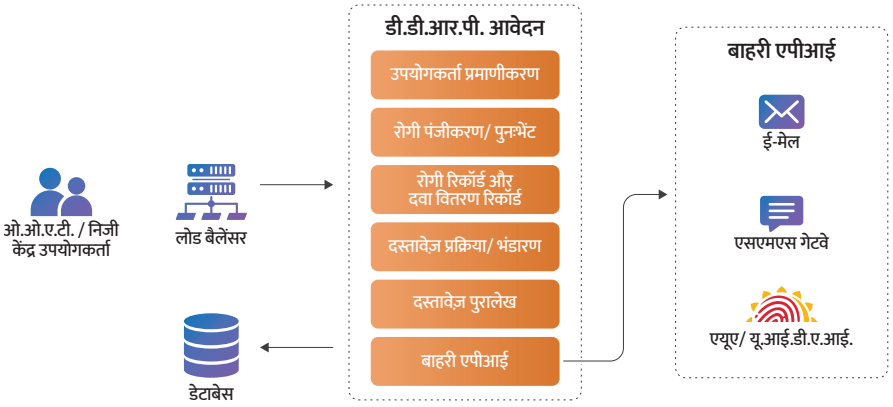

▲ चित्र 6.2 **डी.डी.आर.पी. एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर**

- **एआई/एमएल-सक्षम चेहरा प्रमाणीकरण :** एक मोबाइल एप्लिकेशन चेहरे की पहचान और जियोफेंसिंग का उपयोग करता है, यह सत्यापित करता है कि रोगी उपचार के दौरान केंद्र में शारीरिक रूप से मौजूद हैं।
- **ई-औषधि के साथ एकीकरण :** पंजाब के दवा आपूर्ति श्रृंखला प्लेटफ़ॉर्म से सीधे जुड़कर, डी.डी.आर.पी. रोगी वितरण रिकॉर्ड को वास्तविक समय में दवा इन्वेंट्री से जोड़ता है।
- **स्वचालित डिजिटल वर्कफ़्लो :** नामांकन से लेकर दवा वितरण तक, प्रक्रियाओं को डिजिटल किया जाता है ताकि मैनुअल रजिस्टरों की जगह ली जा सके, जिससे त्रुटियाँ कम हों और सेवा वितरण में तेज़ी आए।
- **रीयल-टाइम डैशबोर्ड और विश्लेषण :** प्रशासकों को केंद्रों में दृश्यता मिलती है, जिससे तेज़ी से निर्णय लेने और विसंगतियाँ दिखाई देने पर सक्रिय हस्तक्षेप करने में मदद मिलती है।

यह तकनीकी ढांचा सुनिश्चित करता है कि डी.डी.आर.पी. केवल एक निगरानी उपकरण नहीं है, बल्कि एक जीवंत प्रणाली है - निरंतर अद्यतन, स्व-सुधार, और सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन की उभरती ज़रूरतों के अनुकूल।

उपलब्धियाँ और सकारात्मक प्रभाव

डी.डी.आर.पी. ने पंजाब के नशामुक्ति कार्यक्रम को एक पारदर्शी, डिजिटल-प्रथम प्रणाली से मैन्युअल कमियों को दूर करके बदल दिया है।

- **सुरक्षित उपचार** - आधार + एआई जाँच सुनिश्चित करती है कि केवल वास्तविक रोगियों को ही दवाएँ मिलें।
- **कोई चोरी नहीं** - ई-औषधि के साथ रीयल-टाइम समन्वय आपूर्ति श्रृंखला में रिसाव को रोकता है।
- **रोगी सुविधा** - क्रॉस-सेंटर पहुँच ड्रॉपआउट को कम करती है और निरंतरता में सुधार करती है।
- **दक्षता** - डिजिटल वर्कफ़्लो नामांकन और वितरण को तेज़ करता है, जिससे प्रतीक्षा समय कम होता है।
- **जवाबदेही** - डैशबोर्ड और अलर्ट प्रशासकों के लिए रीयल-टाइम दृश्यता प्रदान करते हैं।
- **बेहतर योजना** - केंद्रीकृत डेटा पूर्वानुमान और साक्ष्य-आधारित नीति को सक्षम बनाता है।

संक्षेप में, डी.डी.आर.पी. डिजिटल शासन की शक्ति के माध्यम से दवाओं की सुरक्षा करता है, विश्वास का निर्माण करता है और रोगी के परिणामों में सुधार करता है।

अग्रिम दिशा

डी.डी.आर.पी. की सफलता पंजाब के प्रौद्योगिकी-सक्षम जन स्वास्थ्य के व्यापक दृष्टिकोण की दिशा में पहला कदम मात्र है। आगे बढ़ते हुए, राज्य की योजना दवा की मांग के पूर्वानुमान के लिए पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण के साथ प्रणाली को मज़बूत करने की है, जिससे आवश्यक दवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। आधार-आधारित और एआई-संचालित प्रमाणीकरण ढाँचे का विस्तार अन्य स्वास्थ्य सेवाओं तक भी किया जाएगा जहाँ पहचान सत्यापन और जवाबदेही महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकरण से अंतर-संचालनीयता और देखभाल की निरंतरता में और वृद्धि होगी, जबकि भविष्य के उन्नयन में परामर्श सत्रों पर नज़र रखना, रोग की पुनरावृत्ति की निगरानी और उपचार को समग्र बनाने के लिए मनोसामाजिक सहायता शामिल हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब का लक्ष्य डी.डी.आर.पी. को अन्य राज्यों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में स्थापित करना है, यह प्रदर्शित करते हुए कि कैसे डिजिटल शासन संसाधनों की सुरक्षा कर सकता है, रोगी परिणामों में सुधार कर सकता है, और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में विश्वास बहाल कर सकता है।

▼ चित्र 6.1 **मरीजों का पंजीकरण माह एवं वर्षवार**

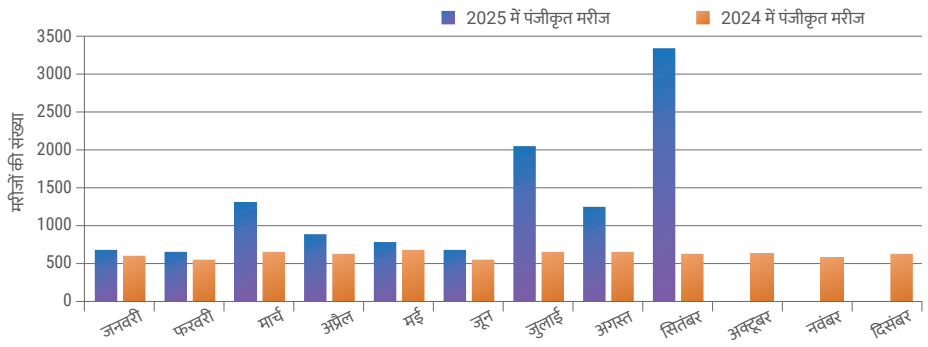

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी पंजाब राज्य केंद्र
कमरा संख्या 31, पंजाब सिविल सचिवालय
सेक्टर-1, चंडीगढ़ - 160001
ईमेल: sio-punjab@nic.in, फ़ोन: 0172-2747357

जिज्ञासा

डिजिटल इंडिया के लिए एक एआई-संचालित सहायिका

संपादित : **निस्सी जॉर्ज**

डिजिटल क्रांति अब भारत के हर कोने को छू रही है। लाखों सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन हैं, जो पारदर्शिता, समावेशन और व्यापक पहुँच प्रदान कर रही हैं। फिर भी, नागरिकों को अभी भी बिखरे हुए पोर्टल, जटिल यूआई/ यूएक्स (उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस/ अनुभव) और ऐसी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है जो सरल नागरिक कार्यों को लंबी और अक्सर निराशाजनक यात्रा में बदल देती हैं।

'जिज्ञासा' कुछ हद तक इस कठिनाई को हल करती है। डिजिटल इंडिया के लिए एआई-सशक्त सहायिका के रूप में, यह एक ऐसा प्लग-इन संवादात्मक परत है जो किसी भी सरकारी वेबसाइट या ऐप के साथ एकीकृत हो जाता है। उपयोगकर्ता सामान्य भाषा में बोलते हैं; जिज्ञासा उनके इरादे को समझती है, जवाब ढूंढती है या उन्हें सीधे सही फॉर्म या पेज तक पहुँचाती है, और भाषिनी जैसी सेवाओं के ज़रिए तुरंत अनुवाद भी कर सकती है, जिससे पूरी बातचीत एक शांत, निर्देशित संवाद में बदल जाती है।

विशेषताएँ और क्षमताएँ

- **आसान एकीकरण:** एपीआई कॉल के माध्यम से मौजूदा सरकारी वेबसाइटों में आसानी से जुड़ जाता है।
- **अनुकूलनीय एआई मॉडल:** इसे विभिन्न उपयोगों के लिए अलग-अलग एआई मॉडल का उपयोग करने के लिए ढाला जा सकता है।
- **बहुभाषी समर्थन:** यह कई भाषाओं को सपोर्ट करता है और इसमें भाषिनी जैसी अनुवाद सेवाओं को जोड़ने का विकल्प भी है।

सपना कपूर
उप. महानिदेशक व एसआईओ
sapna.kapoor@nic.in

स्नेहा लोटाणकर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
sneha.nl@nic.in

गंगाशंकर सिंह
वैज्ञानिक - बी
sg.indra@nic.in

भारत ने किफायती ई-गवर्नेंस समाधानों में अपनी वैश्विक नेतृत्व क्षमता साबित की है, फिर भी नागरिकों को अक्सर ऐसे इंटरफेस से जूझना पड़ता है जो सार्थक और मार्गदर्शित संवाद प्रदान नहीं कर पाते। जिज्ञासा इस परिदृश्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है - यह एक सहज, एआई-संचालित, बहुभाषी संवाद परत है जिसे मौजूदा ई-गवर्नेंस प्रणालियों में आसानी से जोड़ा जा सकता है। यह जटिल प्रणालियों को सहज, मानव-केंद्रित अनुभवों में बदल देती है, जहाँ उपयोगकर्ता केवल पूछते हैं और सीधे संबंधित अनुभागों तक पहुँच जाते हैं। जिज्ञासा के साथ, डिजिटल शासन न केवल सुलभ बनता है, बल्कि अत्यंत सहज, समावेशी और सशक्त भी हो जाता है।

- **फीडबैक-आधारित प्रशिक्षण:** वास्तविक उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया के माध्यम से लगातार बेहतर होता रहता है।
- **सीपीयू और जीपीयू वेरिएंट:** यह सीपीयू और जीपीयू दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपलब्ध है।
- **अनुकूलनीय चैटबॉट यूआई और थीम:** इसका डायनामिक चैटबॉट इंटरफ़ेस किसी भी एप्लिकेशन या वेबसाइट के विशिष्ट स्वरूप और अनुभव से मेल खाने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर का प्रवाह

'जिज्ञासा' के मूल में ध्यान से डिज़ाइन किया गया एक इंटेलिजेंस पाइपलाइन है, जिसे पाँच शक्तिशाली स्तंभों के माध्यम से समझा जा सकता है जो सामान्य प्रश्नों को अर्थपूर्ण, निर्देशित अनुभवों में बदल देते हैं।

विशेष सिमेंटिक खोज

पारंपरिक कीवर्ड-आधारित खोज के विपरीत, जिज्ञासा सिमेंटिक इंटेलिजेंस (अर्थ संबंधी बुद्धिमत्ता) डालती है जो कीवर्ड संकेतों को गहरी प्रासंगिक समझ के साथ जोड़ती है। उपयोगकर्ता के पास अपनी ज़रूरतों के अनुसार कीवर्ड खोज, सिमेंटिक खोज, या दोनों को चुनने की स्वतंत्रता है। यह समायोजित किए जा सकने वाले वज़न के साथ डोमेन-विशिष्ट कीवर्ड्स और सूक्ष्म अर्थों को संतुलित करता है, इरादे, संबंधों और संदर्भ को पकड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि अस्पष्ट या अव्यवस्थित प्रश्नों का भी सटीक और प्रासंगिक परिणाम के साथ समाधान हो।

एआई-आधारित पुनर्वर्गीकरण

एक बार संभावित परिणाम प्राप्त होने के बाद, जिज्ञासा एडवांस्ड पुनर्वर्गीकरण मॉडल लागू करती है। प्रत्येक परिणाम को यह निर्धारित करने के लिए स्कैन और पुनः-मूल्यांकन किया जाता है कि क्या वह वास्तव में प्रश्न का उत्तर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम सिर्फ "कुछ मिलता-जुलता" वापस नहीं करता है, बल्कि प्रासंगिक रूप से संरेखित उत्तरों को शीर्ष पर धकेलता है।

नॉलेज ग्राफ़ संश्लेषण

केवल कच्चे उत्तर ही पर्याप्त नहीं होते, क्योंकि सरकारी जानकारी अक्सर आपस में जुड़ी हुई होती है। जिज्ञासा प्राप्त जानकारी को एक संरचित नॉलेज ग्राफ़ में बदल देती है, विभिन्न पृष्ठों पर स्थित जानकारी को एक सुसंगत स्टोरीबोर्ड में पिरोती है, जिससे उपयोगकर्ता को एक संपूर्ण, संदर्भ-समृद्ध प्रतिक्रिया मिलती है जो उसकी जिज्ञासा को सचमुच शांत करती है।

एआई - आधारित नेविगेशन

अपने इंटरैक्टिव स्टोरीबोर्ड के माध्यम से, उपयोगकर्ता एक क्लिक से सीधे जानकारी के सटीक टुकड़े तक पहुँच सकते हैं। यह स्थिर पोर्टलों को जीवंत, संवादात्मक यात्राओं में बदल देता है, जहाँ जानकारी को तुरंत पहुँचाया जाता है और प्रासंगिक रूप से खोजा जाता है, भले ही वह साइटमैप (वेबसाइट की रूपरेखा) में गहराई में दबी हो।

फीडबैक और सुधार

हर बातचीत सीखने का एक अवसर है। जिज्ञासा उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया और प्रदर्शन डेटा एकत्र करती है, इसे सटीकता, प्रतिक्रियाशीलता और प्रासंगिक गहराई को लगातार परिष्कृत करने

के लिए अपने मॉडलों को वापस भेजती है। यह बंद-लूप प्रणाली सुनिश्चित करती है कि जिज्ञासा स्थिर नहीं है, बल्कि एक सदा-विकसित होने वाली एआई सहायिका है जो हर प्रश्न के साथ तेज़ होती जाती है।

टेक्नोलॉजी स्टैक और कार्यप्रवाह

'जिज्ञासा' को कंटेनरीकृत घटकों के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो डॉकर के साथ स्केलेबिलिटी (बढ़ोतरी की क्षमता) और प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक घटक पायथन फैस्टएपीआई पर बने एपीआई के माध्यम से संवाद करता है:

- **डेटा निष्कर्षण:** यह फास्टएपीआई + क्यूड्रांट डीबी का उपयोग करके सामग्री को क्रॉल करता है, खंडों में तोड़ता है, और टेक्स्ट और वेक्टर प्रारूपों में संग्रहीत करता है।
- **सूचना पुनर्प्राप्ति:** यह ओपन-वेट एआई मॉडल द्वारा संचालित कीवर्ड और सिमेंटिक खोज के माध्यम से सबसे प्रासंगिक सामग्री प्रदान करता है।
- **वैकल्पिक एलएलएम (बृहत् भाषा मॉडल):** यह प्राप्त डेटा को नॉलेज ग्राफ़ में परिवर्तित करता है, जिससे गहरी अंतर्दृष्टि का पता चलता है।
- **प्लगेबल फ्रंटएंड:** यह एक डायनामिक, अनुकूलनीय जेएस इंटरफ़ेस है जो फीडबैक से सीखता है और सहजता से एकीकृत हो जाता है।

लाभ

'जिज्ञासा' हर हितधारक को तत्काल, मापने योग्य मूल्य प्रदान करती है, ई-गवर्नेंस अनुभव को एक चुनौती से एक अवसर में बदल देती है।

नागरिकों के लिए

- **सीखने की आवश्यकता शून्य:** अपनी पसंदीदा भाषा में स्वाभाविक रूप से पूछकर तुरंत जानकारी प्राप्त करें।
- **बेहतर डिजिटल समावेशन:** गैर-तकनीकी-समझ वाले उपयोगकर्ताओं, गैर-अंग्रेज़ी भाषी लोगों और दिव्यांगजनों के लिए बाधाओं को तोड़ता है।

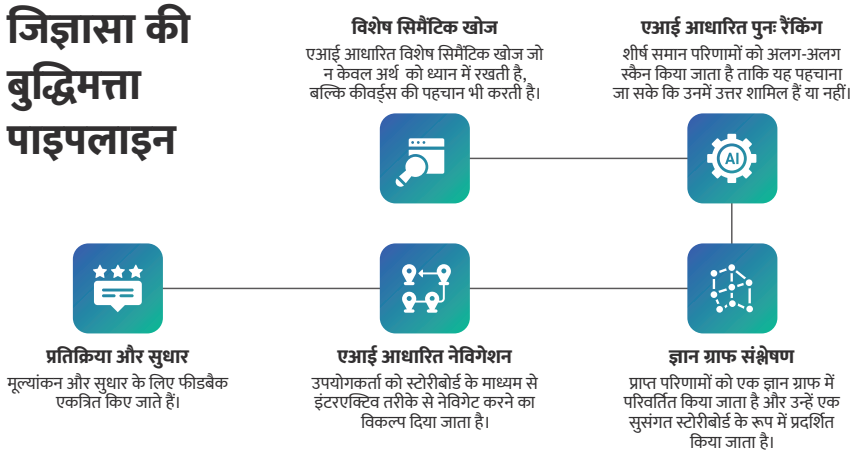

- **समय और लागत की बचत:** फॉर्म खोजने से लेकर योजना की पात्रता जाँचने जैसे सरल कार्यों पर खर्च होने वाले समय और प्रयास को नाटकीय रूप से कम करता है।

सरकारी विभागों के लिए

- **कम हुआ सपोर्ट का बोझ:** हेल्पलाइन कॉल और व्यक्तिगत पूछताछ में कटौती करता है, जिससे कर्मचारियों को जटिल, उच्च-मूल्य वाले कार्यों के लिए समय मिलता है।
- **डेटा-चालित अंतर्दृष्टि:** नागरिक समस्या बिंदुओं, लोकप्रिय प्रश्नों और पोर्टल की अक्षमताओं पर वास्तविक समय के विश्लेषण प्राप्त करें।
- **सहज एकीकरण:** कम लागत वाला, एपीआई-आधारित प्लगइन मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ काम करता है, पिछले निवेशों की रक्षा करता है।
- **तेज़ डिजिटल अपनाना:** सहज बातचीत विश्वास का निर्माण करती है और ई-गवर्नेंस सेवाओं के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करती है।
- **एकीकृत, बहुभाषी पहुँच:** सभी पोर्टलों पर एक सुसंगत, उच्च-गुणवत्ता वाला अनुभव प्रदान करता है, जिससे डिजिटल इंडिया ब्रांड को मजबूती मिलती है।
- **बढ़ी हुई पारदर्शिता:** जानकारी के लिए स्पष्ट, सीधे रास्ते प्रदान करता है, जिससे अधिक सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष

'जिज्ञासा' का एक कार्यशील मॉडल महाराष्ट्र के आईटी प्रधान सचिव को दिखाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप विभाग ने इंडियाएआई मिशन के तहत जीपीयू आवंटन को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है।

जैसे-जैसे हम उत्पादन बुनियादी ढाँचे को सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, हमारा समानांतर ध्यान जिज्ञासा को एक स्टैंडअलोन उत्पाद से एक बुनियादी, ओपन-सोर्स टेक्नोलॉजी में विकसित करने पर है। यह रणनीतिक विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को अपनी किसी भी परियोजना के लिए बुद्धिमान सहायक बनाने और तैनात करने के लिए सशक्त करेगा, जिससे ई-गवर्नेंस परिदृश्य मौलिक रूप से बदल जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान महाराष्ट्र राज्य केंद्र
11वीं मंज़िल, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग,
मंत्रालय के सामने, मैडम कामा रोड, मुंबई-400032
ईमेल: sio-mah@nic.inn, फ़ोन: : 022-22046934/ 22837339

ओडिशा आपदा संसाधन नेटवर्क

हर जीवन अनमोल है

संपादित : **निस्सी जॉर्ज**

1999 में स्थापित ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ओ.एस.डी.एम.ए.), आपदा प्रबंधन और लचीलापन निर्माण के लिए राज्य का सर्वोच्च निकाय है। ओडिशा आपदा संसाधन नेटवर्क (ओ.डी.आर.एन.) सभी प्रशासनिक स्तरों पर जनशक्ति, बुनियादी ढाँचे और उपकरणों के एक केंद्रीकृत, जीआईएस -आधारित डेटाबेस के रूप में कार्य करके इसके प्रयासों को पूरक बनाता है। वास्तविक समय, स्थान-विशिष्ट जानकारी प्रदान करके, ओ.डी.आर.एन. आपदा प्रबंधन योजना का समर्थन करता है, संसाधनों के त्वरित जुटाव को सक्षम बनाता है और एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करता है। यह प्रौद्योगिकी-संचालित मंच तैयारी को बढ़ाता है, जोखिमों को कम करता है और ओडिशा भर में लचीलापन बनाता है।

उद्देश्य

- **संसाधन सूची प्रबंधन** - आपातकालीन संसाधनों का एक अद्यतन डेटाबेस बनाए रखता है, जिसमें उपकरण, मानव संसाधन और बुनियादी ढाँचा शामिल है।

डॉ. अशोक कुमार होता
उप. महानिदेशक व एसआईओ
ak.hota@nic.in

ममता खमारी
उप. महानिदेशक
m.khimari@nic.in

जयंत कुमार मिश्रा
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
jkmishra@nic.in

रवीन्द्र कुमार मोहराणा
तकनीकी निदेशक
rabinda.moharana@nic.in

ओडिशा आपदा संसाधन नेटवर्क (ओ.डी.आर.एन.) संसाधन प्रबंधन प्रणाली का एक केंद्रीकृत जीआईएस आधारित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (https://odrn.nic.in/) है, जिसे ओडिशा में आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह चक्रवात, बाढ़, सूखा और अन्य आपात स्थितियों जैसी आपदाओं के दौरान आवश्यक महत्वपूर्ण संसाधनों, जैसे मानव, बुनियादी ढाँचा और उपकरण, का पता लगाकर और उनका प्रबंधन करता है।

- **वास्तविक समय पहुँच** - सरकारी एजेंसियों और आपदा प्रबंधन टीमों के लिए संसाधनों की उपलब्धता की जानकारी तक त्वरित पहुँच प्रदान करता है।
- **समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया** - कुशल आपदा प्रतिक्रिया के लिए विभिन्न विभागों और हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय को सुगम बनाता है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही** - कुप्रबंधन और देरी को रोकने के लिए संसाधनों की उचित निगरानी और उपयोग सुनिश्चित करता है।
- **आपदा प्रबंधन योजनाओं के साथ एकीकरण** - एक सुव्यवस्थित आपदा प्रबंधन रणनीति के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया ढाँचों के साथ संरेखित करें।

विशेषताएँ

- **जीआईएस-सक्षम मानचित्रण** - राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर आश्रयों, उपकरणों, जनशक्ति और अन्य संपत्तियों का दृश्यांकन करता है, ताकि आपात स्थितियों के दौरान आसान तैनाती सुनिश्चित हो सके।
- **संसाधन नियोजन और संचलन** - प्रशासन को आपदाओं के दौरान बचाव दल, आश्रयों और उपकरणों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने में मदद करता है।
- **योजना सहायता** - स्थानिक डेटा और अद्यतन सूची का उपयोग करके सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन योजनाएँ (डीएमपी) तैयार करने में सहायता करता है।
- **सुरक्षित पहुँच और वेब उपलब्धता** - त्वरित निर्णय लेने में सहायता के लिए अधिकृत अधिकारियों के लिए सुरक्षित, बहु-प्लेटफ़ॉर्म पहुँच के साथ भूमिका-आधारित लॉगिन प्रदान करता है।

कार्यक्षमताएं

- **संसाधन सूची प्रबंधन** – राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर मानव संसाधन, अवसंरचना और उपकरणों का एक व्यापक एवं नियमित रूप से अद्यतन किया जाने वाला डेटाबेस बनाए रखता है।
- **जीआईएस आधारित दृश्यांकन** – संसाधनों, आश्रयों की क्षमता और मार्गों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, जिससे आपदा संभावित क्षेत्रों की त्वरित पहचान, संसाधन जुटाव और स्थानिक विश्लेषण में सहायता मिलती है।
- **योजना एवं निर्णय समर्थन** – आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी और अद्यतन में सहायता करता है, संसाधन अंतराल की पहचान करता है, तथा खरीद और क्षमता निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- **आपातकालीन संसाधन जुटाव** – वास्तविक समय में निकटतम संसाधनों की पहचान करता है, जिससे आपदा के दौरान प्रभावी लॉजिस्टिक्स, आवंटन और तैनाती सुनिश्चित होती है।
- **अंतर-विभागीय समन्वय** – ओ.एस.डी.एम.ए., जिला प्राधिकरणों, विभागों, ओ.डी.आर.ए.एफ., एस.डी.आर.एफ. और एन.डी.आर.एफ. के बीच सहयोग और समन्वय को सुदृढ़ करता है।
- **रिपोर्टिंग एवं प्रलेखन** – संसाधनों, अवसंरचना, तत्परता और तैनाती पर अनुकूलित रिपोर्ट तैयार करता है, जो ऑडिट और आपदा उपरांत समीक्षा में सहायक होती हैं।
- **उपयोगकर्ता अभिगम एवं सुरक्षा** – विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए भूमिका-आधारित लॉगिन प्रदान करता है, जिससे सुरक्षित, गोपनीय और नियंत्रित सूचना तक पहुँच सुनिश्चित होती है।
- **सूचना समर्थन** – केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों की जानकारी अधिकारियों को अद्यतन रूप में प्रदान करता है।
- **उपयोगकर्ता प्रबंधन** – अधिकृत उपयोगकर्ताओं के नियंत्रित रूप से जोड़ने और प्रबंधन की सुविधा देता है।

- **एमआईएस रिपोर्ट निर्माण** – योजना, निगरानी और मूल्यांकन के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट तैयार करता है।

तकनीकी संरचना

ओ.डी.आर.एन. एप्लिकेशन को स्प्रिंग बूट पर आधारित मॉडल-व्यू-कंट्रोलर (एमवीसी) फ्रेमवर्क का उपयोग करके विकसित किया गया है, जिससे कोड संरचना स्वच्छ, स्केलेबल और सुगमता से बनाए रखने योग्य बनी रहती है। यह आर्किटेक्चर फ्रंटएंड और बैकएंड घटकों के बीच निर्बाध इंटरैक्शन, सहज संपर्क, कुशल डेटा प्रवाह, और मॉड्यूलर विकास को सक्षम बनाता है। मॉड्यूलर संरचना, सुरक्षित डेटा प्रबंधन, उत्तरदायी उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस, उन्नत दृश्यांकन उपकरण, और एकीकृत भू-स्थानिक इंटेलिजेंस के साथ डिज़ाइन किया गया यह सिस्टम, आपदा प्रबंधन संचालन के लिए विश्वसनीयता और लचीलापन - दोनों प्रदान करता है।

बैकएंड लेयर

- **फ्रेमवर्क :** स्प्रिंग बूट वेब एप्लिकेशनों के लिए एक मज़बूत, प्रोडक्शन-रेडी वातावरण प्रदान करता है।
- **डेटाबेस :**पोस्टग्रेएसक्यूएल सुरक्षित डेटा भंडारण, तेज़ क्वेरी निष्पादन और विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
- **डेटा हैंडलिंग :** उपयोगकर्ता डेटा के सुरक्षित प्रबंधन को सक्षम बनाता है, जिसमें उचित ट्रांज़ैक्शन हैंडलिंग और इंटीग्रिटी चेक शामिल हैं।

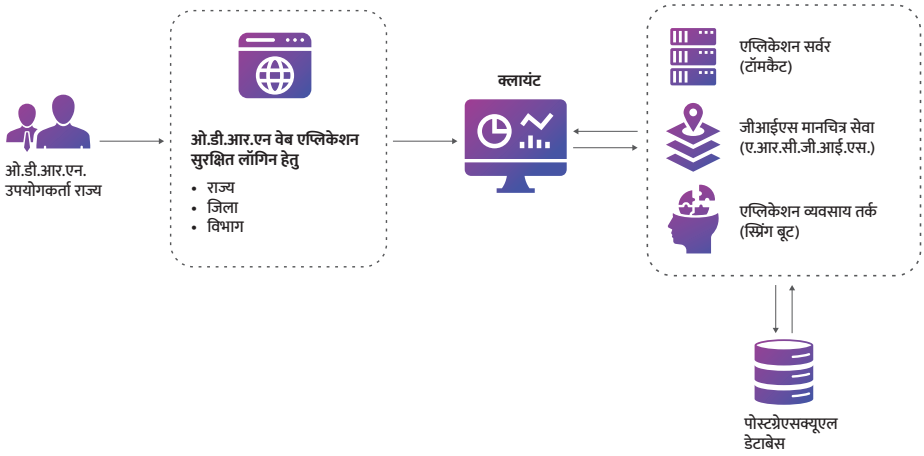

▲ चित्र 8.1 सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर

प्रेज़ेंटेशन लेयर

- **टेम्पलेट इंजन :** डायनेमिक कंटेंट रेंडरिंग के लिए थीमलीफ का उपयोग किया गया है।
- **यूज़र इंटरफ़ेस :** बूटस्ट्रैप पर आधारित, जो मोबाइल-अनुकूल और सभी के लिए सुलभ डिज़ाइन प्रदान करता है।
- **डेटा विज़ुअलाइज़ेशन :** चार्ट.जेएस इंटरएक्टिव डैशबोर्ड्स को संचालित करता है, जिससे उपयोगकर्ता जटिल डेटा को आसानी से समझ और विश्लेषण कर सकते हैं।

इंटीग्रेशन एवं जीआईएस क्षमताएँ

- **एनआईसीमैप सर्विस एपीआई :** भारत मैप जीआईएस के माध्यम से भू-स्थानिक कार्यक्षमताओं का एकीकरण करता है, जिससे स्थान-आधारित मैपिंग, दृश्यांकन और विश्लेषण संभव होता है।
- **निर्णय समर्थन :** संसाधन डेटा को भू-स्थानिक इंटेलिजेंस के साथ संयोजित कर आपदा योजना और प्रतिक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है।

लाभ

- **संसाधनों की बेहतर दृश्यता एवं ट्रैकिंग** – विभिन्न स्थानों पर मानव संसाधन, अवसंरचना और उपकरणों का मानचित्रण करता है, जिससे अधिकारी उपलब्ध संसाधनों की त्वरित पहचान कर सकते हैं, दोहराव से बच सकते हैं और बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं।
- **तेज़ एवं अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया** – पूर्व-मैप किए गए संसाधन त्वरित जुटाव को सक्षम बनाते हैं, जिससे विलंब कम होता है और जीवन बचाने में सहायता मिलती है।
- **बेहतर तैयारी** – पहले से संसाधन अंतराल को दर्शाता है, जिससे राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं को मज़बूती मिलती है।
- **समन्वित योजना** – केंद्रीकृत किन्तु स्थान-विशिष्ट डेटा सभी प्रशासनिक स्तरों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करता है।
- **प्रभावी पुनर्प्राप्ति** – संसाधनों की उपलब्धता का डेटा तेज़ और प्रभावी पुनर्प्राप्ति योजना में सहायक होता है।
- **पारदर्शी निर्णय-निर्माण** – नियमित रूप से अद्यतन और मानचित्रित डेटा अस्पष्टता को कम करता है, जवाबदेही बढ़ाता है और सार्वजनिक विश्वास को सशक्त करता है।
- **संसाधन आवंटन का अनुकूलन** – आवश्यकताओं को उपलब्ध संसाधनों से मेल कराता है, जिससे उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों में संसाधनों की पूर्व-स्थिति सुनिश्चित होती है और बर्बादी से बचा जा सकता है।
- **विस्तारयोग्यता एवं गतिशील अद्यतन** – जीआईएस आधारित प्रणाली संसाधनों में बदलाव या पुनर्वितरण के अनुसार निरंतर अद्यतन की सुविधा देती है।
- **जोखिम में कमी एवं लचीलापन** – बार-बार आने वाले अंतराल और कमजोरियों की पहचान कर समय के साथ ओडिशा की आपदा-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है।
- **अन्य प्रणालियों के साथ एकीकरण** – समग्र आपदा प्रबंधन तंत्र के सुचारू संचालन में सहायक होती है।

अग्रिम दिशा

ओ.डी.आर.एन. का भविष्य जीपीएस/ आर.एफ.आई.डी और लाइव डैशबोर्ड के माध्यम से महत्वपूर्ण संसाधनों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग और ओडिशा की पूर्व चेतावनी प्रणालियों के साथ एकीकरण पर केंद्रित है। ऑफ़लाइन एक्सेस वाला मोबाइल ऐप दूरस्थ क्षेत्रों में उपयोगिता बढ़ाएगा, जबकि स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन और अन्य विभागों के समन्वय से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी। एआई और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण से संसाधन अंतर की पहचान, तैयारी स्कोर और योजना सुदृढ़ होगी। ये नवाचार ओडिशा की आपदा प्रतिक्रिया को अधिक गतिशील, लचीला और समन्वित बनाएंगे, जिससे राज्य के "शून्य हताहत मिशन" को मज़बूती मिलेगी और समग्र आपदा प्रबंधन क्षमता में बड़ा सुधार होगा।

ओडिशा डिज़ास्टर रिसोर्स नेटवर्क (ओ.डी.आर.एन.) एप्लिकेशन, ओ.एस.डी.एम.ए. और ओडिशा राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो भू-स्थानिक (GIS) आधारित प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अवसंरचना, उपकरणों और मानव संसाधनों से संबंधित जानकारी को केंद्रीकृत करता है। यह प्रणाली आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण संसाधनों की त्वरित पहचान और जुटाव को सक्षम बनाती है, जिससे प्रतिक्रिया समय कम होता है और समय पर बचाव एवं राहत कार्य सुनिश्चित होते हैं। ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर संसाधनों का मानचित्रण करके यह प्रणाली तैयारी को मजबूत करती है और आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण की योजना में सुधार लाती है। यह विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय को प्रोत्साहित करती है, जिससे आपदा प्रबंधन कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। संसाधनों के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है, जिससे कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है। अंततः, ओ.डी.आर.एन. आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने और "शून्य हताहत मिशन" को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है।

मैं एनआईसी ओडिशा टीम को तकनीकी सहयोग प्रदान करने और ओ.एस.डी.एम.ए. के अधिकारियों को इस परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ।

डॉ. कमल लोचन मिश्रा, आईएएस
कार्यकारी निदेशक, ओ.एस.डी.एम.ए.

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

रवीन्द्र कुमार मोहराणा
तकनीकी निदेशक
एनआईसी, ओडिशा राज्य केंद्र, सचिवालय मार्ग, यूनिट-IV
भुवनेश्वर, ओडिशा - 751001
ईमेल: rabinda.moharana@nic.in, फोन: 0674-2508438

पैमाना पोर्टल

बुनियादी ढांचा परियोजना निगरानी प्लेटफार्म

संपादित : **अर्चना शर्मा**

पैमाना पोर्टल (ipm.mospi.gov.in) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई) की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचे और परियोजना प्रबंधन से संबंधित आँकड़ों की निगरानी, मूल्यांकन और प्रसार के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्म के रूप में कार्य करना है। पैमाना का औपचारिक शुभारंभ 25 सितंबर को माननीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा किया गया, जो पारदर्शिता और आँकड़ा-संचालित शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

यह पोर्टल विश्वसनीय परियोजना जानकारी तक वास्तविक समय में पहुँच सुनिश्चित करके जवाबदेही बढ़ाता है, जिससे साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया मज़बूत होती है और कुशल शासन संभव होता है। यह ₹150 करोड़ और उससे अधिक मूल्य की परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति को व्यापक रूप से दर्शाता है, और 20 से अधिक मंत्रालयों की 1,700 से अधिक परियोजनाओं को सम्मिलित करता है, और संबंधित मंत्रालयों, विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से डेटा की रिपोर्ट करता है।

नीता चौहान
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एचओडी
neeta.chauhan@nic.in

सौधामिनी श्रीनिवासन
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
sdamini@nic.in

दीपा पालीवाल
वैज्ञानिक - डी
paliwal.deepa@nic.in

शुभेन्द्र सिंह
वरिष्ठ तकनीकी सहायक - बी
shubhendra.singh@nic.in

एम.ओ.एस.पी.आई. द्वारा विकसित पैमाना पोर्टल, पूरे भारत में उच्च-मूल्य वाली बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्म प्रदान करता है। 150 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परियोजनाओं को कवर करते हुए, यह पारदर्शिता बढ़ाता है, वास्तविक समय में निर्णय लेने में सहायता करता है और हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करता है। यह साक्ष्य-आधारित शासन को सक्षम बनाता है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं की समय पर निगरानी सुनिश्चित करने में मदद करता है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र विभाग के साथ समय-समय पर परियोजना समीक्षा बैठकें आयोजित करता है और परियोजना निष्पादन में तेजी लाने के लिए लगातार प्रणालीगत सुधारों को लागू करता है। ये प्रयास बाधाओं की पहचान करने, समय और लागत में वृद्धि का विश्लेषण करने और समय पर सुधारात्मक उपाय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे अंततः शासकीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदर्शन-उन्मुख और पारदर्शी परियोजना प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

टेक्नोलॉजी स्टैक

- **फ्रंटएंड :** एच.टी.एम.एल, सीएसएस रेस्पॉन्सिव इंटरफ़ेस यूआई डिज़ाइन के लिए बूटस्ट्रैप के साथ
- **डेटाबेस :** संग्रह डेटा संग्रहण के लिए एमएस एसक्यूएल
- **होस्टिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर :** सुरक्षित और स्केलेबल परिनियोजन के लिए एनआईसी क्लाउड
- **एनालिटिक्स और विज़ुअलाइज़ेशन :** एकीकृत बीआई टूल और डैशबोर्ड के लिए एस.एस.आर.एस, जिसमें ड्रिल-डाउन सुविधाएँ हैं
- **सुरक्षा :** भूमिका-आधारित एक्सेस नियंत्रण, एसएसएल एन्क्रिप्शन, और सरकारी साइबर सुरक्षा मानकों का अनुपालन
- **एपीआई और एकीकरण :** अन्य सरकारी प्लेटफार्म के साथ निर्बाध डेटा विनिमय के लिए रेस्टफुल एपीआई
- **प्रोटोटाइप :** प्रोटोटाइपिंग और वायरफ़्रेम के लिए फिग्मा

सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर

यह प्रणाली कई प्रमुख घटकों वाली एक स्तरिय वास्तुकला का

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.) ने पैमाना नामक एक वन-स्टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर वेब प्लेटफॉर्म पेश किया है, जो 150 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली चल रही केंद्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए एक विश्वसनीय डेटा स्रोत के रूप में कार्य करता है। निगरानी और विश्लेषण को एक एकीकृत प्लेटफॉर्म में एकीकृत करके, पैमाना मंत्रालयों को शक्तिशाली कार्यवाही योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जवाबदेही को मजबूत करता है और महत्वाकांक्षी निवेशों को शीघ्र परिणामों में बदलने में मदद करता है जिससे लोगों का जीवन बेहतर होता है और राष्ट्र निर्माण में तेजी आती है। एनआईसी ने आईसीटी को अपनाने की वकालत करने और मंत्रालय भर में प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों के कार्यान्वयन की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि एनआईसी इस उत्कृष्ट कार्य को जारी रखेगा, आवश्यक तकनीकी सहायता और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आईसीटी सेवाओं का कार्यान्वयन पूरी तरह से सफलतापूर्वक हो, और हमेशा इसका अंतिम उद्देश्य नागरिकों को लाभ पहुँचाना है।

डॉ. सौरभ गर्ग, आईएएस
सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अनुसरण करती है। बहुस्तरिय वास्तुकला कई घटकों में मापनीयता, सुरक्षा और कुशल डेटा विनिमय सुनिश्चित करती है। डेटा प्रविष्टि और एकीकरण सुरक्षित इंटरफेस के माध्यम से प्रबंधित किए जाते हैं जहाँ मंत्रालय और एजेंसियाँ परियोजना जानकारी अपलोड करती हैं। दूरस्थ डेटा कैप्चर तंत्र रेस्टफुल एपीआई का उपयोग करके बाहरी प्रणालियों से जानकारी प्राप्त करते हैं। यह लोड बैलेंसर के माध्यम से इंटरैक्ट करता है, जो प्रदर्शन और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आने वाले अनुरोधों को विभिन्न सर्वरों पर कुशलतापूर्वक प्रबंधित और वितरित करता है। एंटरप्राइज़ लाइब्रेरी, रिले सेवा, लॉगर सेवा और रिपोर्टिंग सेवा (एस.एस.आर.एस.) जैसे सहायक घटक उपयोगिता कार्य, संचार, लॉगिंग, और रिपोर्ट और डैशबोर्ड निर्माण प्रदान करते हैं।

यह ऐतिहासिक निरंतरता बनाए रखने के लिए पुरानी प्रणालियों के लीगेसी डेटा के साथ भी एकीकृत है।

कुल मिलाकर, यह आर्किटेक्चर सरकारी परियोजनाओं के लिए वास्तविक समय में निर्बाध एकीकरण, सत्यापन, रिपोर्टिंग और विज़ुअलाइज़ेशन को सक्षम बनाता है, जिससे विश्वसनीयता, पारदर्शिता और सूचित निर्णय लेने की क्षमता सुनिश्चित होती है। स्वचालित सत्यापन प्रक्रियाएँ डेटा की सटीकता सुनिश्चित करती हैं, जबकि निगरानी डैशबोर्ड परियोजना की प्रगति पर निरंतर नजर रखने में सक्षम बनाते हैं। अधिकृत उपयोगकर्ता बाधाओं की पहचान करने और समग्र स्थिति का आकलन करने के लिए डेटा की समीक्षा और विश्लेषण कर सकते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

यह प्लेटफार्म एक केंद्रीकृत परियोजना निगरानी प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो मंत्रालयों, विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना जानकारी अपलोड करने, ट्रैक करने और समीक्षा करने के लिए एकल-खिड़की इंटरफ़ेस प्रदान करता है। इसमें ड्रिल-डाउन क्षमताओं वाले रीयल-टाइम डैशबोर्ड हैं, जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों और समय-सीमाओं में प्रगति की निगरानी करने में सक्षम बनाते हैं। सुरक्षित रेस्टफुल एपीआई के माध्यम से, यह प्रणाली बाहरी सर्वरों से निर्बाध डेटा संग्रहण और एकीकरण

▲ चित्र 9.2 : माननीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री, राव इंद्रजीत सिंह द्वारा 25 सितम्बर 2025 को पैमाना का शुभारंभ किया गया

सुनिश्चित करती है। एक भूमिका-आधारित पहुँच नियंत्रण तंत्र डेटा की सुरक्षा करता है और विभिन्न उपयोगकर्ता श्रेणियों को अनुकूलित पहुँच अधिकार प्रदान करके जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

इस प्लेटफार्म में एक इंटरैक्टिव रिपोर्टिंग इंटरफ़ेस भी है, जिसे नीति निर्माताओं, प्रशासकों और हितधारकों के लिए अनुकूलित, डाउनलोड करने योग्य और डेटा-समृद्ध रिपोर्ट तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सेवाओं (एस.एस.आर.एस.) का उपयोग करके विकसित यह सिस्टम-जनरेटेड रिपोर्टिंग मॉड्यूल, उन्नत विज़ुअलाइज़ेशन सूचना विज्ञान के साथ 80-पृष्ठों की एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें पाठ, तालिकाओं, ग्राफ़ और चार्ट का सहज सम्मिश्रण है। ये रिपोर्टें पाँच उत्कृष्ट परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती हैं, जो स्पष्ट और आकर्षक विश्लेषण के माध्यम से उनकी प्रगति, उपलब्धियों, वित्तीय स्थिति और महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डालती हैं। स्थिर सारांशों के अलावा, यह इंटरफ़ेस गतिशील फ़िल्टरिंग और ड्रिल-डाउन विश्लेषण का समर्थन करता है, जो उपयोगकर्ताओं को कई आयामों से परियोजना डेटा का अन्वेषण करने में सक्षम बनाता है। इसकी विश्लेषण और निर्णय-समर्थन सुविधाएँ प्रवृत्ति विश्लेषण, पूर्वानुमान और अड़चनों की पहचान को सक्षम बनाती हैं, जिससे रणनीतिक योजना और सूचित निर्णय लेने की क्षमता मज़बूत होती है। मोबाइल-उत्तरदायी इंटरफ़ेस के साथ, उपयोगकर्ता किसी भी डिवाइस से परियोजना की प्रगति की आसानी से निगरानी कर सकते हैं।

सुरक्षित एनआईसी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निर्मित, यह प्रणाली सरकारी साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा मानकों का पालन करती है। इसके अलावा, इसका मॉड्यूलर और स्केलेबल आर्किटेक्चर नई सुविधाओं, डेटासेट और उभरती प्रौद्योगिकियों के निर्बाध एकीकरण की अनुमति देता है - जिससे परियोजना निगरानी और मूल्यांकन में दीर्घकालिक अनुकूलनशीलता, स्थिरता और निरंतर सुधार सुनिश्चित होता है।

प्रभाव और लाभ

यह प्रणाली खुली और विश्वसनीय परियोजना जानकारी के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ावा देकर पारदर्शिता बढ़ाती है। यह वास्तविक समय में प्रगति पर नजर रखने और परियोजना निष्पादन में देरी को कम करके निगरानी में दक्षता में सुधार करती है। नीति-निर्माताओं को सटीक विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि द्वारा समर्थित सूचित निर्णय लेने से लाभ होता है जो प्रभावी हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करते हैं। यह प्लेटफार्म वित्तीय और मानव संसाधनों के बेहतर आवंटन और उपयोग को सुगम बनाकर संसाधन अनुकूलन सुनिश्चित करता है। यह हितधारक सहयोग को भी बढ़ावा देता है और मंत्रालयों, विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय को मज़बूत करता है। अंततः, यह प्रणाली समय पर परियोजना पूर्णता सुनिश्चित करके और नागरिकों को सेवा वितरण में सुधार करके अधिक सार्वजनिक मूल्य प्रदान करती है।

अग्रिम दिशा

आगे बढ़ते हुए, पैमाना पोर्टल उन्नत विश्लेषण, एआई-संचालित पूर्वानुमान और उन्नत मोबाइल पहुँच को एकीकृत करेगा ताकि परियोजना निगरानी और मूल्यांकन को और मज़बूत बनाया जा सके। एआई-संचालित पूर्वानुमान समय और लागत वृद्धि, संसाधन आवश्यकताओं और संभावित जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करेगा, जिससे बेहतर परियोजना परिणामों के लिए समय पर और डेटा-समर्थित हस्तक्षेप संभव होंगे। हितधारकों की निरंतर सहभागिता और प्रणाली में सुधार से बेहतर उपयोगिता, मज़बूत निर्णय समर्थन और राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के साथ संरेखण सुनिश्चित होगा।

▼ चित्र 9.1 **सिस्टम आर्किटेक्चर**

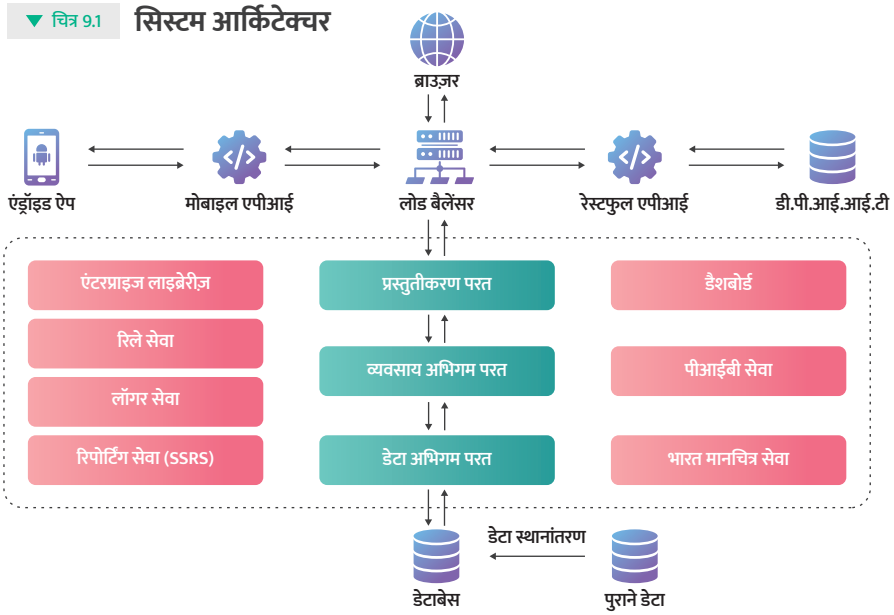

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

विभागाध्यक्ष, एनआईसी-मोसपी इन्फार्मेटिक्स डिवीज़न
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
कक्ष संख्या 428, के.एल. भवन, जनपथ, नई दिल्ली - 110001
ईमेल: hod-mspi@nic.in, फ़ोन: 011-23455428

अनुमति प्रबंधन प्रणाली

साइबराबाद पुलिस में चुस्त और पारदर्शी शासन को सशक्त बनाना

संपादित : **निस्सी जॉर्ज**

डिजिटल शासन के युग में, दक्षता का अर्थ अब केवल सार्वजनिक सेवाओं को ऑनलाइन करना नहीं रह गया है। इसका अर्थ है ऐसी प्रणालियाँ बनाना जो विकसित हो सकें - ऐसी प्रणालियाँ जो नई नीतियों, तात्कालिक परिस्थितियों और बदलती नागरिक आवश्यकताओं का बिना किसी भारी तकनीकी हस्तक्षेप के जवाब दे सकें। पारंपरिक सरकारी अनुप्रयोग अक्सर यहाँ विफल हो जाते हैं; उनका कठोर डिज़ाइन छोटे अपडेट को भी धीमा, महंगा और विशेष सॉफ़्टवेयर टीमों पर निर्भर बना देता है।

इस चुनौती को समझते हुए, एनआईसी, हैदराबाद ने साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के लिए एक अभिनव, लचीला और नागरिक-केंद्रित समाधान विकसित किया है - अनुमति प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस)। यह एक व्यापक, विन्यास योग्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे सार्वजनिक अनुमतियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह तेज़ अनुमोदन, पारदर्शिता और अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करता है - साथ ही अधिकारियों पर प्रशासनिक बोझ कम करता है और नागरिकों की सुविधा में सुधार करता है।

अपने मूल में, पीएमएस तीन गतिशील उपकरणों को एकीकृत करता है जो बिना कोडिंग के पूर्ण विन्यास क्षमता प्रदान करते हैं:

- **डायनेमिक फ़ॉर्म डिज़ाइनर** - आवेदन फ़ॉर्म को आसानी से बनाने और प्रबंधित करने के लिए।
- **वर्कफ़्लो डिज़ाइनर** - अनुमोदन प्रक्रियाओं को कॉन्फ़िगर करने और निर्णय प्रवाह को स्वचालित करने के लिए।

गुंटुकु प्रसाद
उप महानिदेशक व एसआईओ
gprasad@nic.in

आकेल्ला श्रीनिवास सुब्बा राव
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एचओडी
ssrakella@nic.in

अनिल कुमार येन्नी
वैज्ञानिक - सी
ak.yenni@nic.in

साइबराबाद पुलिस के लिए एनआईसी हैदराबाद द्वारा विकसित पीएमएस एक नो-कोड डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो सार्वजनिक अनुमतियों को स्वचालित और सरल बनाता है। गतिशील फ़ॉर्म, वर्कफ़्लो और दस्तावेज़ टूल के साथ, इसने अनुमोदन समय को कम किया है, पारदर्शिता में सुधार किया है और नागरिकों की सुविधा को बढ़ाया है - जो अनुकूली डिजिटल शासन के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में उभर रहा है।

- **दस्तावेज़ टेम्पलेट डिज़ाइनर** - आधिकारिक संचार को स्वचालित रूप से उत्पन्न करने के लिए।

इन उपकरणों ने मिलकर अनुमतियों के प्रबंधन के तरीके को बदल दिया है - एक समय लेने वाली, काग़ज़-आधारित प्रक्रिया को एक डिजिटल, पता लगाने योग्य और नागरिक-अनुकूल प्रणाली में बदल दिया है।

सार्वजनिक अनुमतियों के लिए एक एकीकृत डिजिटल ढाँचा

अनुमति प्रबंधन प्रणाली नागरिकों के लिए एक वन-स्टॉप डिजिटल इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करती है ताकि वे पुलिस की अनुमति की आवश्यकता वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए आवेदन कर सकें, उन्हें ट्रैक कर सकें और अनुमोदन प्राप्त कर सकें।

इनमें कई तरह के मामले शामिल हैं - धार्मिक जुलूस, सार्वजनिक रैलियाँ और मैराथन आयोजित करने से लेकर फिल्म शूटिंग लाइसेंस, लाउडस्पीकर उपयोग और स्थापना परमिट प्रदान करने तक।

कॉन्फ़िगरेबिलिटी को स्वचालन के साथ जोड़कर, PMS ने मैन्युअल फ़ाइल मूवमेंट और भौतिक अनुमोदनों को डिजिटल वर्कफ़्लो से बदल दिया है जो सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल हैं।

डायनेमिक फ़ॉर्म डिज़ाइनर

पारंपरिक व्यवस्थाओं में, एक नया अनुमति प्रकार शुरू करने या किसी मौजूदा फ़ॉर्म को संशोधित करने में सॉफ़्टवेयर डेवलपर्स के साथ समन्वय, सिस्टम डाउनटाइम और परीक्षण में देरी शामिल होती है। पीएमएस में निर्मित डायनेमिक फ़ॉर्म डिज़ाइनर इन बाधाओं को दूर करता है। यह एक नो-कोड इंटरफ़ेस प्रदान करता है जो प्रशासकों को फ़ॉर्म को तुरंत डिज़ाइन, संपादित और परिनियोजित करने की अनुमति देता है।

प्रमुख क्षमताएँ

- **तत्काल फ़ॉर्म निर्माण:** नए फ़ॉर्म बिना किसी कोडिंग के मिनटों में बनाए और प्रकाशित किए जा सकते हैं
- **फ़ील्ड-स्तरीय लचीलापन:** व्यवस्थापक फ़ील्ड, नियम और लेआउट आसानी से जोड़, हटा या संशोधित कर सकते हैं
- **पुन: प्रयोज्य घटक:** अक्सर उपयोग किए जाने वाले अनुभाग, जैसे आवेदक विवरण या सहायक दस्तावेज़, सभी फ़ॉर्म में संग्रहीत और पुन: उपयोग किए जा सकते हैं
- **बहुभाषी समर्थन:** व्यापक पहुँच के लिए फ़ॉर्म को कई भाषाओं में डिज़ाइन करने में सक्षम बनाता है

यह क्षमता त्योहारों जैसे उच्च-मांग वाले परिदृश्यों के दौरान अमूल्य रही है, जब हज़ारों ईवेंट अनुमतियों को शीघ्रता से संसाधित किया जाना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, गणेश पंडालों, धार्मिक परेडों और सामुदायिक समारोहों के लिए अनुमतियों को गतिशील रूप से उत्पन्न फ़ॉर्म का उपयोग करके कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया गया - बिना किसी नए विकास की आवश्यकता के।

वर्कफ़्लो डिज़ाइनर

अनुमतियों के लिए अक्सर कई विभागों - कानून और व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, खुफिया विभाग और स्थानीय प्रशासन - की जाँच की आवश्यकता होती है। एक निश्चित अनुमोदन संरचना ऐसी विविधता को समायोजित नहीं कर सकती।

वर्कफ़्लो डिज़ाइनर इन जटिलताओं से निपटने के लिए लचीलापन और तर्क-संचालित स्वचालन प्रदान करता है। सूत्र-आधारित मानचित्रण का उपयोग करके, प्रशासक ऐसे वर्कफ़्लो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो स्वचालित रूप से एप्लिकेशन की प्रकृति के अनुकूल हो जाते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

- **कॉन्फ़िगर करने योग्य अनुमोदन स्तर:** बहु-स्तरीय अनुमोदन श्रृंखलाएँ बनाएँ जो विशिष्ट अनुमति प्रकारों के साथ संरेखित हों
- **भूमिका-आधारित असाइनमेंट:** भूमिका, पदनाम और अधिकार क्षेत्र के आधार पर आवेदनों को स्वचालित रूप से अधिकारियों तक पहुँचाता है

- **सशर्त रूटिंग:** बुद्धिमान नियम अपवादों का प्रबंधन करते हैं - उदाहरण के लिए, यदि किसी घटना में सार्वजनिक सड़कें शामिल हैं, तो उसे मंजूरी के लिए ट्रैफ़िक पुलिस को भेजा जाता है
- **स्वचालित एस्केलेशन:** यदि देरी होती है, तो सिस्टम अनुस्मारक भेजता है या मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाता है
- **रीयल-टाइम ट्रैकिंग:** नागरिक और अधिकारी दोनों ही हर चरण में आवेदन की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं

इस लचीलेपन के साथ, साइबराबाद पुलिस कुछ ही घंटों में वर्कफ़्लो शुरू या संशोधित कर सकती है, जिससे वे कोड को फिर से लिखे बिना बदलती प्रशासनिक आवश्यकताओं या घटना-विशिष्ट आवश्यकताओं का जवाब दे सकते हैं।

दस्तावेज़ टेम्पलेट डिज़ाइनर

सरकारी संचार सटीक, एकरूप और समय पर होना चाहिए। दस्तावेज़ टेम्पलेट डिज़ाइनर मॉड्यूल आधिकारिक पत्रों, नोटिसों, कार्यवाहियों और अनुमोदनों के निर्माण को स्वचालित करता है, जिससे महत्वपूर्ण मैन्युअल प्रयास की बचत होती है।

एक उन्नत मेल मर्ज सिस्टम की तरह, यह आवेदक डेटा को गतिशील रूप से मानकीकृत टेम्पलेट्स में मर्ज करता है।

इसकी कुछ कार्यात्मक विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- **स्वचालित दस्तावेज़ निर्माण:** तुरंत ज्ञापन, अनुमतियाँ या सूचनाएँ तैयार करता है
- **प्रारूप में एकरूपता:** सभी विभागों में मानक डिज़ाइन और संरचना बनाए रखता है
- **त्रुटि न्यूनीकरण:** मैन्युअल इनपुट और संभावित अशुद्धियों को कम करता है
- **पुन: प्रयोज्यता:** टेम्पलेट्स को कई वर्कफ़्लो में अपडेट और पुन: उपयोग किया जा सकता है

यह मॉड्यूल सुनिश्चित करता है कि आधिकारिक संचार सुसंगत, पेशेवर और निर्णय लेने के तुरंत बाद उपलब्ध हों।

प्रमुख विशेषताएँ

पीएमएस में शक्तिशाली विशेषताएँ शामिल हैं जो शासन के प्रत्येक स्तर पर उपयोगिता, पारदर्शिता और नियंत्रण को बढ़ाती हैं:

- **ऑनलाइन, कभी भी पहुँच:** नागरिक मोबाइल-अनुकूल इंटरफेस, आधार/ पैन एकीकरण, भुगतान गेटवे और पुन: प्रयोज्य उप-प्रपत्रों द्वारा समर्थित, ऑनलाइन अनुमति अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।
- **रीयल-टाइम सूचनाएँ:** स्वचालित एसएमएस और ईमेल अलर्ट आवेदकों और अधिकारियों को प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण पर सूचित रखते हैं।

प्रमाणीकरण	डिज़ाइन अनुप्रयोग	डिज़ाइन वर्कफ़्लो	दस्तावेज़ डिज़ाइनर
सुरक्षित लॉगइन ऑडियो के साथ कैप्चा	किसी कार्यक्रम की अनुमति के लिए आवेदन पत्र बनाएँ मंज़ूरी देना प्रकाशित करना	अनुमोदन प्रक्रिया के लिए कार्यप्रवाह बनाएँ वर्कफ़्लो को मंज़ूरी दें	आउटपुट बनाएँ दस्तावेज़ डिज़ाइन दस्तावेज़ टेम्पलेट स्वीकृत करें टेम्पलेट प्रकाशित करें

▲ चित्र 10.2 सिस्टम अवलोकन

- **भूमिका-आधारित पहुँच नियंत्रण:** यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता —लिपिक कर्मचारियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक—केवल अपनी भूमिकाओं से संबंधित जानकारी ही देखें।
- **व्यापक ट्रैकिंग:** आवेदक स्थिति अपडेट की निगरानी कर सकते हैं, जबकि अधिकारी एकल इंटरफ़ेस के माध्यम से टिप्पणियों, अनुलग्नकों और नोटिस तक पहुँच सकते हैं।
- **कॉन्फ़िगर करने योग्य वर्कफ़्लो:** समानांतर प्रसंस्करण, पुनरावृत्त स्पष्टीकरण और प्रति-चरण कॉन्फ़िगरेशन जैसे टिप्पणियाँ, डिजिटल हस्ताक्षर या भुगतान की अनुमति देता है।
- **दस्तावेज़ और फ़ीडबैक प्रबंधन:** सुरक्षित दस्तावेज़ अपलोड सक्षम करता है और निरंतर सुधार के लिए पोस्ट-इवेंट फ़ीडबैक कैप्चर करता है।
- **उन्नत विश्लेषण और रिपोर्ट:** प्रक्रिया की बाधाओं की पहचान करने और दक्षता में सुधार करने के लिए भूमिका-वार, समय-वार और फ़ॉर्म-वार विश्लेषण उत्पन्न करता है।
- **लीगेसी ऑनबोर्डिंग:** ऑफ़लाइन सिस्टम के माध्यम से पहले जारी की गई अनुमतियों के डिजिटलीकरण और नवीनीकरण का समर्थन व डिजिटल परिवर्तन में समावेशिता सुनिश्चित करता है।

शामिल अनुमतियाँ

PMS वर्तमान में 20 से ज़्यादा श्रेणियों की अनुमतियों का समर्थन करता है, जिनमें शामिल हैं:

- सार्वजनिक और निजी कार्यक्रम
- फ़िल्म और विज्ञापन शूटिंग (सड़क और ऑफ-रोड)
- मैराथन, रैलियाँ और चैरिटी वॉक
- ब्लास्टिंग अनुमतियाँ और नवीनीकरण
- लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम का उपयोग
- प्रतिष्ठान लाइसेंस और नवीनीकरण
- कार्यक्रम रद्दीकरण, संशोधन और कार्यक्रम के बाद की प्रतिक्रिया

प्रत्येक श्रेणी को स्वतंत्र रूप से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिससे प्रशासकों को फ़ॉर्म डिज़ाइन, वर्कफ़्लो और अनुमोदनों पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है।

साइबराबाद में मापनीय प्रभाव

अपनी शुरुआत के बाद से, पीएमएस ने साइबराबाद में सार्वजनिक आवेदनों के प्रसंस्करण में एक मापनीय परिवर्तन लाया है:

- **प्रसंस्करण समय में कमी:** स्वचालित वर्कफ़्लो ने औसत अनुमोदन समय को कई दिनों से घटाकर कुछ घंटों तक कर दिया है।
- **पारदर्शिता में वृद्धि:** नागरिक ऑनलाइन आवेदनों पर नज़र रख सकते हैं, और अधिकारियों को ऑडिट ट्रेल्स और रीयल-टाइम डेटा दृश्यता का लाभ मिलता है।
- **नागरिकों के लिए सुविधा:** कागज़ रहित आवेदन, डिजिटल भुगतान और तत्काल अपडेट समय की बचत करते हैं और भौतिक यात्राओं की आवश्यकता को समाप्त करते हैं।
- **प्रशासनिक चपलता:** त्योहारों या मैराथन जैसे प्रमुख आयोजनों के दौरान, नए फ़ॉर्म और वर्कफ़्लो तुरंत लागू किए जा सकते हैं।
- **मापनीयता और अपनाना:** इस प्रणाली की सफलता के कारण हैदराबाद और राचकोंडा पुलिस आयुक्तालयों ने इसे अपनाया, जिससे इसकी मापनीयता और प्रतिकृति में आसानी का प्रदर्शन हुआ।

त्यौहारों के मौसम के दौरान एक उल्लेखनीय उदाहरण देखने को मिला, जब हजारों पंडाल और आयोजनों की अनुमतियाँ सुचारू रूप से और समय पर संसाधित की गईं, जिससे पीक लोड के तहत प्रणाली की लचीलापन साबित हुआ।

निष्कर्ष

अनुमति प्रबंधन प्रणाली एक प्रशासनिक उन्नयन से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती है —यह अनुकूली, बुद्धिमान और नागरिक-केंद्रित शासन की ओर एक बदलाव का प्रतीक है।

कॉन्फ़िगरेबिलिटी, स्वचालन और पारदर्शिता को मिलाकर, पीएमएस डेवलपर्स पर निर्भरता कम करता है, मैन्युअल त्रुटियों को न्यूनतम करता है और निर्णय लेने में तेज़ी लाता है।

यह पुलिसिंग तक सीमित नहीं है; इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन इसे सरकारी विभागों में लागू करने योग्य बनाता है - नगर निगमों से लेकर शिक्षा बोर्डों और पर्यावरण एजेंसियों तक।

▼ चित्र 10.1 : श्री अविनाश मोहंती, आईपीएस, आयुक्त एवं उच्च अधिकारियों द्वारा साइबराबाद पुलिस अनुमति प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया गया

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

गुंटुकु प्रसाद
उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना अधिकारी
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान तेलंगाना राज्य केंद्र
ए-ब्लॉक, बी.आर.के.आर. भवन, टैंक बंड रोड
हैदराबाद, तेलंगाना – 500004
ईमेल: sio-tg@nic.in, फ़ोन: 040-23229474

शासन में साइबर सुरक्षा व गोपनीयता

साइबर सुरक्षा और डेटा का एकीकरण डी.पी.डी.पी अधिनियम, 2023 के तहत सुरक्षा

संपादित : **मोहन दास विस्वम्**

जब किसी अस्पताल का डिजिटल सिस्टम रैंसमवेयर हमले के कारण ठप हो जाता है या किसी नागरिक का आधार से जुड़ा डेटा ऑनलाइन लीक हो जाता है, तो नुकसान केवल खोई हुई फ़ाइलों तक ही सीमित नहीं रहता - यह जनता के विश्वास को भी कम करता है। ऐसी हर घटना हमें याद दिलाती है कि गोपनीयता के बिना साइबर सुरक्षा अधूरी है, और साइबर सुरक्षा के बिना गोपनीयता असंभव है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डी.पी.डी.पी) अधिनियम, 2023 देश की डिजिटल शासन यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। पहली बार, नागरिकों को अपने व्यक्तिगत डेटा पर लागू करने योग्य अधिकार प्राप्त हुए हैं, और संगठन इसकी सुरक्षा के लिए स्पष्ट दायित्वों से बंधे हैं। फिर भी, कानून पारित करना केवल शुरुआत है। असली चुनौती इस अधिनियम के उद्देश्य को दैनिक शासन में लागू करने में है - यह सुनिश्चित करना कि व्यक्तिगत डेटा न केवल कानूनी रूप से संसाधित हो, बल्कि उल्लंघनों, दुरुपयोग और लापरवाही से भी सुरक्षित रहे।

यहीं पर साइबर सूचना सुरक्षा शासन अपरिहार्य हो जाता है। लोगों, प्रक्रियाओं और तकनीक में संरचित जवाबदेही का निर्माण करके, यह कानूनी अनुपालन को परिचालन अनुशासन में बदल देता है। एक सुव्यवस्थित साइबर सुरक्षा ढाँचा यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सुरक्षा किसी उल्लंघन की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि प्रत्येक डिजिटल प्रणाली में अंतर्निहित एक संस्कृति है।

संक्षेप में, डी.पी.डी.पी अधिनियम कानूनी आधार प्रदान करता है, लेकिन साइबर शासन इसे कार्यान्वित करने के लिए शक्ति और स्मृति प्रदान करता है। साथ मिलकर, ये दोनों मिलकर एक गोपनीयता-प्रथम, साइबर-लचीले और नागरिक-विश्वास-संचालित डिजिटल भारत की नींव रखते हैं।

सी. जे. एन्टनी
उप महानिदेशक व एचओजी
antony@nic.in

मनोज के. कुलश्रेष्ठ
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
mkk@nic.in

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डी.पी.डी.पी) अधिनियम, 2023 नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा पर अधिकार स्थापित करता है और संगठनों को इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश देता है। हालाँकि, वास्तविक अनुपालन के लिए साइबर सूचना सुरक्षा शासन की आवश्यकता होती है - एक ऐसा ढाँचा जो सभी प्रणालियों, लोगों और प्रक्रियाओं में जवाबदेही, सतर्कता और अनुशासन को समाहित करता है। गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को एक शासन मॉडल के अंतर्गत एकीकृत करके, संगठन प्रतिक्रियाशील अनुपालन से सक्रिय विश्वास निर्माण की ओर बढ़ सकते हैं। क्षेत्र-विशिष्ट मॉडल, एकीकृत निगरानी और जवाबदेही की संस्कृति इस अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक हैं। अंततः, साइबर शासन डेटा सुरक्षा को एक कानूनी आवश्यकता से डिजिटल जिम्मेदारी, लचीलेपन और नागरिक विश्वास की संस्कृति में बदल देता है।

डी.पी.डी.पी के बाद साइबर गवर्नेंस क्यों मायने रखता है?

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डी.पी.डी.पी) अधिनियम, 2023 प्रत्येक संगठन के लिए अनिवार्य करता है कि वह व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए "उचित सुरक्षा उपाय" अपनाए। लेकिन सरकारी प्रणालियों, स्टार्ट-अप्स और सार्वजनिक प्लेटफार्मों के जटिल डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में, वास्तव में किसे उचित माना जाता है? अकेले तकनीक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। इसके लिए संरचना, जवाबदेही और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है - जो साइबर सूचना सुरक्षा शासन का मूल सार है।

साइबर शासन एक ऐसा ढाँचा प्रदान करता है जो अनुपालन को सुसंगतता में बदल देता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा व्यक्तिगत निर्णय या बाद में विचार करने पर न छोड़ी जाए, बल्कि संस्थान की योजना का हिस्सा बन जाए। खतरों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय, शासन जाँच और संतुलन की एक सक्रिय प्रणाली बनाता है जो सुरक्षा स्थिति की निरंतर निगरानी, मूल्यांकन और सुधार करती है।

अपने मूल में, साइबर गवर्नेंस कानून और प्रौद्योगिकी को अनुशासन के माध्यम से जोड़ता है। यह साइबर सुरक्षा नियंत्रणों को डी.पी.डी.पी के गोपनीयता सिद्धांतों के साथ संरेखित करता है डेटा न्यूनीकरण और उद्देश्य सीमा से लेकर उल्लंघन सूचना और सहमति प्रबंधन तक। परिणामस्वरूप एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है जहाँ प्रत्येक विभाग, विक्रेता और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म एक एकीकृत जवाबदेही मॉडल के तहत काम करता है।

साइबर सूचना सुरक्षा गवर्नेंस के प्रमुख आयामों में शामिल हैं:

- **प्रणालीगत अनुशासन:** स्पष्ट नीतियाँ, परिभाषित भूमिकाएँ और प्रलेखित प्रक्रियाएँ स्थापित करना ताकि तदर्थ या प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा प्रथाओं का स्थान लिया जा सके।
- **जोखिम प्राथमिकता:** वर्गीकरण और स्तरित सुरक्षा के माध्यम से संवेदनशील डेटा श्रेणियों - जैसे स्वास्थ्य, वित्तीय, या बायोमेट्रिक जानकारी - की सुरक्षा पहले करना।
- **निरंतर सतर्कता:** यह स्वीकार करना कि उल्लंघन अपरिहार्य हैं, लेकिन जब पता लगाने, प्रतिक्रिया और रिपोर्टिंग प्रणालियों का सुशासन हो, तो क्षति को रोका जा सकता है।
- **एकीकृत अनुपालन:** साइबर सुरक्षा उपायों को सीधे डी.पी.डी.पी दायित्वों में शामिल करना जैसे सूचित सहमति सुनिश्चित करना, डेटा संग्रह को न्यूनतम करना, और समय पर उल्लंघन का खुलासा करना।

संक्षेप में, साइबर गवर्नेंस डी.पी.डी.पी अनुपालन के लिए एक संचालन प्रणाली प्रदान करता है। यह संस्थानों को ज़िम्मेदारी से कार्य करने, त्वरित प्रतिक्रिया देने और आत्मविश्वास से उबरने की क्षमता प्रदान करता है - जिससे "उचित सुरक्षा" का सिद्धांत मापनीय, लेखापरीक्षित और स्थायी विश्वास में बदल जाता है।

वास्तविक जीवन के उदाहरण

कानून इरादे ज़ाहिर करते हैं; शासन क्रियान्वयन की परीक्षा लेता है। विभिन्न क्षेत्रों में, कई वास्तविक घटनाओं ने दिखाया है कि जब साइबर सुरक्षा और गोपनीयता ढाँचे अलग-अलग काम करते हैं, तो प्रणालियाँ कितनी नाज़ुक हो जाती हैं - और जब शासन उन्हें एक साथ बाँधता है, तो वे कितनी लचीली होती हैं।

2022 में हुए एम्स रैंसमवेयर हमले को ही लीजिए। एक जटिल घुसपैठ ने अस्पताल के सर्वरों को हफ़्तों तक ठप कर दिया, जिससे लाखों मरीज़ों के रिकॉर्ड की गोपनीयता को ख़तरा पैदा हो गया। पैच प्रबंधन, नेटवर्क विभाजन और समय पर प्रतिक्रिया के अभाव ने संकट को और बढ़ा दिया। डी.पी.डी.पी व्यवस्था के तहत, ऐसी घटना से डेटा संरक्षण बोर्ड और प्रभावित नागरिकों, दोनों को अनिवार्य उल्लंघन सूचनाएँ मिल जातीं - एक ऐसा परिदृश्य जो संरचित घटना शासन, ऑफ़लाइन बैकअप और परिभाषित एस्केलेशन चैनलों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

इसी तरह, कोविन डेटा एक्सपोज़र (2021-22) ने कमज़ोर एपीआई शासन के ख़तरों को उजागर किया। नाम, संपर्क नंबर और टीकाकरण की स्थिति जैसे व्यक्तिगत विवरण अनधिकृत इंटरफेस के माध्यम से सुलभ थे। सबक स्पष्ट है: एपीआई सुरक्षा और तृतीय-पक्ष निगरानी को मुख्य प्रशासनिक कार्यप्रणालियाँ बनना चाहिए, न कि तकनीकी बाद की सोच। डी.पी.डी.पी के तहत, व्यक्तिगत डेटा का अनधिकृत प्रकटीकरण प्रत्ययी कर्तव्य का उल्लंघन होगा, जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही और निवारण के दावे सामने आएंगे।

इसके विपरीत, डिजिलॉकर डिज़ाइन द्वारा शासन का एक सकारात्मक उदाहरण है। संग्रहीत दस्तावेज़ों को एन्क्रिप्ट करके, डेटा संग्रह को न्यूनतम करके, और नागरिकों को साझाकरण को नियंत्रित करने का अधिकार देकर, इसने पहले ही कई डी.पी.डी.पी सिद्धांतों को क्रियान्वित कर दिया है - जिनमें उद्देश्य सीमा, डेटा न्यूनतमीकरण और उपयोगकर्ता सहमति शामिल हैं। यह साबित करता है कि गोपनीयता-प्रथम संरचना तब प्राप्त की जा सकती है जब शासन डिज़ाइन का नेतृत्व करता है, न कि जब वह विनियमन का अनुसरण करता है।

वैश्विक अनुभव भी मूल्यवान संकेत प्रदान करते हैं। 2023 में, मेटा पर जीडीपीआर के तहत €1.2 बिलियन का जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि उसने उपयोगकर्ता डेटा को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित कर दिया था। यह मामला एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि सीमा पार डेटा प्रशासन एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है - यह विश्वास की आधारशिला है। वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रहे भारतीय संगठनों के लिए, डी.पी.डी.पी के सीमा पार स्थानांतरण प्रावधानों का अनुपालन इसी तरह की कठोरता की मांग करेगा।

ये सभी उदाहरण एक सिद्धांत पर केंद्रित हैं: साइबर प्रशासन अनुपालन को संस्कृति में बदल देता है। जहाँ प्रशासन कमजोर था, उल्लंघन संकट में बदल गए; जहाँ प्रशासन मजबूत था, विश्वास स्वाभाविक हो गया।

क्षेत्र-विशिष्ट शासन साइबर और डेटा सुरक्षा के लिए मॉडल

कोई भी दो क्षेत्र एक जैसे जोखिमों का सामना नहीं करते। मरीज़ों के रिकॉर्ड के प्रति अस्पताल की ज़िम्मेदारी, वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित रखने के बैंक के दायित्व या ग्राहक की पहचान की सुरक्षा के दूरसंचार ऑपरेटर के कर्तव्य से मौलिक रूप से भिन्न होती है। डी.पी.डी.पी अधिनियम संदर्भ-विशिष्ट सुरक्षा उपायों की माँग करके इस विविधता को स्वीकार करता है - एक सिद्धांत जो साइबर शासन के मूल में है।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, रैंसमवेयर और पहचान की चोरी सबसे बड़े खतरे बने हुए हैं। अस्पतालों और टेलीमेडिसिन प्रदाताओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के रूप में वर्गीकृत करना होगा, मरीजों के रिकॉर्ड को एन्क्रिप्ट करना होगा, और नियमित रूप से गोपनीयता प्रभाव आकलन (पीआईए) करना होगा। एम्स की घटना ने दिखाया कि नेटवर्क विभाजन और अनुशासित पैचिंग के बिना, महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थानों को भी लंबे समय तक व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है।

वित्तीय क्षेत्र आरबीआई और अब डी.पी.डी.पी की दोहरी नियामक निगरानी में काम करता है। यहाँ, शासन का अर्थ है शून्य विश्वास संरचना को अपनाना, बहु-कारक प्रमाणीकरण लागू करना और समय-समय पर तनाव परीक्षण करना। 2018 में कॉसमॉस बैंक साइबर डकैती ने उजागर किया कि कैसे अनियंत्रित एंडपॉइंट और कमज़ोर विक्रेता निगरानी अच्छी तरह से विनियमित संस्थाओं को भी खतरे में डाल सकती है।

दूरसंचार और डिजिटल संचार में, ध्यान डेटा न्यूनीकरण और विक्रेता शासन पर केंद्रित होना चाहिए। दूरसंचार ऑपरेटर भारी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा संभालते हैं - कॉल लॉग से लेकर जियोलोकेशन ट्रेल्स तक - जिससे वैध इंटरसेप्शन नीतियाँ और सीमा-पार डेटा सुरक्षा उपाय अपरिहार्य हो जाते हैं। वोडाफ़ोन यूके के जीडीपीआर जुर्माने जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामले, कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण और अपर्याप्त पारदर्शिता के जोखिमों को दर्शाते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र और ई-गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म नागरिक विश्वास के केंद्र में हैं। आधार, कोविन और डिजिलॉकर जैसे प्लेटफ़ॉर्म बड़े पैमाने की डेटा प्रणालियों की कमज़ोरियों और मज़बूतियों, दोनों को प्रदर्शित करते हैं। डिज़ाइन द्वारा गोपनीयता को एकीकृत करना,

▼ तालिका 11.1 **वास्तविक जीवन के उदाहरण**

मामला	शासन पाठ	डी.पी.डी.पी प्रासंगिकता / मुख्य बातें
एम्स रैंसमवेयर हमला (2022)	कमजोर पैचिंग और विलंबित प्रतिक्रिया ने अस्पताल प्रणालियों को पंगु बना दिया।	डीपीबी को उल्लंघन की अनिवार्य रिपोर्टिंग; नेटवर्क विभाजन, ऑफलाइन बैकअप और घटना प्रशासन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
कोविन डेटा एक्सपोज़र (2021-22)	अपर्याप्त एपीआई प्रशासन के कारण अनाधिकृत डेटा तक पहुंच संभव हुई।	अनधिकृत प्रकटीकरण से प्रत्ययी कर्तव्य का उल्लंघन होता है; मजबूत एपीआई सुरक्षा और तृतीय-पक्ष ऑडिट पर जोर दिया जाता है।
डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म	एन्क्रिप्शन, न्यूनतम डेटा संग्रहण, तथा नागरिक-नियंत्रित साझाकरण, डिजाइन द्वारा गोपनीयता सुनिश्चित करते हैं।	डी.पी.डी.पी सिद्धांतों का आदर्श उदाहरण - सहमति, उद्देश्य सीमा, और कार्रवाई में डेटा न्यूनतमीकरण।
मेटा जीडीपीआर जुर्माना (2023)	डेटा स्थानांतरण में सीमा पार सुरक्षा उपायों का अभाव।	भारतीय संस्थाओं को इसी प्रकार के दंड से बचने के लिए डी.पी.डी.पी के अंतर्गत वैध हस्तांतरण नियंत्रण लागू करना होगा।

साइबर सुरक्षा + गोपनीयता = डिजिटल विश्वास

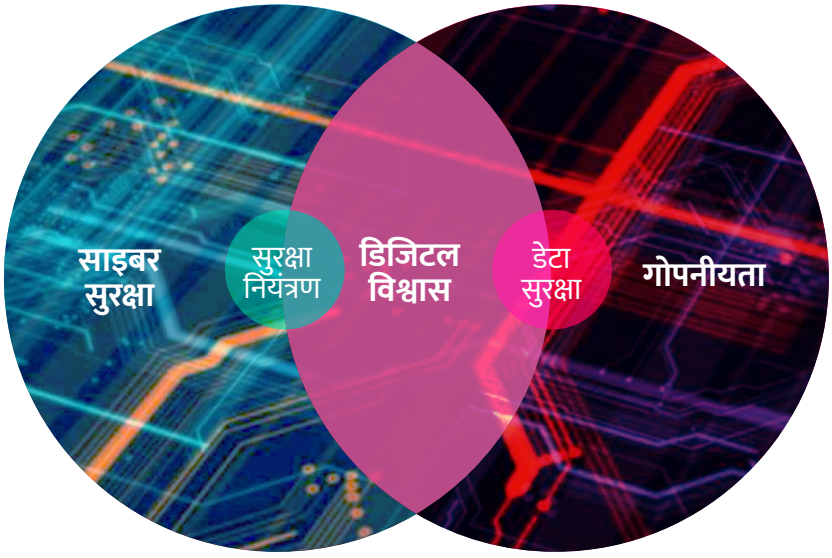

▼ तालिका 11.2 **साइबर और डेटा सुरक्षा के लिए क्षेत्र-विशिष्ट शासन मॉडल**

सेक्टर	प्रमुख जोखिम	शासन प्राथमिकता	उदाहरण/पाठ
स्वास्थ्य देखभाल	रैनसमवेयर, पहचान की चोरी, अनधिकृत अनुसंधान उपयोग	स्वास्थ्य डेटा को एन्क्रिप्ट करें, पहुंच को प्रतिबंधित करें, संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत करें, गोपनीयता प्रभाव आकलन करें	एम्स रैनसमवेयर हमला - खंडित नेटवर्क और समय पर प्रतिक्रिया की आवश्यकता
वित्तीय सेवाएं	धोखाधड़ी, फ़िशिंग, अंदरूनी दुरुपयोग	शून्य विश्वास संरचना अपनाएं, बहु-कारक प्रमाणीकरण लागू करें, आरबीआई और डी.पी.डी.पी मानदंडों के साथ संरेखित करें	कॉसमॉस बैंक डकैती - एंडपॉइंट निगरानी और मजबूत विक्रेता निरीक्षण आवश्यक
दूरसंचार और डिजिटल संचार	सिम स्वैप, डेटा दुरुपयोग, निगरानी	विक्रेता प्रशासन को मजबूत करें, डेटा न्यूनीकरण लागू करें, वैध अवरोधन अनुपालन सुनिश्चित करें	वोडाफोन यूके जीडीपीआर जुर्माना - पारदर्शी ग्राहक डेटा के लिए शासन
ई-गवर्नेंस / सार्वजनिक क्षेत्र	एपीआई लीक, बड़े पैमाने पर डेटा एक्सपोज़र	डिज़ाइन द्वारा गोपनीयता को एकीकृत करें, निगरानी को केंद्रीकृत करें, सीईआरटी-इन रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें	कोविन एक्सपोजर बनाम डिजिलॉकर का एन्क्रिप्शन - शासन परिपक्वता के विपरीत परिणाम
शिक्षा	बाल डेटा शोषण, प्रोफाइलिंग, पहचान की चोरी	सुरक्षित शिक्षण प्लेटफ़ॉर्म, नाबालिगों के लिए माता-पिता की सहमति, सख्त एडटेक विक्रेता ऑडिट	एडमोडो उल्लंघन - सुरक्षा की आवश्यकता दीक्षा और स्वयम् उपयोगकर्ता डेटा
महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा	रैनसमवेयर, तोड़फोड़, राष्ट्रीय व्यवधान	आईटी/ओटी नेटवर्क को अलग करें, एनसीआईआईपीसी फ्रेमवर्क अपनाएँ, रेड-टीम अभ्यास चलाएँ	औपनिवेशिक पाइपलाइन हमला - भारत के स्मार्ट ग्रिड लचीलेपन का मुख्य उदाहरण
एआई और उभरती हुई तकनीक स्टार्टअप्स	पुनः पहचान, पूर्वाग्रह, बिना सहमति के डेटा का उपयोग	गोपनीयता-संरक्षण एआई को लागू करें, सहमति प्राप्त डेटासेट सुनिश्चित करें, ऑडिट ट्रेल्स बनाए रखें	एआई मॉडल के दुरुपयोग के मामले - डी.पी.डी.पी के साथ संरेखित नैतिक एआई प्रशासन की आवश्यकता

सीईआरटी-इन रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना और केंद्रीकृत शासन बोर्ड बनाना अब सभी सरकारी डेटा प्रणालियों के लिए अनिवार्य है।

शिक्षा के क्षेत्र में, छात्रों के डेटा की सुरक्षा विशेषकर नाबालिगों के लिए अभिभावकों की सहमति के ढाँचे, सुरक्षित शिक्षण प्रबंधन प्रणालियों (एलएमएस) और एडटेक सहयोगों में विक्रेताओं की कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है। एडमोडो उल्लंघन, जिसने लाखों छात्रों के रिकॉर्ड उजागर किए, इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत के दीक्षा और स्वयं प्लेटफ़ॉर्म को मज़बूत शासन स्तर क्यों विकसित करने चाहिए।

महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के लिए, जोखिम अस्तित्वगत हैं। पावर ग्रिड, परिवहन नेटवर्क और स्मार्ट सिटी सिस्टम आईटी और परिचालन तकनीक (ओटी) के मिश्रण पर निर्भर करते हैं। यहाँ शासन का अर्थ है सख्त नेटवर्क पृथक्करण, वास्तविक समय निगरानी, और एनसीआईआईपीसी ढाँचों के अनुरूप रेड-टीम अभ्यास। अमेरिका में कोलोनियल पाइपलाइन हमला एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है: एक भी उल्लंघन पूरी राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकता है।

अंततः, एआई और उभरती हुई प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नए शासन के आयाम प्रस्तुत करते हैं। प्रशिक्षण डेटासेट, व्यवहार विश्लेषण और जनरेटिव मॉडल नई गोपनीयता चुनौतियाँ खड़ी करते हैं - पुनः-पहचान जोखिमों से लेकर एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह तक। इन संस्थाओं के लिए डी.पी.डी.पी अनुपालन गोपनीयता-संरक्षण एआई तकनीकों, पारदर्शी मॉडल शासन और प्रशिक्षण प्रणालियों में डेटा के उपयोग के लिए स्पष्ट सहमति पर निर्भर करेगा।

सभी क्षेत्रों में, एक सच्चाई कायम है: शासन को अनुकूलित होना चाहिए, लेकिन जवाबदेही पूर्ण बनी रहती है।

एक गोपनीयता-जागरूक शासन मॉडल न केवल प्रणालियों की रक्षा करता है - यह नागरिकों और उनकी सेवा करने वाली संस्थाओं के बीच सामाजिक अनुबंध को भी मजबूत करता है।

डी.पी.डी.पी के बाद के युग में प्रमुख शासन क्षेत्र

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डी.पी.डी.पी) अधिनियम, 2023 केवल एक कानून नहीं है - यह एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर है जो हमारे देश में संगठनों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के संचालन, प्रसंस्करण और सुरक्षा के तरीके को नया रूप देता है। यह अनुपालन-आधारित डेटा प्रबंधन से जवाबदेही-संचालित शासन की ओर एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है, जहाँ नागरिकों के डेटा की सुरक्षा एक रणनीतिक आवश्यकता और नैतिक दायित्व दोनों बन जाती है।

इस नए युग में, साइबर सुरक्षा को अब केवल तकनीकी या आईटी चिंता के रूप में नहीं देखा जाता। यह एक प्राथमिक प्राथमिकता बन गई है, जिसके लिए अनुपालन टीमों, वरिष्ठ प्रबंधन और व्यावसायिक नेतृत्व की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। यह अधिनियम संगठनों को ऐसी संरचनाएँ बनाने के लिए बाध्य करता है जो कानूनी जागरूकता, तकनीकी लचीलापन और संगठनात्मक संस्कृति का मिश्रण हों।

इस बदलाव को क्रियान्वित करने के लिए, आधुनिक शासन को छह परस्पर जुड़े क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

ये सभी मिलकर एक गोपनीयता-प्रथम और साइबर-सुरक्षित संगठन की नींव रखते हैं, जो डेटा को एक वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि एक साझा राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में देखता है जिसकी देखभाल उसे सौंपी जाती है।

एकीकृत शासन ढाँचे

ऐसी दुनिया में जहाँ डेटा निर्बाध रूप से सिस्टम, विक्रेताओं और सीमाओं के बीच प्रवाहित होता है, खंडित नियंत्रण अब काम नहीं करते। संगठनों को एक एकल, एकीकृत शासन ढाँचे की आवश्यकता है जो गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को एक मॉडल के अंतर्गत एकीकृत करे।

डेटा परिसंपत्तियों का मानचित्रण, स्वामित्व का निर्धारण, और विभागों में नीतियों का संरेखण, सीआईएसओ और डीपीओ के बीच साझा जवाबदेही सुनिश्चित करता है। एकीकृत एन्क्रिप्शन मानक, केंद्रीकृत निगरानी, और एकीकृत रिपोर्टिंग, अलग-थलग प्रथाओं का स्थान लेते हैं, जिससे संगठनों को अनुपालन से वास्तविक डेटा प्रबंधन की ओर बढ़ने में मदद मिलती है।

उल्लंघन प्रतिक्रिया और रिपोर्टिंग

डी.पी.डी.पी अधिनियम और सीईआरटी-इन के निर्देशों के तहत, उल्लंघनों की तुरंत सूचना दी जानी चाहिए - नियामकों और प्रभावित नागरिकों दोनों को। एक मज़बूत उल्लंघन प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए स्पष्ट कार्यवाही पथ, फोरेंसिक तत्परता और पारदर्शी संचार की आवश्यकता होती है।

घटना प्रतिक्रिया को गोपनीयता दायित्वों के साथ एकीकृत करने से खतरों का पता लगाने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद मिलती है, साथ ही जनता का विश्वास भी बना रहता है। एक डिजिटल लोकतंत्र में, कोई संगठन उल्लंघन पर कितनी तेज़ी और कितनी ईमानदारी से प्रतिक्रिया देता है, यह उसकी विश्वसनीयता को परिभाषित करता है।

विक्रेता और तृतीय-पक्ष निरीक्षण

अधिकांश आधुनिक उल्लंघन विक्रेताओं या आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से होते हैं। डी.पी.डी.पी अधिनियम डेटा प्रभावित नागरिकों को अपने भागीदारों की चूकों के लिए ज़िम्मेदार ठहराता है, जिससे विक्रेता प्रशासन एक अनिवार्य प्राथमिकता बन जाता है।

सशक्त निरीक्षण में ऑनबोर्डिंग से पहले उचित परिश्रम, अनुबंधों में अनुपालन संबंधी प्रावधानों को शामिल करना, नियमित ऑडिट करना और विक्रेताओं की निरंतर निगरानी करना शामिल है। विक्रेताओं को जोखिम कारकों के बजाय विश्वास भागीदार बनाना संस्थागत लचीलेपन को मज़बूत करता है।

डेटा जीवनचक्र शासन

डेटा सुरक्षा केवल संग्रहण तक ही सीमित नहीं है, इसे संपूर्ण जीवनचक्र में, निर्माण से लेकर विलोपन तक, विस्तारित होना चाहिए। स्पष्ट अवधारण कार्यक्रम, उपयोग के दौरान एन्क्रिप्शन, और समाप्ति के बाद स्वचालित विलोपन, डेटा न्यूनीकरण के सिद्धांत को जीवंत बनाते हैं।

ऐसा जीवनचक्र शासन यह सुनिश्चित करता है कि संगठन केवल वही रखें जिसकी उन्हें आवश्यकता है, केवल वही संसाधित करें जो वैध है, और डेटा का जिम्मेदारी से निपटान करें - नीति को दैनिक अनुशासन में परिवर्तित करना।

सिसो सहयोग

डी.पी.डी.पी के बाद का युग साइबर सुरक्षा और गोपनीयता कार्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग की माँग करता है। सिसो यह सुनिश्चित करता है कि डेटा की सुरक्षा कैसे की जाए; डीपीओ यह निर्धारित करता है कि इसे क्यों और कितने समय के लिए एकत्र किया जाए।

संयुक्त समीक्षा, साझा ऑडिट और समन्वित जोखिम आकलन सुरक्षा और अनुपालन लक्ष्यों को एकीकृत करने में मदद करते हैं। ये सभी मिलकर एक सुसंगत जवाबदेही ढाँचा बनाते हैं जो सुरक्षा और उद्देश्य के बीच संतुलन बनाता है।

जवाबदेही की संस्कृति

प्रौद्योगिकी प्रणालियों को सुरक्षित कर सकती है, लेकिन केवल संस्कृति ही संगठनों को सुरक्षित करती है। नियमित जागरूकता सत्र, फ़िशिंग अभ्यास और पासवर्ड स्वच्छता अभियान कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति के रक्षक बनाते हैं।

जब हर टीम - विक्रेताओं से लेकर नागरिकों से जुड़ी इकाइयों तक - डेटा को एक साझा ज़िम्मेदारी मानती है, तो शासन अनुपालन से संस्कृति की ओर विकसित होता है।

संक्षेप में, ये छह स्तंभ विश्वसनीय डिजिटल शासन की नींव रखते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि डेटा सुरक्षा एक बार का अनुपालन कार्य नहीं है, बल्कि एक जीवंत अभ्यास है - जो गोपनीयता को एक कानूनी अनिवार्यता से एक राष्ट्रीय मूल्य में बदल देता है और एक लचीले और विश्वसनीय डिजिटल भारत का आधार बनता है।

चुनौतियाँ

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डी.पी.डी.पी) अधिनियम, 2023 को नीति से व्यवहार में लागू करना नए नियमों का मसौदा तैयार करने से कम और संस्थाओं के व्यवहार को बदलने से ज़्यादा है। हालाँकि यह कानून दिशा प्रदान करता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई परिचालनात्मक और सांस्कृतिक बाधाएँ हैं जिनका समाधान साइबर शासन को सही मायने में स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए।

"उचित सुरक्षा उपायों" की परिभाषा

"उचित सुरक्षा उपायों" के लिए अधिनियम की आवश्यकता लचीलापन प्रदान करती है, लेकिन साथ ही अस्पष्टता भी। ठोस मानदंडों के बिना, व्याख्याएँ काफ़ी भिन्न हो सकती हैं - कुछ संगठन सुरक्षा में कम निवेश कर सकते हैं, जबकि अन्य अनावश्यक नियंत्रणों पर ज़्यादा खर्च कर सकते हैं।

एकरूपता लाने के लिए, संगठनों को अपने शासन को वैश्विक मानकों जैसे आईएसओ 27001 (सूचना सुरक्षा), आईएसओ 27701 (गोपनीयता सूचना प्रबंधन), या एन.आई.एस.टी. साइबर सुरक्षा ढाँचे पर आधारित करना चाहिए। सी.ई.आर.टी.-इन के निर्देशों के साथ संरेखित होने पर, ये मानक "उचित" को मापने योग्य, लेखापरीक्षा योग्य और लागू करने योग्य सुरक्षा उपायों में बदल देते हैं।

लागत और अनुपालन में संतुलन

छोटे संगठनों के लिए, अनुपालन एक महंगा प्रस्ताव लग सकता है। एन्क्रिप्शन सिस्टम लागू करना, ऑडिट करना, या डेटा अधिकारियों की नियुक्ति करना वास्तविक वित्तीय और मानवीय लागतों से जुड़ा होता है।

एक चरणबद्ध अनुपालन मॉडल एक व्यावहारिक मार्ग प्रदान करता है - उच्च-जोखिम वाले डेटा और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देना। सरकार साझा सुरक्षा ढाँचे, अनुपालन टूलकिट और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है जो गोपनीयता सुरक्षा को सभी संगठनों के लिए समावेशी और साध्य बनाते हैं, न कि केवल अच्छी तरह से संसाधन संपन्न संगठनों के लिए।

कौशल अंतर को पाटना

भारत के डेटा गवर्नेंस इकोसिस्टम में दोहरी कमी है - साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की जो कानून को समझते हैं और वकीलों की जो तकनीक को समझते हैं। यह कौशल अंतर विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर अनुपालन परिपक्वता में बाधा डालता है।

इससे निपटने के लिए, एनआईसी, एमईआईटीवाई और एन.सी.आई.आई.पी.सी. को क्षमता निर्माण में निरंतर प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिए और सिसो, डीपीओ और सरकारी अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने चाहिए। विश्वविद्यालयों और प्रमाणन निकायों के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी, उद्योगों में डी.पी.डी.पी अधिनियम को लागू करने में सक्षम कुशल पेशेवरों की एक स्थिर पाइपलाइन सुनिश्चित कर सकती है।

नियामक ओवरलैप का प्रबंधन

कई क्षेत्र पहले से ही कई डेटा सुरक्षा व्यवस्थाओं का अनुपालन करते हैं - आईटी अधिनियम और सीईआरटी-इन के निर्देशों से लेकर आरबीआई, आईआरडीएआई और सेबी के दिशानिर्देशों तक। डी.पी.डी.पी को जोड़ने से नियामक भ्रम या "अनुपालन थकान" पैदा होने का खतरा है।

इसका समाधान सामंजस्यपूर्ण शासन ढांचे में निहित है जो इन सभी दायित्वों को प्रतिस्पर्धी के बजाय पूरक के रूप में मानते हैं। ओवरलैप का मानचित्रण करके, संगठन रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, ऑडिट को एकीकृत कर सकते हैं, और एक एकल जवाबदेही संरचना स्थापित कर सकते हैं जो सभी नियामक अपेक्षाओं को सुसंगत रूप से संरेखित करती है।

प्रारंभिक प्रवर्तन का मार्गदर्शन

डी.पी.डी.पी का कार्यान्वयन तब विकसित होगा जब डेटा संरक्षण बोर्ड अपने पहले निर्णय जारी करेगा। तब तक, अनुपालन अपेक्षाएँ अस्थिर बनी रह सकती हैं।

सबसे अच्छी रणनीति सक्रिय दस्तावेज़ीकरण है - शासन संबंधी कार्रवाइयों, जोखिम आकलन और उल्लंघन प्रतिक्रियाओं का रिकॉर्ड रखना – ताकि नियामक अनिश्चितता के बीच भी उचित परिश्रम प्रदर्शित किया जा सके।

डी.पी.डी.पी के बाद साइबर शासन एक यात्रा है, कोई चेकलिस्ट नहीं। चुनौतियाँ वास्तविक हैं, लेकिन हर एक-एक अवसर प्रदान करती है - स्पष्ट मानक निर्धारित करने, संस्थागत क्षमता को मज़बूत करने और डिजिटल प्रणालियों में जवाबदेही को गहराई से समाहित करने का। कानून अधिदेश को परिभाषित करता है; शासन उसे जीवन देता है।

अग्रिम दिशा

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डी.पी.डी.पी) अधिनियम, 2023 के उद्देश्य को सही मायने में सार्वजनिक विश्वास में बदलने के लिए, संगठनों को गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को अपने शासन के डीएनए में शामिल करना होगा। अनुपालन को एक चेकलिस्ट के रूप में नहीं, बल्कि हर निर्णय को निर्देशित करने वाली मानसिकता के रूप में देखा जाना चाहिए। यह परिवर्तन एकीकृत शासन से शुरू होता है - जहाँ सीआईओ, सिसो और डीपीओ तकनीक, नीति और जवाबदेही को संरेखित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। आईएसओ 27001 और 27701 जैसे हाइब्रिड फ्रेमवर्क द्वारा समर्थित नियमित गोपनीयता और सुरक्षा प्रभाव आकलन, जोखिमों का प्रबंधन करने और तकनीकी एवं गोपनीयता मानकों को एकीकृत करने में मदद कर सकते हैं। AI-संचालित निगरानी निरंतर सतर्कता सुनिश्चित करनी चाहिए, जबकि गोपनीयता-द्वारा-डिज़ाइन सिद्धांत सुरक्षा को सिस्टम विकास का एक अभिन्न अंग बनाते हैं। एनआईसी, सी.ई.आर.टी.-इन और क्षेत्रीय नियामकों के साथ घनिष्ठ सहयोग अनुपालन में और अधिक सामंजस्य स्थापित करेगा और संस्थागत विश्वास को मजबूत करेगा।

अंततः, डी.पी.डी.पी के बाद का युग केवल कानूनी अनुपालन के बारे में नहीं है, बल्कि नागरिकों के विश्वास का निर्माण करने के बारे में है। साइबर सुरक्षा और गोपनीयता को नियामक बोझ से डिजिटल ज़िम्मेदारी की संस्कृति में विकसित होना होगा। एक सच्चा डिजिटल राष्ट्र इस बात से परिभाषित नहीं होता कि वह कितने उपकरणों से जुड़ा है, बल्कि इस बात से परिभाषित होता है कि वह प्रत्येक जुड़े हुए नागरिक को सुरक्षा, सम्मान और विश्वास प्रदान करता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

सी.जे. एंटनी
उप महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
साइबर एवं सूचना सुरक्षा प्रशासन प्रभाग
एनआईसी मुख्यालय, ए-ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
ईमेल: antony@nic.in, फ़ोन: 011-24305740

आधुनिक समय की साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ

आधुनिक साइबर सुरक्षा चुनौतियों की जानकारी रखकर स्वयं को सुरक्षित रखें

संपादित : **मोहन दास विस्वम्**

परिष्कृत साइबर खतरों, बढ़े हुए नियमन और तेज़ी से विकसित हो रही तकनीक के कारण साइबर सुरक्षा का परिदृश्य लगातार जटिल होता जा रहा है। संगठनों को अपने उपयोगकर्ताओं की संवेदनशील जानकारी की रक्षा करने के साथ-साथ सहज और आसान उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करना जारी रखने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यहाँ उन उभरती चुनौतियों और खतरों पर करीब से नज़र डाली गई है जो इस वर्ष सुरक्षा परिदृश्य को आकार देने के लिए तैयार हैं :

एआई-संचालित सामाजिक इंजीनियरिंग खतरे

एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की उन्नति के साथ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) और मशीन लर्निंग (एमएल) पर आधारित एल्गोरिदम का उपयोग करके अत्यधिक विश्वसनीय फ़िशिंग अभियान बनाए जा रहे हैं और डीपफेक तैयार किए जा रहे हैं, जो साइबर हमलों को स्वचालित कर रहे हैं। एआई, सोशल मीडिया प्रोफाइल, ऑनलाइन इंटरैक्शन और लीक हुए डेटा का विश्लेषण करके ऐसे संदेश उत्पन्न कर सकता है जो अधिक प्रामाणिक, लक्षित और विश्वसनीय लगते हैं। हमलावर कंपनी के अधिकारियों का प्रतिरूपण करने वाले विश्वसनीय ऑडियो और वीडियो डीपफेक आसानी से बना सकते हैं ताकि कर्मचारियों को धन हस्तांतरित करने या संवेदनशील गोपनीय जानकारी का खुलासा करने के लिए धोखा दिया जा सके। एआई, कई और अद्वितीय लक्षित संदेशों, प्रतिक्रियाओं या परिदृश्यों को उत्पन्न करके बड़े पैमाने पर सोशल इंजीनियरिंग अभियानों को स्वचालित कर सकता है, जिससे मैनुअल प्रयास की आवश्यकता कम हो जाती है और हमलों की मात्रा बढ़ जाती है।

डिजिटल बुनियादी ढांचे में गलत कॉन्फ़िगरेशन

क्लाउड वातावरण में गलत कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि पहुँच नियंत्रण

आर. बिंदू माधवी
वैज्ञानिक - डी
r.bindumadhavi@nic.in

ए. रमादेवी
वैज्ञानिक - डी
rama.a@nic.in

साइबर खतरे तेज़ी से विकसित हो रहे हैं क्योंकि हमलावर अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं और दुनिया भर में जुड़े हुए उपकरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रिमोट वर्क और क्लाउड को अपनाने में वृद्धि के साथ, अंतिम बिंदु और डेटा प्रवाह आकर्षक हमले के लक्ष्य बन जाते हैं। इस लेख में, हमने वैश्विक संगठनों को प्रभावित करने वाले नवीनतम साइबर सुरक्षा रुझानों का पता लगाया है, और सूचित रहना आपके जोखिम को कम कर सकता है।

का न होना, असुरक्षित भंडारण स्थान और सुरक्षा नीतियों का अप्रभावी कार्यान्वयन, डेटा उल्लंघनों के सबसे सामान्य कारण हैं। गलत कॉन्फ़िगरेशन हमलावरों को अपनी पहचान छिपाकर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग जैसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के लिए क्लाउड संसाधनों का अपहरण करने और समझौता किए गए क्लाउड खातों से साइबर हमले शुरू करने में सक्षम बनाता है। कमजोर या अत्यधिक अनुमेय पहुँच प्रबंधन नीतियां उपयोगकर्ताओं या तीसरे पक्ष को उचित सत्यापन के बिना महत्वपूर्ण क्लाउड संसाधनों तक पहुँचने की अनुमति दे सकती हैं, जिससे हमलावरों को इन विशेषाधिकारों का शोषण करने का रास्ता मिल जाता है। क्लाउड सेवाएँ ऐसे एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) को उजागर कर सकती हैं जो सुरक्षित नहीं हैं या जिन्हें अत्यधिक अनुमतियाँ दी गई हैं, जिससे हमलावरों के लिए उनका फायदा उठाना और क्लाउड संसाधनों तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त करना आसान हो जाता है।

मोबाइल उपकरण शोषण

मोबाइल उपकरणों पर बढ़ती निर्भरता के साथ, आने वाले दिनों में इन प्लेटफार्मों पर हमलों में पर्याप्त वृद्धि होने की उम्मीद है। इसमें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऐप और 5G जैसी मोबाइल-केंद्रित तकनीकों में कमजोरियों का फायदा उठाना शामिल है। मोबाइल मैलवेयर में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, और यह प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि मोबाइल उपकरणों का उपयोग बैंकिंग, खरीदारी और संवेदनशील जानकारी तक पहुँचने के लिए तेजी से किया जा रहा है। समझौता की गई कुंजी के साथ, हमलावर एक मैन-इन-द-मिडिल अटैक में एक सुरक्षित एच.टी.टी.पी.एस. कनेक्शन को एक गैर-एन्क्रिप्टेड एचटीटीपी कनेक्शन में डाउनग्रेड कर सकते हैं, जिससे वे नेटवर्क पर प्रसारित होते समय संवेदनशील जानकारी (जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर) चुरा सकते हैं। जेलब्रोकन (आईओएस) या रूटेड (एंड्रॉयड) मोबाइल उपकरण हमलावरों को अनधिकृत ऐप या सॉफ़्टवेयर स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं और इस प्रकार उपकरण को विभिन्न हमलों के लिए खोल देते हैं।

आईओटी उपकरण की कमजोरियाँ

आईओटी उपकरण (इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण) में अक्सर मज़बूत सुरक्षा की कमी पाई जाती है, जिससे वे हमलावरों के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं जो बॉटनेट्स या अन्य दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए उपकरणों का अपहरण करना चाहते हैं। स्मार्ट कैमरे और पहनने योग्य उपकरण जैसे आईओटी उपकरण व्यक्तिगत डेटा एकत्र करते हैं। यदि इन पर समझौता होता है, तो ये उपकरण संवेदनशील जानकारी को उजागर कर सकते हैं या निगरानी के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। आईओटी उपकरण अक्सर कमजोर एन्क्रिप्शन या असुरक्षित संचार प्रोटोकॉल पर निर्भर करते हैं, जिससे वे अवरोधन और शोषण के शिकार हो जाते हैं। समझौता किए गए आईओटी उपकरणों का उपयोग अक्सर डीडॉस हमलों जैसे बड़े पैमाने पर बॉटनेट हमलों में किया जाता है जो नेटवर्क और सर्वर को अभिभूत कर देते हैं। हमलावर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के लिए अपनी प्रोसेसिंग पावर का उपयोग करने हेतु आईओटी उपकरणों का अपहरण कर सकते हैं। स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, कैमरे और यहाँ तक कि गणना शक्ति वाले चिकित्सा उपकरण का भी क्रिप्टो माइनिंग के लिए शोषण किया जा सकता है, जिससे सिस्टम धीमा हो सकता है, हार्डवेयर को नुकसान हो सकता है और बिजली की खपत बढ़ सकती है।

अंदरूनी खतरे

जैसे-जैसे व्यवसाय तेज़ी से डिजिटल और अंतर्संबंधित होते जा रहे हैं, अंदरूनी लोगों - संगठन के भीतर के वे व्यक्ति जिनकी सिस्टम और डेटा तक पहुँच है - से उत्पन्न ख़तरा एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। कर्मचारी अनजाने में गलत प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजकर, क्लाउड सेटिंग्स को गलत तरीके से कॉन्फ़िगर करके, या सुरक्षित संचार विधियों का उपयोग न करके संवेदनशील जानकारी उजागर कर सकते हैं। असंतुष्ट कर्मचारी जानबूझकर कंपनी के

सिस्टम में तोड़फोड़ कर सकते हैं, डेटा चुरा सकते हैं, या संचालन में बाधा डाल सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या वे अपने नियोक्ता से असंतुष्ट हैं। ठेकेदार और विक्रेता, जो स्थायी कर्मचारियों के समान सुरक्षा प्रोटोकॉल के अधीन नहीं हैं, एक कमज़ोर कड़ी हो सकते हैं। दूर से काम करने वाले या व्यक्तिगत उपकरणों (बीवायओडी) का उपयोग करने वाले कर्मचारी अनजाने में कंपनी नेटवर्क को दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर या हमलावरों के सामने उजागर कर सकते हैं यदि उनके उपकरण और पहुँच ठीक से सुरक्षित नहीं हैं। दूरस्थ कर्मचारी असुरक्षित नेटवर्क से सिस्टम तक पहुँच सकते हैं, जिससे अनधिकृत व्यक्तियों के लिए डेटा को इंटरसेप्ट करना या कॉर्पोरेट संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करना आसान हो जाता है।

एन्क्रिप्शन-रहित रैंसमवेयर हमले

एन्क्रिप्शन-रहित रैंसमवेयर हमले एक नए और विकसित हो रहे खतरे का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ हमलावर फ़ाइलों को एन्क्रिप्ट करने की पारंपरिक विधि पर निर्भर किए बिना पीड़ितों से फिरौती वसूलते हैं। डेटा को लॉक करने और डिक्रिप्शन कुंजी के लिए फिरौती की माँग करने के बजाय, इन हमलों में आमतौर पर संवेदनशील जानकारी की चोरी या सिस्टम को इस तरह से बाधित करना शामिल होता है जिससे कम तत्काल परिचालन व्यवधान होता है। इस प्रकार हमलावर लंबे समय तक पता चले बिना काम करते हैं, संवेदनशील जानकारी जुटाते हैं और फिर फिरौती का भुगतान न करने पर उसे प्रकाशित करने की धमकी देते हैं। भले ही डेटा एन्क्रिप्टेड न हो, परिणाम फिर भी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि वे महत्वपूर्ण व्यावसायिक संपत्तियों को लक्षित करते हैं और गोपनीयता से समझौता करते हैं। हमलावर रिमोट एक्सेस ट्रोजन या फ़ाइल-रहित मैलवेयर जैसे टूल तैनात करके डेटा एक्सफ़िल्ट्रेशन के अपने तरीकों में अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं, ताकि पारंपरिक पहचान प्रणालियों को ट्रिगर किए बिना डेटा चुराया जा सके। 'रैंसमवेयर-एज-ए-सर्विस' मॉडल, जो कम कुशल हमलावरों को भी विनाशकारी रैंसमवेयर अभियान शुरू करने में सक्षम बनाता है, एक और सुरक्षा चुनौती है जो आधुनिक समय में बढ़ रही है।

डीएनएस टनलिंग खतरे

डोमेन नाम प्रणाली (डीएनएस) ट्रैफ़िक को अक्सर नेटवर्क संचार के सुचारू रूप से कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क परिधि के पार स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है। हमलावर अपने दुर्भावनापूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीएनएस ट्रैफ़िक का शोषण करने के लिए इस विशेषाधिकार का पता लगाते हैं। डीएनएस टनलिंग एक ऐसी साइबर हमले की तकनीक है जहाँ दुर्भावनापूर्ण अभिनेता डेटा एक्सफ़िल्ट्रेशन या कमांड और नियंत्रण के लिए एक गुप्त संचार चैनल बनाने हेतु डीएनएस प्रोटोकॉल का दुरुपयोग करते हैं। डीएनएस को उसके इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग करने के बजाय, हमलावर डीएनएस प्रश्नों और प्रतिक्रियाओं के भीतर डेटा या कमांड एम्बेड करते हैं। यह उन्हें नेटवर्क सुरक्षा उपायों को बाईपास करने और बिना लाल झंडे उठाए समझौता किए गए सिस्टम के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। डीएनएस टनलिंग का पता पेलोड का निरीक्षण करके, असामान्य पैटर्न के लिए डीएनएस प्रश्नों की निगरानी करके और डेटा एन्कोडिंग के संकेतों की पहचान करने के लिए डीप पैकेट निरीक्षण करके लगाया जा सकता है। अन्य निवारक उपायों में नियमित रूप से डीएनएस ट्रैफ़िक की निगरानी करना, डीएनएस सुरक्षा एक्सटेंशन लागू करना, अनधिकृत सर्वर पर डीएनएस ट्रैफ़िक को ब्लॉक करने के लिए फ़ायरवॉल नियम लागू करना और अनावश्यक डीएनएस प्रश्नों को सीमित करना शामिल है।

▲ चित्र 12.1 विकसित होते साइबर खतरे

क्वांटम-संचालित खतरे

जैसे-जैसे दुनिया क्वांटम कंप्यूटिंग के युग की ओर बढ़ रही है, सुरक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक के आगमन में मौजूदा क्रिप्टोग्राफ़िक सिस्टम को बाधित करने और वर्तमान सुरक्षा उपायों को अप्रचलित करने की क्षमता है। क्वांटम-संचालित खतरों की तैयारी आवश्यक हो जाएगी क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर विकसित होते हैं और उनकी क्षमताएँ साकार होती हैं, खासकर साइबर सुरक्षा समुदाय के लिए। क्वांटम कंप्यूटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक-कुंजी क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम को तोड़ने के साथ-साथ सममित-कुंजी क्रिप्टोग्राफी को बाधित करने की क्षमता है। आधुनिक एल्गोरिदम क्वांटम कंप्यूटरों को क्लासिक कंप्यूटरों की तुलना में अनसुलझे डेटाबेस (या ब्रूट-फ़ोर्स एन्क्रिप्शन कुंजियाँ) को तेजी से खोजने की अनुमति देते हैं। यह कुंजी की लंबाई को प्रभावी ढंग से आधा करके एन्क्रिप्शन की सुरक्षा को कम कर देगा, जिससे 128-बिट कुंजियों का उपयोग करने वाले सिस्टम आज के 64-बिट कुंजियों के जितने ही असुरक्षित हो जाएँगे।

ओपन-सोर्स कोड की कमजोरियाँ

ओपन-सोर्स कोड आधुनिक सॉफ़्टवेयर विकास का एक मूलभूत आधार बन गया है, जो डेवलपर्स को मौजूदा टूल्स, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज़ का लाभ उठाकर अपनी परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने में सक्षम बनाता है। यह विकास के समय को कम करने, सहयोग बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने जैसे कई लाभ प्रदान करता है। हालाँकि, ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर ये लाभ तो प्रदान करता है, लेकिन साथ ही यह संभावित जोखिम भी लाता है जिनसे संगठनों और डेवलपर्स को अवगत होना चाहिए। दुर्भावनापूर्ण योगदानकर्ता या हमलावर ओपन-सोर्स परियोजनाओं में बैकडोर स्थापित कर सकते हैं, जिनका बाद में सिस्टम तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने या संवेदनशील डेटा चुराने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये बैक डोरकोड के प्रतीत होने वाले सौम्य भागों में छिपे हो सकते हैं, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ओपन-सोर्स परियोजनाएँ अक्सर स्वयंसेवकों या छोटी टीमों द्वारा विकसित और अनुरक्षित की जाती हैं, जिनमें व्यापक सुरक्षा परीक्षण का अभाव हो सकता है। अनजाने में लाइसेंस उल्लंघन, लाइसेंस विवाद, विक्रेता समर्थन का अभाव, भेद्यता प्रकटीकरण में जवाबदेही का अभाव, परित्यक्त परियोजनाएँ, खराब दस्तावेज़ीकरण आदि इस मुद्दे को और भी जटिल बना देते हैं।

जनरेटिव एआई मॉडल को खतरे

जैसे-जैसे संगठन अपने संचालन में जनरेटिव एआई को एकीकृत करते हैं, वे अपने हमले की सतह का विस्तार करते हैं। जेनएआई मॉडल डेटा को संसाधित और उत्पन्न करते हैं जिसमें अनजाने में संवेदनशील जानकारी हो सकती है। इन मॉडलों के प्रशिक्षण में उपयोग किए गए गलत, पक्षपातपूर्ण या समझौता किए गए डेटा से डेटा लीक या गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। जेनएआई सिस्टम विरोधी हमलों से प्रतिरक्षा नहीं हैं, जहाँ हमलावर इनपुट डेटा को इस तरह से हेरफेर करते हैं कि एआई मॉडल अप्रत्याशित रूप से व्यवहार करने लगे या दुर्भावनापूर्ण आउटपुट उत्पन्न करे। हमलावर स्वामित्व वाले जेनएआई मॉडल को रिवर्स-इंजीनियर करने या चोरी करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे बौद्धिक संपदा और अंतर्दृष्टि तक पहुँच प्राप्त होती है जिसका दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए शोषण किया जा सकता है। इससे बौद्धिक संपदा की चोरी या व्यापार रहस्यों का अवैध उपयोग हो सकता है।

निष्कर्ष

भविष्य की अवधि के लिए ये भविष्यवाणियाँ सक्रिय रक्षा रणनीतियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की माँग करेंगी। संगठनों को संबंधित नियमों का पालन करके अपनी मूलभूत साइबर सुरक्षा स्थिति में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्हें ज़ीरो-ट्रस्ट आर्किटेक्चर को प्राथमिकता देनी चाहिए, एआई-संचालित सुरक्षा नियंत्रणों की शक्ति का उपयोग करना चाहिए, और इन खतरों को दूर करने के लिए हितधारकों के बीच सुरक्षा जागरूकता की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

राज्य सूचना अधिकारी
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, तमिलनाडु राज्य केंद्र
ई2-ए, राजाजी भवन, बेसेंट नगर
चेन्नई, तमिलनाडु – 600090
ईमेल: sio.tn@nic.in , फ़ोन: 044-44992425

ऐपस्केप

मोबाइल तकनीक सरकारों के लिए अपने नागरिकों की सेवा करने का एक प्रमुख साधन बनकर उभरी है। इसने संचार और सहयोग के लिए पारंपरिक भौतिक नेटवर्क की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यह कहीं अधिक किफायती और सुलभ भी है, जिससे बेहतर नागरिक-सरकार संपर्क के माध्यम से राष्ट्र को मजबूती मिलती है। इस संपर्क को और मज़बूत करने के लिए, एनआईसी ने एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध 730 से ज़्यादा मोबाइल ऐप्स का एक संग्रह तैयार किया है। ऐपस्केप के इस अंक में हाल ही में लॉन्च किए गए कुछ सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऐप्स को शामिल किया गया है। ये ऐप्स प्रशासन, विकास, वित्त, सार्वजनिक वितरण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं।

बैन्ड एसयूपी ई-चालान एचपी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एनआईसी के सहयोग से, हिमाचल प्रदेश गैर-जैवनिम्नीकरणीय कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 के तहत राज्य में एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के लिए प्रतिबंधित एसयूपी ई-चालान एचपी मोबाइल ऐप विकसित किया है।

यह ऐप नियुक्त अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ डिजिटल रूप से चालान दर्ज करने का अधिकार देता है। यह उल्लंघनकर्ताओं को मौके पर दिखाए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके तुरंत कंपाउंडिंग शुल्क का भुगतान करने की सुविधा भी देता है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी, कुशल और कागज़ रहित हो जाती है।

हिमाचल प्रदेश में प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें कैरी बैग, डिस्पोजेबल प्लास्टिक, 80 जीएसएम से कम के नॉन-वोवन कैरी बैग और अन्य प्रतिबंधित उत्पाद शामिल हैं।

यह ऐप न केवल प्रवर्तन को सुव्यवस्थित करता है, बल्कि एक निगरानी उपकरण के रूप में भी कार्य करता है, जिससे अधिकारी उल्लंघनों पर नज़र रख सकते हैं, रुझानों का आकलन कर सकते हैं और नीति कार्यान्वयन को मज़बूत कर सकते हैं। नागरिकों के लिए, यह विभाग की वेबसाइट के माध्यम से जुर्माना भरने और प्रतिबंधित वस्तुओं पर सूचनाएँ प्राप्त करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है।

चालान जारी करने और भुगतान को डिजिटल बनाकर, प्रतिबंधित एसयूपी ई-चालानएचपी जवाबदेही को बढ़ावा देता है और प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण के लिए हिमाचल प्रदेश की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

अजय सिंह चहल (sio-hp@nic.in)

एनआईसी ऐप्स से संबंधित प्रश्नों के लिए कृपया संपर्क करें

एंड्रॉइड
संदीप सूद
ईमेल: sood.sandeep@nic.in | फोन: 0177-2880890

आईओएस
रॉय जोसेफ
ईमेल: roy.joseph@nic.in | फोन: 9447722682

एन.एम.एम.एस. ऐप

2021 में लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सेवा (एन.एम.एम.एस.) एक परिवर्तनकारी मोबाइल एप्लिकेशन है जिसका उद्देश्य मनरेगा अधिनियम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

वास्तविक समय की निगरानी पर केंद्रित, एनएमएमएस ऐप पर्यवेक्षकों को मनरेगा कार्यस्थलों पर सीधे श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने में सक्षम बनाता है। उपस्थिति को जियोटैग्ड, समय-मुद्रित तस्वीरों के माध्यम से दर्ज किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों की उपस्थिति का सटीक दस्तावेजीकरण किया जाए, जिससे प्रॉक्सी उपस्थिति या रिकॉर्ड में हेरफेर की गुंजाइश कम हो जाती है। यह कार्यस्थल के आंकड़ों की प्रामाणिकता को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि रिपोर्ट की गई भागीदारी जमीनी स्तर पर वास्तविकता को दर्शाती है।

प्रशासकों के लिए, यह ऐप विश्वसनीय, तुरंत उपलब्ध डेटा प्रदान करके वेतन वितरण और परियोजना निगरानी को महत्वपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करता है। नागरिकों के लिए, यह सुनिश्चित करके कि उनका वेतन सत्यापित उपस्थिति और पारदर्शी प्रक्रियाओं पर आधारित है, कार्यक्रम में विश्वास बढ़ाता है।

उपस्थिति को डिजिटल बनाकर और इसे भू-स्थानिक और लौकिक डेटा से जोड़कर, एनएमएमएस नागरिक निगरानी को आगे बढ़ाता है, विश्वास को बढ़ावा देता है और जमीनी स्तर पर जवाबदेही का समर्थन करता है। यह ऐप कल्याणकारी कार्यक्रमों को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए मोबाइल गवर्नेंस टूल्स के उपयोग की दिशा में एक बड़ा कदम है।

संजय कुमार पाण्डेय (hog-mord@nic.in)

आधारबास

सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और समय की पाबंदी को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत सरकार द्वारा 2014 में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (ए.ई.बी.ए.एस.) शुरू की गई थी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित आधारबीएएस मोबाइल एप्लिकेशन, पंजीकृत सरकारी कर्मचारियों को अपनी दैनिक उपस्थिति दर्ज करने में सक्षम बनाता है।

यह ऐप विशेष रूप से केंद्रीय उपस्थिति पोर्टल पर नामांकित सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए है और आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। शुरुआत में, उपस्थिति फिंगरप्रिंट या आईरिस प्रमाणीकरण उपकरणों के माध्यम से दर्ज की जाती थी, जिसका वास्तविक समय में यू.आई.डी.ए.आई. के केंद्रीय पहचान डेटा भंडार (सी.आई.डी.आर.) से मिलान किया जाता था। बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एईबीएएस टीम ने यूआईडीएआई की आधार फेस आरडी सेवा का उपयोग करके फेस प्रमाणीकरण को एकीकृत किया है, जिससे कर्मचारियों को उपस्थिति दर्ज करने का एक तेज़, स्पर्श-मुक्त और अत्यधिक सुरक्षित तरीका मिलता है।

व्यवहार में, एक कर्मचारी बस अपनी उपस्थिति आईडी दर्ज करता है और बायोमेट्रिक या फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से पहचान सत्यापित करता है। सिस्टम 2-3 सेकंड में प्रतिक्रिया देता है, चेक-इन और चेक-आउट दोनों को सहजता से रिकॉर्ड करता है। इस नवाचार ने मज़बूत सुरक्षा बनाए रखते हुए उपयोगकर्ता की सुविधा को बढ़ाया है।

आधारबीएएस ऐप एक सुरक्षित, केवल भारत-आधारित प्लेटफ़ॉर्म है जो दर्शाता है कि आधार प्रमाणीकरण कैसे सार्वजनिक सेवा में कुशल शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही का समर्थन कर सकता है।

संजय कुमार पाण्डेय (hog-asd@nic.in)

उल्लास

उल्लास (समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा को समझना) ऐप, भारत सरकार द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत साक्षरता और आजीवन शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के प्रयासों के तहत विकसित किया गया है। एक व्यापक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया गया, यह ऐप समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षार्थियों, स्वयंसेवी शिक्षकों और सर्वेक्षणकर्ताओं के बीच सुचारू समन्वय स्थापित करता है। चुने गए सर्वेक्षणकर्ता उल्लास पोर्टल पर पंजीकृत होते हैं और ऐप तक पहुँच प्राप्त करते हैं, जो शिक्षार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों के नामांकन के लिए उनके प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक शिक्षार्थी को पास के एक स्वयंसेवी शिक्षक के साथ टैग किया जाता है, जिससे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान व्यक्तिगत मार्गदर्शन सुनिश्चित होता है। ऐप सटीक, वास्तविक समय के रिकॉर्ड भी रखता है, जिससे पारदर्शिता और प्रगति की कुशल निगरानी संभव होती है।

शिक्षार्थियों को शिक्षण-अधिगम संसाधनों के समृद्ध भंडार तक पहुँच का लाभ मिलता है, जिससे उन्हें बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मकता और जीवन कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। यह ऐप प्रमाणन का मार्ग भी प्रदान करता है: शिक्षार्थी सीधे ऐप के माध्यम से मूल्यांकन परीक्षाओं के लिए पंजीकरण कर सकते हैं और सफलतापूर्वक पूरा होने पर प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं।

अधिकृत अधिकारी ऐप के माध्यम से समय-समय पर निरीक्षण कर सकते हैं, जिससे सुचारू कार्यान्वयन और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। स्वयंसेवकों, शिक्षार्थियों और प्रशासकों को एक ही मंच पर लाकर, उल्लास ऐप डिजिटल, समावेशी और आजीवन शिक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देता है।

शशि भूषण (hog-epd@nic.in)

खनन सॉफ्ट

बिहार सरकार ने एनआईसी के सहयोग से खनन सॉफ्ट नामक एक व्यापक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिसे रेत और पत्थर जैसे खनिज संसाधनों के प्रशासन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ऐप खनिज उत्पादन, परिवहन और निगरानी प्रक्रियाओं में संपूर्ण स्वचालन लाता है, जिससे राज्य के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगता है।

चालान सत्यापन के माध्यम से, अधिकारी चालान संख्या दर्ज करके या क्यूआर कोड स्कैन करके खनन परमिट की प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकते हैं। यह ऐप अवैध खनन का पता लगाने के लिए बालू घाटों पर ऑन-साइट निरीक्षण का समर्थन करता है और अधिकारियों को वास्तविक समय के निरीक्षण डेटा को कैप्चर करने की अनुमति देता है। वाहन निरीक्षण पंजीकरण सत्यापित करने, चालान की वैधता की जाँच करने और ओवरलोडिंग की निगरानी करने में मदद करता है, जिससे कानूनी और सुरक्षित खनिज परिवहन सुनिश्चित होता है।

यह ऐप रिकॉर्ड रखने के लिए तिथि-वार फ़िल्टर के साथ एक व्यापक निरीक्षण इतिहास भी प्रदान करता है, और दैनिक खनन और परिवहन गतिविधि की जानकारी देने के लिए चालान आँकड़े ग्राफ़िकल प्रारूप में प्रदर्शित होते हैं। अधिकारी सक्रिय और अवरुद्ध घाटों की स्थिति देख सकते हैं, जिससे बेहतर संसाधन नियोजन में सहायता मिलती है।

संसाधन प्रबंधन को डिजिटल बनाकर, खनन सॉफ्ट एक पारदर्शी, जवाबदेह और विनियमित खनन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए बिहार के प्रयासों को मजबूत करता है।

अजय कुमार (sio-bih@nic.in)

अन्न मित्र

भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एनआईसी (NIC) के साथ मिलकर अन्न मित्र नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जो पीडीएस अधिकारियों और हितधारकों को कहीं भी, कभी भी पीडीएस से संबंधित जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। यह ऐप विशेष रूप से एफपीएस डीलरों, डीएफएसओ और खाद्य निरीक्षकों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो राशन वितरण की निगरानी, रिपोर्टिंग और शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करता है।

एफपीएस डीलरों के लिए, यह ऐप मासिक स्टॉक रसीदों, बिक्री रिपोर्ट, एफपीएस रेटिंग्स और महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाओं तक रीयल-टाइम एक्सेस प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि दुकानदार राशन स्टॉक प्रबंधन में अद्यतन और जवाबदेह बने रहें।

डीएफएसओ अधिकारियों के लिए, यह ऐप एफपीएस प्रदर्शन डेटा देखने, स्टॉक उपलब्धता की निगरानी करने, और शिकायत निवारण अपडेट को ट्रैक करने की सुविधा देता है ताकि वे जिला स्तर पर संचालन को अधिक प्रभावी ढंग से देख सकें।

इस बीच, खाद्य निरीक्षकों को निरीक्षण इतिहास, बिक्री और क्लोजिंग स्टॉक के आंकड़े, और एफपीएस फीडबैक तक पहुंच मिलती है, जिससे वे सटीक फील्ड-स्तरीय मूल्यांकन कर सकें।

इन कार्यों के एकीकरण के माध्यम से, अन्न मित्र भारत की पीडीएस प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाता है। यह सुनिश्चित करता है कि राशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत अधिकारियों के लिए उपलब्ध हो, जिससे बेहतर निगरानी संभव हो सके।

जी. मयिल मुथु कुमारन (hog-fpd@nic.in)

नेक्स्टजेन ओआरएस

नेक्स्टजेन ओआरएस एक नागरिक-केंद्रित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को सरल, तेज़ और अधिक सुलभ बनाने के लिए विकसित किया गया है। उपयोगकर्ता-अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया यह एप्लिकेशन, रोगियों को लंबी कतारों या जटिल प्रक्रियाओं के बिना, भारत भर के अस्पतालों में अपॉइंटमेंट आसानी से पंजीकृत, बुक और प्रबंधित करने की सुविधा देता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ एकीकृत, नेक्स्टजेन ओआरएस ओपीडी पंजीकरण के साथ-साथ टेली-कंसल्टेशन का भी समर्थन करता है, जिससे मरीज डॉक्टरों से दूरस्थ रूप से परामर्श कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से मरीज अपने रीयल-टाइम अपॉइंटमेंट स्टेटस देख सकते हैं, अपडेट प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल या कैंसिल भी कर सकते हैं।

यह प्लेटफ़ॉर्म मरीजों के आधार विवरण से लिंक होकर कागज़ी कार्यवाही को कम करता है, जिससे सत्यापन प्रक्रिया आसान होती है और सेवाओं तक तेज़ पहुँच सुनिश्चित होती है। यह अस्पताल प्रशासन को भी सशक्त बनाता है — शेड्यूलिंग को अनुकूलित करता है, काउंटर पर भीड़ को कम करता है, और मरीज प्रबंधन में कुल दक्षता को बढ़ाता है।

मरीजों और अस्पतालों के बीच डिजिटल सेतु बनकर, नेक्स्टजेन ओआरएस सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, सुविधा और समावेशिता को सुदृढ़ करता है।

शुभेन्दु कुमार (hog-ehospital@nic.in)

भारत ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एआई शासन के प्रति समावेशी दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला

27 सितंबर, 2025 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित ग्लोबल डायलॉग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) गवर्नेंस के शुभारंभ के अवसर पर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने एआई के लिए एक सहयोगात्मक और समावेशी वैश्विक रूपरेखा विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित उच्च-स्तरीय बहु-हितधारक बैठक को संबोधित करते हुए सचिव ने वैश्विक दक्षिण और उपेक्षित समुदायों की सार्थक भागीदारी के साथ मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता रेखांकित की, ताकि एआई के लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँच सकें। उन्होंने यह भी कहा कि एआई का विकास ऐसे तरीके से होना चाहिए जो साझा मानवीय मूल्यों को प्रतिबिंबित करे और वैश्विक विश्वास को बढ़ावा दे, न कि मौजूदा असमानताओं को और गहरा करे।

उन्होंने भारत के व्यापक एआई शासन मॉडल का विवरण प्रस्तुत किया, जो सात मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है: भरोसा, लोगों को प्राथमिकता, अनावश्यक प्रतिबंधों की बजाय नवाचार, न्याय और समानता, जवाबदेही, सहज समझ के अनुरूप डिज़ाइन, तथा सुरक्षा, लचीलापन और स्थिरता। उन्होंने जोर दिया कि वैश्विक संवाद को एआई से संबंधित ज्ञान, कौशल, संसाधन और तकनीकी क्षमताओं में मौजूद असमानताओं को भी दूर करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने देशों से आह्वान किया कि सभी राष्ट्र मिलकर एआई को अपनाने के लिए न्यायसंगत मार्ग तैयार करें। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि क्षमता निर्माण, बहुभाषी डेटा सेट, और ज़िम्मेदार नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र उन देशों के लिए अत्यंत आवश्यक होंगे जो डिजिटल विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

सचिव ने यह घोषणा भी की कि भारत फरवरी 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी

करेगा, जिसमें वैश्विक हितधारक सतत विकास के लिए एआई-आधारित समाधानों पर विचार-विमर्श करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के सिद्धांत-आधारित और समावेशी एआई शासन दृष्टिकोण की सराहना इस बात का प्रतीक है कि डिजिटल भविष्य के निर्माण में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। यह भारत की उस प्रतिबद्धता को भी दोहराता है कि परिवर्तनकारी तकनीकों का उपयोग वैश्विक शांति, समृद्धि और मानवीय प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए।

स्रोत - *pib.gov.in*

पेरिस में ग्लोबल एक्सेलरेटर के लिए 10 भारतीय एआई स्टार्टअप्स को चुना गया

भारत के वैश्विक एआई पदचिह्न को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया एआई मिशन ने इंडिया एआई स्टार्टअप्स ग्लोबल (आईएसजी) पहल के लिए 10 नवोन्मेषी भारतीय एआई स्टार्टअप्स का चयन किया है। पहल - स्टेशन F और एचईसी पेरिस के सहयोग से एक प्रतिष्ठित त्वरक कार्यक्रम।।

चार महीने का कार्यक्रम - जिसमें एक महीने का ऑनलाइन मॉड्यूल और पेरिस में तीन महीने का निवास शामिल है - भारतीय स्टार्टअप को वैश्विक बाजारों, मेंटरशिप और सीमा पार सहयोग के अवसरों तक पहुंचने में मदद करेगा।

केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "भारत का एआई पारिस्थितिकी तंत्र एक वैश्विक सफलता के कगार पर है। यह साझेदारी भारत की नवाचार कूटनीति में एक नया अध्याय शुरू करती है।"

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और भारत एआई मिशन के सीईओ, श्री अभिषेक सिंह ने कहा कि यह पहल "भारत की एआई प्रतिभा को वैश्विक नवाचार केंद्रों से जोड़ती है।"

स्टैकू टेक्नोलॉजीज (जार्विस), जो एआई-आधारित ऑडियो-वीडियो एनालिटिक्स में विशेषज्ञता रखती है; सैटश्योर एनालिटिक्स, जो पृथ्वी अवलोकन और निर्णय बुद्धिमत्ता के लिए उपग्रह इमेजरी का लाभ उठाती है; स्टोरीवॉर्ड, जो स्वचालित वीडियो सामग्री के लिए एक एआई सह-निर्माता है; वोलारअल्टा, जो औद्योगिक निरीक्षणों के लिए ड्रोन-आधारित एआई का उपयोग करती है; स्मार्टेल, जो अनुकूली एडटेक अनुभव बनाती है; सिक्योर ब्लिंक, जो एआई-संचालित साइबर सुरक्षा समाधान प्रदान करती है; न्यूरोपिक्सल.एआई, जो ई-कॉमर्स के लिए अल्ट्रा-फास्ट इमेज एडिटिंग को सक्षम बनाती है; और वॉइसिंग एआई, जो एंटरप्राइज़-ग्रेड इंटेलिजेंट वॉयस एजेंटों को सशक्त बनाती है।

मार्च 2024 में लॉन्च किए गए इंडियाएआई मिशन का उद्देश्य सात प्रमुख स्तंभों - कंप्यूट, इनोवेशन, डेटासेट, एप्लिकेशन डेवलपमेंट, फ्यूचरस्किल्स, स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई - के माध्यम से भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, जिससे जिम्मेदार और समावेशी एआई विकास को बढ़ावा मिले।

स्टेशन एफ, जो पेरिस में दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप कैंपस है, और एचईसी पेरिस, जो यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों में से एक है, इस एक्सेलेरेटर प्रोग्राम की मेजबानी करेगा। साथ मिलकर, वे भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों, मार्गदर्शन और यूरोप के फलते-फूलते नवाचार नेटवर्क तक पहुँच प्रदान करेंगे। यह सहयोग न केवल भारतीय नवप्रवर्तकों को नए बाज़ार तलाशने में मदद करेगा, बल्कि नैतिक, समावेशी और उच्च-प्रभावी एआई विकास के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को भी मज़बूत करेगा।

स्रोत - *https://www.hec.edu*

भारत और मॉरीशस ने डिजिटल सहयोग मज़बूत करने पर चर्चा की

मॉरीशस के माननीय सूचना प्रौद्योगिकी, संचार एवं नवाचार मंत्री डॉ. अविनाश रामटोहूल ने 13 सितंबर 2025 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और डिजिटल शासन के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और गहरा करने की संभावनाओं का अन्वेषण करना था।

नई दिल्ली स्थित एनआईसी मुख्यालय में अपने दौरे के दौरान डॉ. रामटोहूल ने श्री अभिषेक सिंह, महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तथा श्री आई.पी.एस. सेठी, उप महानिदेशक, एनआईसी के साथ विस्तृत चर्चाएँ कीं।

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत और मॉरीशस के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाने की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों पक्षों ने चल रहे सहयोग की समीक्षा की और ऐसे नए क्षेत्रों की पहचान की, जहाँ और अधिक साझेदारी की जा सकती है।

चर्चाओं में उभरती डिजिटल तकनीकों के व्यापक आयाम शामिल थे, विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया:

- सार्वजनिक सेवाओं के लिए अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म
- ई-गवर्नेंस ढाँचे और नागरिक-केंद्रित सेवा मॉडल
- डिजिटल कौशल और शासन क्षमता निर्माण हेतु कार्यक्रम
- साइबर सुरक्षा ढाँचे और उसकी मजबूती

भारतीय अधिकारियों ने देश की प्रमुख डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पहलों—जैसे डिजिटल इंडिया, आधार, डिजिलॉकर, उमंग और विभिन्न एआई-आधारित शासन उपकरणों—से प्राप्त अनुभव

साझा किए। मॉरीशस के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी डिजिटल मॉरीशस विज़न को गति देने के लिए इन समाधानों को अपनाने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करने में गहरी रुचि दिखाई, जिसका लक्ष्य एक समावेशी और नवाचार-प्रधान डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

दोनों देशों ने तकनीक-चालित पहलों के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने डिजिटल पहचान, सुरक्षित डेटा विनिमय, डिजिटल भुगतान तथा एआई-सक्षम शासन जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए संयुक्त समाधान विकसित करने के महत्व पर बल दिया।

बैठक का समापन इस सहमति के साथ हुआ कि दोनों देश उच्च-स्तरीय संवाद को नियमित बनाए रखेंगे, संयुक्त क्षमता निर्माण प्रयासों को आगे बढ़ाएँगे और दोनों देशों की तकनीकी टीमों के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे।

स्रोत - *pib.gov.in*

डेटा के नए युग की ओर अमेरिका: अंतर्दृष्टि के लिए 'सिंथेटिक डेटा' का उपयोग

सरकारें जैसे-जैसे नागरिकों की गोपनीयता से समझौता किए बिना डेटा के उपयोग के नए तरीके खोज रही हैं, सिंथेटिक डेटा एक आशाजनक समाधान के रूप में उभर रहा है। डिजिटल रूप से उत्पन्न डेटासेट वास्तविक जानकारी की संरचना और पैटर्न की नकल करते हैं, लेकिन उनमें कोई वास्तविक व्यक्तिगत रिकॉर्ड नहीं होता है, जिससे एजेंसियों को कम जोखिम के साथ रुझानों का विश्लेषण और प्रणालियों का परीक्षण करने में मदद मिलती है।

ऐसे समय में जब साइबर खतरों और डेटा चोरी की घटनाएँ बढ़ रही हैं, सार्वजनिक संस्थानों में गोपनीयता-सुरक्षित उपकरणों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

यूटा खुद को एक शुरुआती अपनाने वाले राज्य के रूप में स्थापित कर रहा है। राज्य के मुख्य गोपनीयता अधिकारी सिंथेटिक डेटा को "एक नया क्षितिज" बताते हैं और कहते हैं कि विभिन्न एजेंसियों में नवाचार और गोपनीयता सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए इस तकनीक के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है। यूटा सिंथेटिक डेटा को राज्य के कानून में परिभाषित करने वाला दुर्लभ राज्य भी बन गया है, जो यह दर्शाता है कि कृत्रिम डेटा उपकरणों के विकसित होने के साथ राज्य एक सक्रिय और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपना रहा है तथा व्यापक डिजिटल आधुनिकीकरण के लिए तैयारी कर रहा है।

इस तकनीक का आकर्षण स्पष्ट है: सिंथेटिक डेटा सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों को जानकारी साझा करने, बेहतर पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने और उभरती तकनीकों पर प्रयोग करने में मदद कर सकता है—वह भी संवेदनशील विवरणों को उजागर किए बिना। यह विशेष रूप से परिवहन योजना, स्वास्थ्य सेवाओं और लाभ प्रशासन जैसे क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है, जहाँ वास्तविक डेटा तक पहुँच कड़े नियंत्रणों और जटिल प्रक्रियाओं के कारण सीमित रहती है।

फिर भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सिंथेटिक डेटा को वास्तविक जानकारी के सांख्यिकीय मूल्य को बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई गोपनीयता जोखिम न हो। यदि इसे गलत ढंग से तैयार किया गया, तो यह पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है या वास्तविक दुनिया के व्यवहार को ठीक से प्रतिबिंबित नहीं कर पाएगा। इस संतुलन को बनाए रखना सार्थक अपनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा, और

विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे-जैसे तकनीक विकसित होगी, कठोर सत्यापन और पारदर्शिता मानकों की आवश्यकता और भी बढ़ेगी।

फिलहाल, यूटा प्रारंभिक चरण में है। नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा पायलट कार्यक्रमों और शासन ढाँचे पर काम किया जा रहा है ताकि भविष्य में इसके प्रभावी उपयोग का मार्गदर्शन किया जा सके। उनकी प्रगति यह तय कर सकती है कि अन्य राज्य सिंथेटिक डेटा को कैसे अपनाते हैं—क्या यह आधुनिक शासन में एक मानक उपकरण बनेगा या केवल एक प्रयोगात्मक प्रवृत्ति बनकर रह जाएगा।

स्रोत - *govtech.com*

डिजिटल समावेशिता को आगे बढ़ाना

वेब अभिगम्यता (एक्सेसिबिलिटी) पर एनआईसी की कार्यशालाएँ

संपादित : **अर्चना शर्मा**

अभिगम्यता (एक्सेसिबिलिटी) कोई विशेषता नहीं है - यह सम्मान का द्वार है। यह वह शांत आश्वासन है कि हर नागरिक, अपनी क्षमता की परवाह किए बिना, शासन के डिजिटल गलियारों में कदम रख सकता है और खुद को शामिल महसूस कर सकता है। डिजिटल इंडिया के युग में, पहुँच सुनिश्चित करना केवल राज्य का दायित्व नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है जिसके माध्यम से हम शासन के ताने-बाने में विश्वास, संवेदनशीलता और समानता को बुन सकते हैं।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, अपनी मीडिया सूचना विज्ञान प्रभाग के माध्यम से, इस दृष्टिकोण को शांत दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा रहा है। एक ऐतिहासिक क्षण तब आया जब एनआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पूरी तरह से सुलभ हो गई - यह उपलब्धि मीडिया सूचना विज्ञान प्रभाग के अथक प्रयासों, वेब प्रौद्योगिकी प्रभाग की तकनीकी दक्षता, और पूरे संगठन में प्रमुख विभाग, सिस्टम इंटिग्रेशन अधिकारी, विभागाध्यक्ष, और अधिकारियों के अटूट समर्थन से संभव हुई। यह महज़ एक तकनीकी उन्नयन नहीं था, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश था: समावेश हमारी डिजिटल यात्रा का आधार बनेगा।

इस गति को आगे बढ़ाते हुए, मीडिया सूचना विज्ञान प्रभाग ने 20 अगस्त 2025 और 25 सितंबर 2025 को वेब पहुँच पर दो कार्यशालाएँ आयोजित कीं। ये बैठकें महज़ प्रशिक्षण सत्र नहीं थीं; ये जिम्मेदारी पर, क्षमता निर्माण पर, और भारत के डिजिटल शासन को समावेशिता के उच्चतम मानकों डब्ल्यू.सी.ए.जी. 2.1 स्तर एए और जी.आई.जी.डब्ल्यू. 3.0 - के साथ संरेखित करने पर केंद्रित गहन बातचीत थीं।

प्रशांत कुमार मित्तल
उप महानिदेशक एवं एचओजी
pk.mittal@nic.in

वीरेंद्र कुमार त्यागी
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
vk.tyagi@nic.in

तुहिना कुमार
तकनीकी निदेशक
tuhina@nic.in

प्रारंभिक वक्तव्य और मुख्य वक्ता के विचार

कार्यशालाओं की शुरुआत मीडिया सूचना विज्ञान प्रभाग के विभाग प्रमुख श्री वीरेंद्र कुमार त्यागी की स्थिर आवाज़ के साथ हुई, जिन्होंने प्रतिभागियों को याद दिलाया कि पहुँच केवल नियमों के अनुपालन का मामला नहीं है, बल्कि यह उन सभी की साझा जिम्मेदारी है जो नागरिकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाते और उनका रखरखाव करते हैं।

संवाद को दिशा देते हुए, सुश्री तुहिना कुमार, निदेशक (आईटी), ने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे पहुँच को डिज़ाइन के केंद्र में रखें - इसे बाद में जोड़ा गया विचार नहीं, बल्कि हर चुनाव का मार्गदर्शन करने वाला सिद्धांत मानें। उनके शब्दों ने इस विश्वास को आकार दिया कि सच्चा शासन समावेशन से ही शुरू होना चाहिए।

मुख्य भाषण श्री प्रशांत कुमार मित्तल, उप महानिदेशक और समूह प्रमुख, मीडिया सूचना विज्ञान प्रभाग, द्वारा दिया गया। उन्होंने एनआईसी की उस रणनीतिक भूमिका पर बात की, जो डिजिटल स्पेस को न केवल मज़बूत और कुशल बल्कि संवेदनशील और नागरिक-अनुकूल भी बनाता है। उन्होंने अधिकारियों से "सबके लिए डिज़ाइन" सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया, जिसमें समावेशिता को कोड की हर लाइन, हर पेज और हर सेवा में समाहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि पहुँच पारदर्शिता, समावेश और स्थिरता - जो स्वयं शासन की भावना को बनाए रखते हैं - उन मूल्यों से अविभाज्य है।

तकनीकी प्रस्तुतिकरण और व्यावहारिक ज्ञान

कार्यशालाओं का मुख्य केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ सूचीबद्ध एक वेब पहुँच ऑडिटिंग संगठन द्वारा दिया गया विस्तृत प्रस्तुतिकरण था।

- ये सत्र, डिजिटल दुनिया के अभ्यासकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शिका की तरह खुले:
- वे सामान्य बाधाएँ जो नागरिकों को बाहर कर देती हैं, और उन्हें दूर करने के व्यावहारिक तरीके।
- पहुँच के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास, जो डिज़ाइन के साथ-साथ संवेदनशीलता पर भी आधारित हैं।
- उन उपकरणों का प्रदर्शन - स्वचालित और मैन्युअल - जो समावेशन को ठोस तरीके से मापते हैं।
- सुलभ पीडीएफ बनाने और वेबसाइटों को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने की रणनीतियाँ।
- सौंदर्यशास्त्र से समझौता किए बिना पहुँच को सहज रूप से एकीकृत करने के व्यावहारिक तरीके।

इन प्रदर्शनों ने ज्ञान को अनुभव में बदल दिया, जिससे प्रतिभागियों ने पहुँच को केवल सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि एक कार्यशील वास्तविकता के रूप में देखा।

सहभागी चर्चाएँ और मुख्य निष्कर्ष

वास्तविक शिक्षा सवालों के साथ जीवंत हो उठी। प्रतिभागियों ने पुरानी सामग्री, बदलाव का विरोध करने वाले कार्यप्रवाहों, और

एनआईसी के व्यापक, विविध प्लेटफार्मों पर पहुँच सुनिश्चित करने के बारे में पूछा। हर प्रश्न का उत्तर स्पष्ट, व्यावहारिक समाधानों के साथ दिया गया, जिनमें तकनीकी गहराई और सरलता दोनों शामिल थीं।

इन चर्चाओं से मुख्य सबक उभरे

- अभिगम्यता को हर डिजिटल पहल की शुरुआत में ही बुना जाना चाहिए।
- यदि अनुपालन को बनाए रखना है, तो ऑडिट अनियमित नहीं, बल्कि नियमित होने चाहिए।
- परीक्षण स्वचालित और मानव-चालित दोनों होने चाहिए, क्योंकि संवेदनशीलता को केवल सॉफ्टवेयर पर नहीं छोड़ा जा सकता।
- सबसे महत्वपूर्ण, क्षमता भीतर ही विकसित की जानी चाहिए - डेवलपर्स, डिज़ाइनर और प्रशासकों को अभिगम्यता को एक स्व-प्रेरित अभ्यास के रूप में अपनाना होगा।

विकसित भारत के लिए साझा प्रतिबद्धता

कार्यशालाओं का समापन किसी निष्कर्ष के साथ नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प के साथ हुआ। राज्यों और मंत्रालयों के अधिकारियों ने, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों या वीडियो के माध्यम से जुड़े हों, एक साझा दृष्टिकोण के साथ विदा ली: भारत में डिजिटल शासन के लिए अभिगम्यता को एक मूल सिद्धांत बनाना।

सत्रों की स्पष्टता, व्यावहारिक ज्ञान की प्रासंगिकता और उनमें निहित भविष्योन्मुखी ऊर्जा की व्यापक रूप से सराहना की गई। इससे भी अधिक, उन्होंने एक नेता के रूप में एनआईसी की भूमिका को फिर से स्थापित किया - एक ऐसा संगठन जो न केवल प्रौद्योगिकी का निर्माण कर रहा है, बल्कि डिजिटल समावेशन की नैतिकता को भी आकार दे रहा है।

ऐसी पहलों के माध्यम से, मीडिया सूचना विज्ञान प्रभाग ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है: इस यात्रा को जारी रखना, हर स्तर पर अभिगम्यता को मजबूत करना, और यह सुनिश्चित करना कि डिजिटल इंडिया न केवल उन्नत हो, बल्कि समावेशी, नागरिक-केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार भी हो।

इस दृष्टिकोण में ही विकसित भारत का वादा निहित है - एक ऐसा राष्ट्र जहाँ डिजिटल शासन केवल दक्षता के बारे में नहीं, बल्कि जुड़ाव के बारे में है।

ऊपरी सुबनसिरी में यू.एस.पी.एन. मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया

उपायुक्त श्री तासो गाम्बो ने गुरुवार को यू.एस.पी.एन. एंड्रॉइड मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य आधिकारिक सूचनाओं तक जनता की पहुँच में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम में जिला विभागाध्यक्ष और प्रभारी जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री दिनेश कुमार रजक उपस्थित थे।

यह ऐप नागरिकों को भूस्खलन अलर्ट, त्योहारों की अपडेट, रूट मैप, विज्ञापन और सामान्य घोषणाओं जैसी जिला सूचनाओं को सीधे अपने स्मार्टफोन पर आसानी से देखने और डाउनलोड करने में सक्षम बनाता है। अधिकारी सार्वजनिक सूचनाओं और संपर्क सूचियों सहित प्रमाणित पीडीएफ दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और समय पर संचार सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

डीसी गाम्बो ने कहा कि इस पहल से नागरिकों को कहीं से भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मिलने से लाभ होगा। डीआईओ रजक ने उपस्थित लोगों को ऐप की तकनीकी व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। यह लॉन्च ऊपरी सुबनसिरी में डिजिटल शासन को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है।

– दिनेश कुमार रजक, अरुणाचल प्रदेश

पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सी.सी.एम.एस. मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया

पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने सी.सी.एम.एस. मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया

सरकारी विभागों में कानूनी कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक कदम उठाते हुए, पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम (सी.सी.एम.एस.) मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य कोर्ट केसों के प्रबंधन को मज़बूत करना, समय पर अनुपालन सुनिश्चित करना और वादकारियों के लाभ के लिए विवादों का तेज़ी से निपटारा करना है।

सी.सी.एम.एस. मोबाइल एप्लिकेशन एक सरल डिजिटल इंटरफ़ेस प्रदान करता है जिसके माध्यम से संबंधित हितधारक वास्तविक समय में केस की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं, अनुपालन की निगरानी कर सकते हैं और विभागों के बीच अधिक प्रभावी ढंग से समन्वय स्थापित कर सकते हैं। अधिकारियों को समय पर और सूचित कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाकर, इस प्लेटफॉर्म से लंबित मामलों में कमी आने, जवाबदेही बढ़ने और शासन में मज़बूत कानूनी अनुपालन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सी.सी.एम.एस. एप्लिकेशन का लॉन्च दक्षता, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित न्याय वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की न्यायपालिका और सरकार की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

– सैयद मुमताज़ हुसैन, बिहार

एन्टे भूमि कार्यक्रम के तहत सर्वे रिकॉर्ड के ऑनलाइन वितरण के लिए केरल ने कियोस्क लॉन्च किया

केरल सरकार के सर्वेक्षण और भूमि रिकॉर्ड निदेशालय के 'एन्टे भूमि' डिजिटल सर्वेक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, सर्वेक्षण रिकॉर्ड के ऑनलाइन वितरण के लिए एक अत्याधुनिक कियोस्क का उद्घाटन केरल के माननीय राजस्व मंत्री द्वारा किया गया।

यह कियोस्क एक उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिसके माध्यम से नागरिक सुविधापूर्वक डिजिटल रूप से सर्वेक्षण किए गए मानचित्र और भूमि रिकॉर्ड खरीद सकते हैं। एनआईसी द्वारा विकसित 'एन्टे भूमि' पोर्टल के साथ एकीकृत, यह सुविधा नागरिकों को सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान करने और सीधे मानचित्र तथा रिकॉर्ड डाउनलोड करने में सक्षम बनाती है, जिससे भूमि-संबंधी सेवाओं तक तेज़, पारदर्शी और परेशानी मुक्त पहुँच सुनिश्चित होती है।

यह पहल केरल के व्यापक "माय भूमि" कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से भूमि सर्वेक्षण और अभिलेखों का रखरखाव का आधुनिकीकरण करना है। प्रक्रिया को डिजिटाइज़ और सुव्यवस्थित करके, यह प्रणाली मैन्युअल रिकॉर्ड पर निर्भरता कम करती है, पारदर्शिता बढ़ाती है और नागरिकों को कहीं भी, कभी भी महत्वपूर्ण भूमि जानकारी तक पहुँच प्रदान कर सशक्त बनाती है।

यह विकास डिजिटलकेरल की ओर राज्य की यात्रा में एक और मील का पत्थर है, जो दर्शाता है कि आईसीटी संचालित शासन किस तरह नागरिक सेवाओं को बदल सकता है और आवश्यक रिकॉर्ड तक सार्वजनिक पहुँच में सुधार कर सकता है।

– सूसी एम., केरल

केरल के माननीय राजस्व मंत्री ने सर्वेक्षण रिकॉर्ड के ऑनलाइन वितरण के लिए एक अत्याधुनिक कियोस्क का उद्घाटन किया

एनआईसी मणिपुर ने कोहसेम के लिए नए ईपीएमएस एप्लिकेशन पर प्रशिक्षण आयोजित किया

परीक्षा प्रसंस्करण और प्रबंधन प्रणाली (ई.पी.एम.एस.), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र मणिपुर द्वारा विकसित एक नया वेब-आधारित एप्लिकेशन है, जिसे काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मणिपुर (कोहसेम) के लिए आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से पेश किया गया।

ईपीएमएस को माइक्रोसर्विसेज़ आर्किटेक्चर पर ओपन-सोर्स तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया है, जो मापनीयता, लचीलापन और मज़बूती सुनिश्चित करता है। इसे परीक्षा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और परीक्षा से संबंधित कार्यों के एंड-टू-एंड चक्र को कवर करते हुए प्रबंधन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य कोहसेम अधिकारियों को नई प्रणाली की विशेषताओं, कार्यक्षमताओं और संचालन पहलुओं से परिचित कराना था। व्यावहारिक सत्रों के माध्यम से, प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया गया कि ईपीएमएस का उपयोग परीक्षा डेटा प्रबंधन में सुधार लाने, मैन्युअल हस्तक्षेपों को कम करने और तेज़, अधिक पारदर्शी परिणाम प्रदान करने के लिए कैसे किया जा सकता है।

यह पहल अभिनव, नागरिक-केंद्रित डिजिटल समाधान विकसित करने की एनआईसी मणिपुर की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो शासन को मज़बूत करते हैं और मुख्य प्रशासनिक कार्यों का आधुनिकीकरण करते हैं। ईपीएमएस के साथ, कोहसेम परीक्षा प्रबंधन में बेहतर सटीकता, दक्षता और पारदर्शिता से लाभान्वित होने के लिए तैयार है, जो मणिपुर के शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एनआईसी मणिपुर ने परीक्षा प्रसंस्करण और प्रबंधन प्रणाली (ई.पी.एम.एस.) पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

– निरीश वाहेन्गबाम, मणिपुर

पारदर्शिता और जवाबदेही को मज़बूत करने के लिए देहरादून में एनजीओ दर्पण पोर्टल पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित

एनजीओ दर्पण पोर्टल पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित की गई

एनजीओ दर्पण पोर्टल पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य राज्य के अधिकारियों को जागरूक करना और एनजीओ को प्रभावी ढंग से अनुदान जारी करने के लिए पोर्टल के डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड के उपयोग पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना था।

इस कार्यशाला में उत्तराखंड सरकार, नीति आयोग, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, नोडल अधिकारियों और संबंधित राज्यों के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इंटरैक्टिव सत्रों और प्रदर्शनों के माध्यम से, प्रतिभागियों को पोर्टल की विशेषताओं को नेविगेट करने, डेटा का विश्लेषण करने और अनुदान आवंटन में निर्णय लेने में सुधार के लिए डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षित किया गया।

एनजीओ दर्पण पोर्टल, जिसका प्रबंधन एनआईसी के तकनीकी सहयोग से नीति आयोग करता है, सरकार और स्वैच्छिक संगठनों के बीच डिजिटल पुल का काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि एनजीओ से संबंधित डेटा सटीक, सुलभ और सत्यापन योग्य हो, जिससे शासन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।

राज्य के अधिकारियों को डिजिटल उपकरणों और वास्तविक समय के विश्लेषण से सशक्त बनाकर, कार्यशाला ने सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराया कि एनजीओ को अनुदान समय पर, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से जारी किया जाए, जिससे नागरिक समाज और शासन संस्थानों के बीच विश्वास मज़बूत हो।

– चंचल गोयल, उत्तराखंड

कोल इंडिया चेयरमैन ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और पुनर्वास प्रयासों को मज़बूत करने के लिए कोल-आर.आर. पोर्टल का उद्घाटन किया

कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष ने एनआईसी द्वारा विकसित कोलआरआर पोर्टल का उद्घाटन किया

कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष ने कोल-आर.आर. (कॉनसॉलीडेशन ऑफ अकाउंटेबल लैंड, रिहैबिलिटेशन ऐंड रिसैटलमेंट) पोर्टल का उद्घाटन किया, जिसे एनआईसी ने विकसित किया है। यह कोयला खनन कार्यों के लिए भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और पुनर्वास प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक अग्रणी कदम है।

कोलआरआर पोर्टल https://eclcoalrr.in पर उपलब्ध, भूमि-संबंधी डेटा की प्रभावी निगरानी, त्वरित अनुमोदन और पारदर्शी प्रबंधन को सक्षम करने के लिए जीआईएस-आधारित मैपिंग को एकीकृत करता है। यह भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन को ट्रैक करने के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना प्रभावित परिवार (पी.ए.एफ.ए.) और उनके नामांकित व्यक्ति आसानी से प्राप्त होने वाले लाभों तक पहुँच सकें और उनका दावा कर सकें।

सिस्टम में पारदर्शिता, पहुँच और जवाबदेही लाकर, यह पोर्टल जमीन मालिकों, विस्थापित परिवारों और कोयला क्षेत्र के हितधारकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। यह न केवल परिचालन दक्षता बढ़ाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि परियोजना प्रभावित परिवार के लिए कल्याणकारी उपाय समय पर और न्यायपूर्ण तरीके से लागू किए जाएँ।

कोलआरआर का लॉन्च स्थायी विकास के लिए डिजिटल नवाचार का लाभ उठाने की कोल इंडिया और एनआईसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोयला खनन के माध्यम से होने वाला आर्थिक विकास सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिक सशक्तिकरण के साथ संतुलित हो।

– अर्चना शर्मा, दिल्ली

डिजिटल शासन को मज़बूत करने के लिए एनआईसी तेलंगाना ने हैदराबाद में डीआईओ/ डीआईए मीट 2025 की मेजबानी की

डीआईओ मीट में श्री वीटीवी रमना (राज्य समन्वयक), श्री आशीष विक्रम अस्थाना (डेटा सेंटर नॉन-आईटी इंफ्रा समूह प्रमुख), श्री गुंटुकु प्रसाद (राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी) और श्री राधा कृष्ण (सहायक राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी) ने मुख्य संबोधन दिया

एनआईसी तेलंगाना ने जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों और जिला सूचना विज्ञान सहयोगियों (डीआईए) को एक साझा मंच पर एकत्र करने, सहयोग करने और नवाचार करने के लिए 15 सितंबर 2025 को डीआईओ/ डीआईए मीट – 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

यह बैठक इंटरैक्टिव सत्रों और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक गतिशील मंच थी, जिसमें चर्चाएँ डिजिटल बुनियादी ढांचे, सूचना विज्ञान और सेवा वितरण पर केंद्रित थीं। प्रतिभागियों ने सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा किया, उभरती प्रौद्योगिकियों का पता लगाया और ज़िला-स्तरीय ई-गवर्नेंस पहलों को मज़बूत करने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया।

क्षमता-निर्माण और सहयोगात्मक समस्या-समाधान पर ध्यान केंद्रित करके, इस आयोजन ने ज़िला केंद्रों को सशक्त बनाने और तेलंगाना के लिए एक मज़बूत डिजिटल शासन ढाँचे को आकार देने में की महत्वपूर्ण भूमिका को दोहराया। सत्रों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जमीनी स्तर पर प्रभावी डिजिटल हस्तक्षेप किस प्रकार पूरे राज्य में पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक सेवा वितरण को बढ़ा सकते हैं।

डीआईओ/ डीआईए मुलाकात 2025 ने न केवल ज़िला-स्तरीय प्राथमिकताओं को राज्य और राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन लक्ष्यों के साथ संरेखित करने का अवसर प्रदान किया, बल्कि नवाचार-संचालित शासन की भावना को भी रेखांकित किया जो एनआईसी के मिशन का मार्गदर्शन करती रहती है।

– रेयनिल जॉन, तेलंगाना

आंध्र प्रदेश के माननीय राज्यपाल ने राज्य सूचना आयोग की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया

आंध्र प्रदेश के माननीय राज्यपाल ने 8 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश सूचना आयोग की नई वेबसाइट का उद्घाटन किया, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित किया गया है और यह https://sic.ap.gov.in पर उपलब्ध है।

इस नए रूप में लॉन्च किए गए पोर्टल में आंध्र प्रदेश सूचना आयोग की सुनवाई की सीधा प्रसारण की सुविधा शुरू की गई है, जो शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त, वेबसाइट सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का समर्थन करती है, पहुँच में सुधार करती है और नागरिकों को उनके सूचना का अधिकार (आरटीआई) का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सशक्त बनाती है।

एक आधुनिक, उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस के साथ, यह पोर्टल अधिक सार्वजनिक पहुँच, कुशल शिकायत निवारण और बेहतर नागरिक जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सेवाओं को एकीकृत करता है। यह लॉन्च खुले शासन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने की आंध्र प्रदेश की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है और राज्य भर में ई-गवर्नेंस पहलों को मज़बूत करने में एनआईसी की भूमिका को रेखांकित करता है।

एनआईसी द्वारा विकसित आंध्र प्रदेश सूचना आयोग की नई वेबसाइट

– विनय सोवपति, आंध्र प्रदेश

भुवनेश्वर में "एआई के माध्यम से शासन को सशक्त बनाना" पर तकनीकी बूट कैंप का उद्घाटन

एआई के माध्यम से शासन को सशक्त बनाना" विषय पर एक टेक-बूट कैंप का उद्घाटन श्रीमती अनु गर्ग, आईएएस, विकास आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना एवं अभिसरण और जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा किया गया

ओडिशा सरकार के विकास आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना एवं अभिसरण और जल संसाधन विभाग की श्रीमती अनु गर्ग, आईएएस. ने 8 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में "एआई के माध्यम से शासन को सशक्त बनाना" विषय पर एक तकनीकी बूट कैंप का उद्घाटन किया।

यह आयोजन शासन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अवसर पर, एनआईसी द्वारा विकसित एआई-संचालित परियोजनाओं को उजागर करने वाली एक विवरणिका जारी की गई, जिसमें सार्वजनिक सेवा वितरण, डेटा-आधारित निर्णय लेने और नागरिक जुड़ाव में एआई के अभिनव अनुप्रयोगों को प्रदर्शित किया गया।

कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, भुवनेश्वर में नए नवीनीकृत एनआईसी प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया गया, जिससे निरंतर सीखने और डिजिटल क्षमता-निर्माण का समर्थन करने के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा का निर्माण हुआ। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों के 100 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक विशेष एआई कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य नीति निर्माताओं और प्रशासकों को शासन में पारदर्शिता, दक्षता और सेवा वितरण में सुधार के लिए एआई की क्षमता के बारे में जागरूक करना था।

यह तकनीकी बूट कैंप ओडिशा और पूरे भारत में अगली पीढ़ी के डिजिटल परिवर्तन को चलाने की एनआईसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, यह सुनिश्चित करता है कि एआई जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग समावेशी और नागरिक-केंद्रित शासन के लिए किया जाए।

– जयंता कुमार मिश्रा, ओडिशा

क्षीरश्री को केरल राज्य ई-गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र केरल द्वारा विकसित 'क्षीरश्री' एप्लिकेशन को केरल राज्य ई-गवर्नेंस पुरस्कार (2021-22 और 2022-23) में ई-नागरिक सेवा वितरण श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

यह पुरस्कार तिरुवनंतपुरम में आयोजित समापन समारोह में केरल के माननीय मुख्यमंत्री, श्री पिनाराई विजयन द्वारा प्रदान किया गया। यह सम्मान प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारंपरिक क्षेत्रों को बदलने वाले नागरिक-केंद्रित डिजिटल समाधानों को अपनाकर 'डिजिटल केरल' को मज़बूत करने की राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

'क्षीरश्री' प्लेटफॉर्म केरल में डेयरी क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए डिज़ाइन किया गया एक व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है। यह दूध की खरीद, पारदर्शी भुगतान वितरण, सहकारी संचालन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और वास्तविक समय की निगरानी जैसी प्रक्रियाओं के एंड-टू-एंड प्रबंधन (शुरुआत से अंत तक प्रबंधन) को सुगम बनाता है। किसानों और हितधारकों के लिए सेवाओं को डिजिटाइज़ करके, यह प्लेटफॉर्म दक्षता, जवाबदेही और पहुँच सुनिश्चित करता है, जिससे राज्य भर के हजारों डेयरी किसानों को सीधा लाभ मिलता है। 'क्षीरश्री' को डिजिटल सेवा वितरण के एक मॉडल के रूप में मान्यता मिलना, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक-प्रथम शासन में केरल की अग्रणी स्थिति को और मज़बूत करता है।

मेरी पंचायत ऐप ने जीता डब्ल्यू.एस.आई.एस. पुरस्कार 2025 चैंपियन अवार्ड

मेरी पंचायत मोबाइल ऐप, जिसे पंचायती राज मंत्रालय और एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है, को जिनेवा में आयोजित डब्ल्यू.एस.आई.एस. +20 हाई-लेवल इवेंट में सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधता तथा स्थानीय कंटेंट श्रेणी के अंतर्गत डब्ल्यूएसआईएस प्राइसस 2025 चैंपियन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में माननीय पंचायती राज केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह को औपचारिक रूप से प्रदान किया गया, जबकि एनआईसी की वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्रीमती सुनीता जैन ने जिनेवा में भारत की ओर से यह सम्मान ग्रहण किया।

ग्रामीण स्तर पर डिजिटल सुशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विकसित यह ऐप देशभर की 2.65 लाख ग्राम पंचायतों के नागरिकों को बहुभाषी सुविधा प्रदान करता है, जिसमें बजट, विकास योजनाएँ, परियोजना प्रगति, अवसंरचना विवरण, शिकायत निवारण तथा मौसम संबंधी जानकारी शामिल है। परियोजनाओं का प्रस्ताव देने, कार्यों की समीक्षा करने और ग्राम सभा के निर्णयों तक पहुँच जैसी सुविधाओं के साथ यह ऐप पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। यह प्लेटफ़ॉर्म सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सूचना अंतराल को पाटने में मदद करता है।

यह सम्मान समावेशी, नागरिक-केंद्रित डिजिटल परिवर्तन में भारत के नेतृत्व को उजागर करती है, तथा यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है कि शासन में ग्रामीण आवाज़ सुनी जाए।

एनआईसी के सर्विसप्लस और यू-डाइस प्लस प्लेटफॉर्म को 'आधार संवाद 2025' में सम्मानित किया गया

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित दो प्रमुख डिजिटल शासन प्लेटफॉर्म—सर्विसप्लस और यू-डाइस+ (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस)—को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) द्वारा हैदराबाद में आयोजित 'आधार संवाद 2025' में तकनीकी श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पहचान मिली है।

सर्विसप्लस फ्रेमवर्क को एकीकृत, नागरिक-केंद्रित वितरण मॉडल के माध्यम से सरकारी सेवाओं की दक्षता और पहुँच बढ़ाने में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस प्लेटफॉर्म ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभागों को नागरिकों को निर्बाध, पारदर्शी और डिजिटल-प्रथम सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाया है, जिससे भारत में ई-गवर्नेंस की नींव मज़बूत हुई है।

व्यापक स्कूल शिक्षा डेटा प्रबंधन के लिए विकसित यू-डाइस+ प्लेटफॉर्म को, छात्रों के आधार-आधारित अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को संभव बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए 'अभिज्ञान प्रमाण पत्र' से सम्मानित किया गया। शिक्षा रिकॉर्ड की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करके,

यू-डाइस+ नीति निर्माताओं और प्रशासकों को वास्तविक समय की सटीक जानकारी प्रदान करता है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।

'आधार संवाद 2025' में यह दोहरा सम्मान शिक्षा, शासन और पहचान प्रबंधन में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने वाले स्केलेबल, अभिनव और नागरिक-उन्मुख डिजिटल समाधान बनाने में एनआईसी के नेतृत्व को रेखांकित करता है। सर्विसप्लस और यू-डाइस+ मिलकर सार्वजनिक सेवा वितरण को मज़बूत करने और पारदर्शी, जवाबदेह शासन सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका को दर्शाते हैं।